वर्ष: 5 अंक: 8 अगस्त, 2025 मूल्य: 60 रु. पृष्ठ : 44 RNI No. RAJHIN/2020/11458

राजस्थान टुडे

राजनीतिक धोखा vs लोकतांत्रिक निष्ठा

4

मानसून सत्र में 'इस्तीफा बम'

5

सिर्फ हंगामा ही मकसद है कांग्रेस का?

7

राजस्थान ग्रामीण बैंक

(सरकार के स्वामित्वाधीन अनुसूचित बैंक)

“पढ़ो बिना रुकावट – हम हैं आपके साथ”

ब्याज दर - 7.60%★

कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं★|अधिकतम ऋण ₹1.5 करोड़ तक का★

0291-2593100 | LEADS@RMGB.IN

www.rajgb.in

नियम एवं शर्तें लागू
★

राजस्थान टुडे

आपकी पत्रिका, आपकी बात
www.rajasthantoday.online

RNI No. RAJHIN/2020/11458
वर्ष 5, अंक 8, अगस्त, 2025
(प्रत्येक माह 15 तारीख को प्रकाशित)

प्रधान सम्पादक
दिनेश रामावत

राजनीतिक सम्पादक
सुरेश व्यास

सम्पादक
अजय अस्थाना

प्रबंध सम्पादक
राकेश गांधी

सह सम्पादक
बलवंत राज मेहता

रेखाचित्र
राजेंद्र यादव

संपादकीय कार्यालय
बी-4, फोर्थ फ्लोर, एम.आर. हाईट्स
महावीर कॉलोनी, भास्कर सर्किल,
रातानाड़ा, जोधपुर - 342011
व्हाट्सएप नंबर - 8107800000
ई-मेल - rajasthantoday@gmail.com

सभी विवादों का निपटारा जोधपुर की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा।

राजस्थान टुडे में प्रकाशित आलेख लेखकों की राय है। इसे राजस्थान टुडे की राय नहीं समझा जाए। राजस्थान टुडे के मुद्रक, प्रकाशक और सम्पादक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। हमारी भावना किसी वर्ग या व्यक्ति को आहत करना नहीं है। विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व राजस्थान टुडे का नहीं होगा।

• मारवाड़ मीडिया प्लस के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक पूनम अस्थाना द्वारा बी-4, फोर्थ फ्लोर, महावीर कॉलोनी, रातानाड़ा, जोधपुर-342011 से प्रकाशित और डी.बी. कॉर्प लिमिटेड, 01 पार्श्वनाथ इंडस्ट्रीयल एरिया, रिलायंस वेयर हाउस के पास, मोगरा कलां, जोधपुर-342802 में मुद्रित, संपादक : अजय अस्थाना।

अंदर विशेष

5 राजनीतिक हलचल
मानसून सत्र में इस्तीफा बम

7 राजनीति
सिर्फ हंगामा ही मकसद है कांग्रेस का?

नियमित कालम

12 बोल हरि बोल
19 बात बेलगाम
39 अभिव्यक्ति
42 ग्रहों की चाल

40 चौंकाती है 'सैय्यारा' की सफलता

32 प्रगति का असली पैमाना...
33 AI से धारदार हो रहे जासूसी औजार
35 हरमन-स्मृति की छत्रछाया में युवा शक्ति ने दिखाया...
37 सुखी जीवन का सूत्र- कम तनाव, अधिक संतुलन

04 अपनी बात...
राजनीतिक धोखा v/s लोकतांत्रिक निष्ठा

09 राजनीति...
भाजपा में वर्चस्व की लड़ाई, कांग्रेस में...

13 बिहार चुनाव...
बिहार में हंगामा क्यों है बरपा..?

16 हादसा...
जर्जर स्कूल भवनों से बच्चों की जान का खतरा

20 साइंस...
सिर्फ कोडिंग नहीं, आगे बढ़ने के लिए...

22 साक्षात्कार...
बदलता समाज और मानसिक स्वास्थ्य...

24 भाषाई इतिहास...
माटी, संगीत व संवाद में सुनाई...

25 स्टार्टअप क्रांति...
सपनों का कारोबार, किसकी किमत पर?

राजनीतिक धोखा Vs लोकतांत्रिक निष्ठा

उपराष्ट्रपति पद पर बैठा एक संवैधानिक चेहरा जब सत्ता पक्ष की रणनीति को दरकिनार कर विपक्ष के प्रस्तावों को स्वीकार करता है, तो सवाल उठते हैं— क्या यह लोकतांत्रिक निष्ठा का परिचायक था या राजनीतिक भरोसे का धोखा? जस्टिस वर्मा और जस्टिस शेखर यादव से जुड़े दो महाभियोग प्रस्तावों को लेकर जगदीप धनखड़ की भूमिका ने भाजपा की सोच, संगठन और 'आयातित नेतृत्व' नीति पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या यह अकेली घटना थी या वैचारिक प्रतिबद्धता बनाम अवसरवाद का बड़ा संकेत?

दिनेश रामावत
प्रधान सम्पादक

भारतीय लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति का पद गरिमा और मर्यादा का प्रतीक है। वह राज्यसभा का सभापति होता है— उच्च सदन की कार्यवाही का संचालन करने वाला, और संवैधानिक संतुलन का रक्षक। पर जब यही व्यक्ति अचानक सत्ता पक्ष की रणनीति को तोड़कर विपक्ष की पहल को वैधता देने लगे, तब यह मात्र संवैधानिक विवेक नहीं रह जाता, बल्कि एक राजनीतिक संकेत बन जाता है।

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के हालिया इस्तीफे से ठीक पहले जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को न केवल स्तब्ध किया, बल्कि यह अहसास भी करा दिया कि निष्ठा और वैचारिक गहराई की अनदेखी कभी- कभी बहुत महंगी पड़ सकती है।

केंद्र सरकार की योजना थी कि लोकसभा के माध्यम से जस्टिस वर्मा को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके पीछे मंशा यह थी कि सरकार न्यायपालिका में पारदर्शिता और जवाबदेही का संदेश दे सके। लेकिन इस पूरी रणनीति को उस समय गहरा धक्का लगा, जब राज्यसभा में विपक्ष ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया, और धनखड़ साहब ने उसे बिना सत्ता पक्ष को सूचित किए स्वीकार कर लिया। इस प्रस्ताव पर विपक्ष के 63 सांसदों के हस्ताक्षर थे। इसे स्वीकार कर उपराष्ट्रपति ने विपक्ष को संसद की प्रक्रिया में वैध भागीदार बना दिया, जबकि केंद्र सरकार इस पूरी प्रक्रिया को लोकसभा से नियंत्रित करना चाहती थी। यह कदम भाजपा के लिए रणनीतिक असहजता का कारण बन गया।

यह सिर्फ जस्टिस वर्मा तक सीमित नहीं था। विपक्ष प्रयागराज हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस

शेखर यादव को हटाने का प्रस्ताव भी ला रहा था, जिन्होंने विहिप के एक कार्यक्रम में मंच से कहा था, "यह देश कठमुल्लों से नहीं चलेगा।" यह वक्तव्य संघ की विचारधारा के अनुरूप था और पार्टी उन्हें संरक्षण देना चाहती थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि धनखड़ साहब इस प्रस्ताव को भी स्वीकारने को तैयार थे, और केंद्र सरकार को इसकी भनक तक नहीं थी। यह स्थिति भाजपा और संघ के लिए अत्यंत अपमानजनक बन सकती थी- विपक्ष, भाजपा के बनाए उपराष्ट्रपति के सहयोग से, एक 'हिंदुत्व समर्थक' न्यायाधीश को हटा देता!

धनखड़ साहब के व्यवहार से विपक्ष को लगा कि अब राज्यसभा में सभापति उनके 'पक्ष' में हैं। यही कारण था कि विपक्ष ने उच्च सदन में पहले से कहीं ज़्यादा आक्रामक रुख अपनाया। राज्यसभा में केंद्र की योजनाएं लगातार ठप होती दिखीं, और सत्ता पक्ष इस गतिरोध का समाधान नहीं निकाल पा रहा था।

सत्ता पक्ष को जैसे ही यह आभास हुआ कि उपराष्ट्रपति अब राजनीतिक रूप से 'स्वतंत्र' सोचने लगे हैं, तो राजनाथ सिंह के कार्यालय से एनडीए के सांसदों को बुलाया गया और उनसे कोरे कागज पर हस्ताक्षर लिए गए। यह अपूर्व कदम था— अपने ही उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी।

धनखड़ साहब को रात 8 बजे के बाद स्पष्ट रूप से संदेश दिया गया— "अब फैसला आपका है।" और उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया।

जब वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी, या गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेताओं ने पद छोड़ा, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावनात्मक भाषण दिए थे। लेकिन धनखड़ साहब के इस्तीफे पर पीएम मोदी ने केवल एक औपचारिक ट्वीट किया :

"उन्हें अनेक जिम्मेदारियों में सेवा का अवसर मिला है, वे शीघ्र स्वस्थ हों।"

न सम्मान, न श्रद्धा, न आभार। भाजपा के किसी वरिष्ठ नेता ने भी कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी। यह मौन अपने आप में एक तीखा राजनीतिक वक्तव्य था कि पार्टी ने राहत की सांस ली है।

विडंबना देखिए, जो विपक्ष कल तक धनखड़ को "लोकतंत्र का भक्षक", "संघी कठपुतली" जैसे विशेषण दे रहा था, वही आज उन्हें "संविधान का प्रहरी", "न्यायिक स्वतंत्रता का रक्षक" कहकर सराह रहा है।

यही राजनीति की शाश्वत वास्तविकता है— विरोध केवल सुविधा तक सीमित होता है, और प्रशंसा भी अवसर पर टिकी होती है।

भाजपा के लिए सबक : जगदीप धनखड़ भाजपा की परम्परागत नर्सरी— आरएसएस से निकले नेता नहीं थे। वे एक दक्ष अधिवक्ता, क्षेत्रीय नेता और पूर्व राज्यपाल जरूर रहे, लेकिन उनकी वैचारिक जड़ें भाजपा की नहीं थीं। भाजपा ने बीते वर्षों में जिन नेताओं को अन्य दलों से आयात किया है, उनमें से अधिकतर या तो निष्क्रिय निकले हैं या अवसरवादी।

धनखड़ साहब का इस्तीफ़ा केवल एक व्यक्ति का त्याग नहीं था— यह भाजपा की वैचारिक रणनीति की एक कमीज़ोर कड़ी का टूटना था। वह कड़ी, जिसे सत्ता ने सुदृढ़ समझा, वही विश्वासघात की सबसे कमज़ोर नस बन गई।

भाजपा को अब यह गहराई से समझना होगा कि सांस्थानिक पदों पर निष्ठावान और वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध नेता ही संकट की घड़ी में पार्टी की रीढ़ बनते हैं— आयातित नेता नहीं।

क्योंकि राजनीति भले ही बदलती रहती हो, पर निष्ठा, नेतृत्व की स्थायी पूंजी होती है।

उपराष्ट्रपति धनखड़ के त्याग पत्र पर सिर्फ अटकलें ही बनी खबर

मानसून सत्र में 'इस्तीफा बम'

इसमें कोई दो राय नहीं है कि धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से कार्यकाल पूरा होने से लगभग दो साल पहले इस्तीफा देना देश को लोकतांत्रिक इतिहास की बड़ी और अहम घटना है। यह घटना तेजी से बदल रहे राजनीतिक दृष्टिकोण और सियासी जमातों के बीच आपसी विश्वास में लगातार आ रही कमी से उत्पन्न होने वाली खतरनाक स्थितियों की ओर इशारा करती है।

सुरेश व्यास ✍ वरिष्ठ पत्रकार
एवं राजनीतिक विश्लेषक

दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में यह पहली बार हुआ है जब किसी उपराष्ट्रपति ने कार्यकाल पूरा होने से पहले स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों से इस्तीफा दिया। हालांकि पूर्व में भी कई उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन तब उन्हें राष्ट्रपति का पदभार सम्भालना था। ऐसे उपराष्ट्रपति वीवी गिरी से लेकर शंकरदयाल शर्मा तक रहे हैं, लेकिन किसी ने बीच में ऐसे पद नहीं छोड़ा, जैसे निवर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने त्याग-पत्र दिया है।

धनखड़ ने संसद के 21 जुलाई को शुरू हुए मानसून सत्र के पहले दिन ही इस्तीफा बम फोड़ दिया, लेकिन अभी तक यह खुलासा नहीं हो पाया कि इस्तीफे के पीछे असली कारण क्या है। मैनस्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर जो कुछ भी सामने आया है, वह सिर्फ अटकलों पर आधारित है। कयास लगाए जा रहे हैं और सिर्फ सम्भावनाएं जताई जा रही है। इस बारे में न तो सरकार ने कुछ कहा है और न ही धनखड़ अभी तक सामने आए हैं। उनका आखिरी ट्वीट भी उनका इस्तीफा ही था, जो उन्होंने 21 जुलाई की रात 9 बजकर 35 मिनट पर सोशल मीडिया साइट एक्स (पूर्व में ट्वीटर) पर पोस्ट किया था।

इसके बाद कई तरह की खबरें फैली कि धनखड़ को तुरंत उपराष्ट्रपति आवास खाली करने को कहा गया है और उनके सोशल मीडिया से जुड़े स्टाफ को हटा दिया गया है। हालांकि सरकार ने इसका पीआईबी फैक्ट चैक के सहारे खण्डन भी करवा दिया, लेकिन अटकलें हैं कि रूक ही नहीं रही। यहां तक बात होने लगी कि धनखड़ और उनकी पत्नी के मोबाइल फोन स्विच-ऑफ करवा दिए गए। खाना भी बाहर से आ रहा है, यानि एक तरह से धनखड़ के हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति बताई जा रही है। हालांकि सभी बातें बिना सिर पैर के हो रही है और दोनों ओर से चुप्पी इन्हें अलग ही हवा दे रही है। दस दिन बाद भी स्थिति स्पष्ट न हो तो ऐसी बातों को और अधिक बल मिलने लगता है और अभी ऐसा ही हो रहा है।

मानसून सत्र के पहले दिन उन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही न सिर्फ सदन के सदस्य रहे दिवंगतों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जरूरी दस्तावेज सदन पटल पर रखवाए और चार नए सदस्यों को शपथ दिलाई, बल्कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे पर विपक्ष की ओर से रखे गए काम रोको प्रस्तावों को नामंजूर भी किया। इसी दौरान नामंजूरी पर आपत्ति दर्ज करवा रहे विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को उन्होंने बोलने का मौका दिया और जवाब के लिए नेता सदन व स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भी जवाब देने को कहा। इस दौरान हंगामे के बीच एक ऐसी घटना हुई, जिसमें नड्डा विपक्ष की ओर मुखातिब होकर यह कहते हुए सुने-देखे गए कि 'नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, ओनली गो इन रिकॉर्ड वाट आई एम सेइंग...' यानी सदन की कार्रवाई में कुछ नहीं जाएगा, जो वे बोल रहे हैं वो ही रिकॉर्ड होगा।

यूं देखा जाए तो नड्डा का ये बयान बड़ी घटना थी, जिसने एक बार तो सदन के आसन पर बैठे धनखड़ को भी असहज किया होगा, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं होने दिया। यदि धनखड़ का इस्तीफा नहीं आता तो ये बयान निश्चित रूप से बड़ा मुद्दा बनता। कई लोग इसी बयान को धनखड़ के इस्तीफे के पीछे का एक कारण भी मानते हैं, लेकिन इसके बाद हुए घटनाक्रम की कड़ियां जुड़ने से अटकलों को इतना बल मिला कि सच्चाई अभी तक सामने नहीं आई कि आखिर हुआ क्या, जिसकी वजह से धनखड़ ने मैदान छोड़ दिया। सरकार के तुरंत इस्तीफे का नोटिफिकेशन जारी करते ही चुनाव आयोग ने भी नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी शुरू कर दी। यानी किसी ने धनखड़ को मनाने की कोशिश भी नहीं की। इससे इन अटकलों को बल मिला कि धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं, उनसे इस्तीफा लिया गया है। अब सवाल यही है कि इस्तीफा मांगने की नौबत क्यों आई?

कई बार असहज हुई सरकार

जानकार बताते हैं कि धनखड़ के बयानों ने कई बार सरकार के लिए असहज स्थिति उत्पन्न की थी। खासतौर पर विपक्षी नेताओं को निशाने पर लिए गए उनके राजनीतिक बयान और न्यायपालिका को 'सुपर संसद' कह देने जैसे वक्तव्य जैसे ये संकेत दे रहे थे कि धनखड़ ऐसा सरकार के इशारे पर बोल रहे हैं। इस्तीफे से कुछ घंटे पहले भी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर उन्होंने तल्खी दिखाई।

सदन में सकपका गए मंत्री

दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहते जस्टिस यशवंत वर्मा के घर जली हुई हालत में मिली लाखों की नगदी के मुद्दे पर पहले से हमलावर रहे धनखड़ ने राज्यसभा में विपक्ष की ओर से उन्हें हटाने के लिए दिए गए महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा के सभापति के तौर पर उन्होंने मंजूरी दे दी। ऐसे में अपनी ओर से पक्ष-विपक्ष का प्रस्ताव लोकसभा में पेश करने की तैयारी कर रही सरकार को जोर का झटका लगा। धनखड़ जब राज्यसभा में विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव मंजूर कर रहे थे, उस वक्त सदन में मौजूद विधि मंत्री अर्जुनराम मेघवाल असहज नजर आए। जब धनखड़ ने उनकी ओर मुखातिब होकर पूछा कि क्या लोकसभा में भी ऐसा प्रस्ताव आया है, तो उन्होंने सकपकाते हुए ही जवाब दिया कि हां, ऐसा नोटिस लोकसभा स्पीकर को सौंपा गया है।

तो यूं लिखी गई पटकथा

▪ वरिष्ठ पत्रकार के.पी. मलिक कहते हैं कि इसी घटना ने शायद धनखड़ के इस्तीफे की पटकथा लिख दी और सदन स्थगित होने के बाद जब राज्यसभा के चेयरमैन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की दोपहर में स्थगित हुई बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे तो सदन के नेता नड्डा, संसदीय कार्यमंत्री किरण रिजिजू और संसदीय कार्यमंत्री अर्जुन मेघवाल को नदारद पाकर चौंक गए। जब उन्हें भाजपा के ही एक बीएसी सदस्य ने बताया कि मंत्री किसी और बैठक में व्यस्त हैं तो धनखड़ उखड़ गए और बैठक फिर अगले दिन के लिए टाल दी।

यह भी खूब रही चर्चा

यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन संसद के एक दूसरे गलियारे में अचानक हुई हलचल ने आग में घी का काम किया। कहा जाता है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ राज्यसभा में विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव मंजूर होने की सूचना ने सरकार को सहमा दिया। प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। इसमें जवाबी कार्रवाई का कोई प्लान बना। इसके तहत राज्यसभा के भाजपा व एनडीए सदस्यों को दस- दस के समूह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के चैम्बर में बुला कर कथित रूप से खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए और इस मुद्दे पर कठोर गोपनीयता बरतने की सलाह दी गई। इसे धनखड़ को हटाने की कोशिशों के रूप में देखा गया। इसके बाद यह भी अटकल सामने आई कि शाम करीब सात बजे प्रधानमंत्री के दूत के रूप में किसी वरिष्ठ नेता ने धनखड़ को फोन करके कथित रूप से कहा कि 'अब बहुत हो गया है...।' इस दौरान हुई बातचीत के बाद धनखड़ ने इस्तीफा देने का मन बनाया और अचानक राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर इस्तीफा बम फोड़ दिया।

इस्तीफा दिया या लिया...

इस्तीफे के पंद्रह घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से सोशल मीडिया साइट पर प्रतिक्रिया दी, उससे यह तो साफ संकेत मिल गया कि सरकार उनसे बेहद खफा थी। मोदी की यह प्रतिक्रिया भी उनका इस्तीफा नोटिफाई होने यानी आम भाषा में त्यागपत्र मंजूर होने के बाद आई। जिस तेजी से इस्तीफा मंजूर हुआ, उससे भी यह बात सही होती दिखी कि इस्तीफा लिया गया है धनखड़ से।

विपक्ष से बढ़ता मेलजोल

संसद के मानसून सत्र से पहले विपक्ष की आंख की किरकिरी बने धनखड़ के इस्तीफे का एक कारण उनकी इस्तीफे से पहले विपक्षी नेताओं के साथ बढ़ती नजदीकियों को भी माना जा रहा है। ऐसा कांग्रेस की ओर से धनखड़ के इस्तीफे के पीछे 'दाल में कुछ काला' वाला बयान या कांग्रेसाध्यक्ष खरगे व आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात अथवा उनका खरगे को नामंजूर काम रोको प्रस्ताव पर बोलने का मौका देने की वजह से ही नहीं सोचा जा रहा। देश के एक बड़े मीडिया हाउस के लिए राजनीतिक रिपोर्टिंग करने वाले एक पत्रकार ने तो दावा भी कर दिया कि धनखड़ मोदी सरकार को समर्थन दे रहे आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू से सम्पर्क में थे और उन्हें मोदी सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए कथित रूप से उकसा भी रहे थे। यह बात सरकार तक पहुंच गई और इसके साथ ही मोदी सरकार ने धनखड़ से पीछा छुड़ाने पर विचार करना शुरू कर दिया था। फिर जस्टिस वर्मा के मामले में धनखड़ के फैसले ने सरकार को यह मौका दे दिया कि वे धनखड़ को रास्ते से हटा सकें।

सरकार के लिए सबक... धनखड़ के इस्तीफे ने न सिर्फ मोदी सरकार को एक सबक दिया है, बल्कि उसके सामने चुनौती भी खड़ी की है। मोदी को अब दो साल के लिए नया उपराष्ट्रपति चुनने के लिए सोच समझ कर ही कदम बढ़ाने पड़ेंगे। उनके लिए ऐसे किसी व्यक्ति को इस पद पर लाना बड़ी चुनौती है, जो भाजपा या दक्षिणपंथी विचारधारा से परिचित ही नहीं, उसके सिद्धांतों से भी बंधा हुआ हो। वैसे भी मोदी की चौंकाने वाली स्टाइल के चलते भी यह चुनौती कम नहीं है कि किसे इस संवैधानिक पद पर लाया जाए, जो जरूरत पड़ने पर सरकार का संकटमोचक भी बन सके। सियासी पंडितों की राय में इसलिए ही जो नाम सामने आए हैं, उनमें से सिवाय राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के अलावा कोई ज्यादा विश्वसनीय नहीं लग रहा।

चुनाव की समय सीमा नहीं... धनखड़ के मानसून सत्र के पहले ही दिन इस्तीफे से हालांकि संवैधानिक संकट जैसी स्थिति नहीं बनी। कारण कि उपराष्ट्रपति का मुख्य काम राज्यसभा के सभापति के रूप में ही परिलक्षित होता है और राज्यसभा में उपसभापति मौजूद हैं। उपराष्ट्रपति के दो सचिवालयों में राज्यसभा सचिवालय ही काफी अहम होता है। ऐसे में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उपसभापति ने तुरंत काम सम्भाल लिया। हालांकि उपराष्ट्रपति का पद खाली घोषित हो चुका है, लेकिन चुनाव करवाने के लिए संविधान में कोई समय सीमा तय नहीं है। नियमावली में आकस्मिक ढंग से यह पद खाली हो जाने के बाद पद भरने के लिए चुनाव की समय सीमा के स्थान पर सिर्फ 'जितना जल्दी सम्भव हो' ही लिखा है। ऐसे में निर्वाचन आयोग पर ही निर्भर है कि वह कितना जल्दी चुनाव करवाता है। आयोग ने धनखड़ के इस्तीफे से खाली हुआ पद भरने की प्रक्रिया तो शुरू कर दी है, लेकिन अभी अधिसूचना जारी नहीं की है।

कहां चूक रहा विपक्ष : मोदी ही बने कांग्रेस के एकमात्र निशाने, 11 साल की चूक और लगातार पतन की कहानी

सिर्फ हंगामा ही मकसद है कांग्रेस का?

राजेश कसेरा ✍ वरिष्ठ
पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक

दुष्यंत कुमार ने बखूबी लिखा है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए..., मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए! लेकिन पिछले 11 साल से विपक्ष में बैठे देश के सबसे बड़े और पुराने राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सिर्फ हंगामा खड़ा करने का काम किया। न वे देश की सूरत बदल पाए और न ही आमजन के दिलों में आग जला पाए। बल्कि गलतियों पर गलतियां कर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को मजबूत करने का काम किया। इसका असर केवल केन्द्र की राजनीति पर नहीं दिखा, बल्कि ज्यादातर राज्यों में भी कांग्रेस का जनाधार उसके हाथ से फिसल गया। हाल ये हो गए कि मोदी-शाह का कांग्रेस मुक्त भारत का संकल्प धीरे-धीरे साकार होता दिख रहा है।

हर बार की तरह संसद के मानसून सत्र का पहला सप्ताह भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस ने सदन के अंदर और बाहर पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को लेकर केन्द्र सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया। लेकिन सरकार की ओर से दोनों सदनों में चर्चा के लिए समय निर्धारित होते ही गेंद फिर कांग्रेस के हाथ से निकलती दिखने लगी। देखा जाए तो बीते एक दशक में कांग्रेस का यही रवैया देखने को मिला है। संसद के सत्रों में भागीदारी निभाने से ज्यादा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने समय जाया करने का काम किया। इसका सीधा लाभ सत्तारूढ़ दल को मिला और उन्होंने जो मिशन तय किया, उसे बकायदा संसद के दरवाजे से बाहर निकालकर पूरा भी कर दिखाया। भाजपा और मोदी ने भांप लिया कि कैसे और कहां कांग्रेस और विपक्ष को उलझाकर रखना है। सत्तारूढ़ सरकार ने अपने एजेंडे के हिसाब से न केवल अपने संकल्पों को साधा, विपक्ष से भी मनचाहा करवा लिया। मोदी- शाह की जोड़ी ने सभी मोर्चों पर विपक्ष को बेनकाब करने के साथ उनको शिकस्त पर शिकस्त देने का काम भी किया।

राजनीतिक रूप से विश्लेषण करेंगे तो साफतौर पर दिख जाएगा कि बीते 11 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने राडार पर रखा। हर मुद्दे पर उनको घेरने का ही काम किया और इसे स्थायी रणनीति बनाकर अपने संगठन के नीचे तक यही संदेश दिया कि मोदी पर राजनीतिक प्रहार से केन्द्र सरकार और भाजपा संगठन दोनों कमजोर होंगे। यही कारण रहा कि कांग्रेस के शीर्ष से लेकर नीचे तक के पदाधिकारियों ने गली-कूचों की समस्याओं तक से मोदी को जोड़ना शुरू कर दिया। इसका खमियाजा लगातार झेलने के बाद भी कांग्रेस ने इससे कोई सबक नहीं लिया और चुनाव-दर-चुनाव हार का स्वाद ही चखा। जिन राज्यों में उसको सरकार बनाने का मौका भी मिला तो वहां के सियासी समीकरणों और लगातार चले आ रहे ट्रैंड के कारण मिला। नहीं तो छह दशक तक देश पर राज करने वाले दल का इतना तेजी से संतुलन तो नहीं बिगड़ता। इसे कांग्रेस के निरंतर पतन का कारण ही कहा जाएगा कि 1984 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ दो सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी आज केंद्र और 18 राज्यों में शासन कर रही है। स्वतंत्रता के बाद की भारतीय राजनीति का यह सबसे बड़ा परिवर्तन है। भाजपा उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश, राजस्थान और असम सहित 14 राज्यों में अपने दम पर सत्ता में है तो एनडीए सहयोगियों के साथ बिहार और आंध्रप्रदेश सहित चार और राज्यों में सत्तारूढ़ गठबंधन का हिस्सा हैं।

राहुल गांधी : कांग्रेस का आज, कल और भविष्य

देश से राजनीतिक जनाधार लगातार खिसकने के बावजूद कांग्रेस ने अपने संगठन और जमीनी स्तर पर कोई ठोस काम नहीं किया। पार्टी की कमान भी बीते दो दशक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राहुल गांधी के हाथ में ही रहीं। वे ही पार्टी का बीता कल, आज और आने वाला कल बनकर रह गए। पार्टी के अनुभवी रणनीतिकार को दरकिनार कर दिए गए। इसका परिणाम ये रहा कि अक्टूबर 2009 में 32 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 13 में कांग्रेस की सरकारें थीं। वहीं 3 अन्य राज्यों में नेशनल कॉन्फ्रेंस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ गठबंधन में थी। केवल छह राज्यों में भाजपा की सरकारें थीं, जबकि दो राज्यों पंजाब और बिहार में सहयोगी दलों की सरकारें थीं। पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में वामपंथी दल सत्ता में थे। इसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बावजूद कांग्रेस 9 राज्यों में सत्ता में थी। जम्मू-कश्मीर, बिहार और झारखंड में सहयोगियों की सरकारें थीं। लेकिन, 2025 तक आते-आते तस्वीर एकदम पलट गई। भाजपा ने देशभर में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर कमल खिला दिया तो कांग्रेस मात्र तीन राज्यों हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक तक सिमट कर रह गई। कांग्रेस को इस हाल पर लाने वाले राहुल गांधी ही रहे।

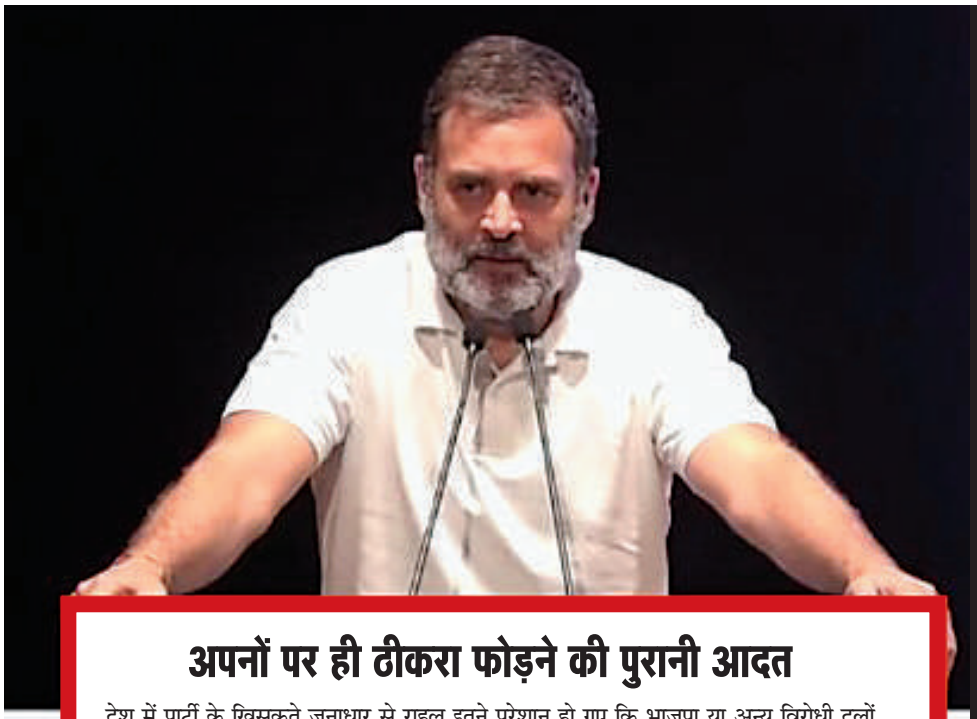

अपनों पर ही ठीकरा फोड़ने की पुरानी आदत

देश में पार्टी के खिसकते जनाधार से राहुल इतने परेशान हो गए कि भाजपा या अन्य विरोधी दलों से लड़ने के बजाय उन्होंने गुजरात में तो पार्टी के एक बड़े वर्ग को भाजपा के लिए काम करने का जिम्मेदार ठहरा दिया। लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार से जुड़े नेताओं को उम्मीद थी कि आगे सब अच्छा होगा और समर्थकों में जोश का संचार होगा। लेकिन, पांच प्रदेशों हरियाणा, झारखंड, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, दिल्ली के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर होता गया। दिल्ली में तो पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। ऐसा दिल्ली में लगातार तीसरी बार हुआ। हाल तो ये हैं कि देश के पांच प्रदेशों की विधानसभा में कांग्रेस का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं हैं। ये राज्य हैं पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, नागालैंड और सिक्किम। कांग्रेस अपने खोते जनाधार को वापस पाने के लिए कोई सकारात्मक या ठोस प्रयास नहीं कर रही। अब तो उसके सहयोगी दल भी गठबंधन के तहत सीट नहीं देना चाह रहे।

विश्लेषकों की चेतावनी अनसुनी

देश में कई राजनीतिक विश्लेषक अक्सर कांग्रेस के पतन के कारण गिनाते हैं। वे उनको आगाह भी करते हैं, लेकिन कांग्रेस, राहुल और उनको घेरे रहने वाले नेता न तो इसको समझते हैं और न ही कोई सीख लेते हैं। पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व अपनी कमी का दोष अपने दल के कार्यकर्ताओं, नेताओं तथा अन्य लोगों पर मढ़ने का अवसर ढूंढते हैं। इसे ये भी मान सकते हैं कि कांग्रेस ने अपना आकलन करना ही बंद कर दिया है, जो उसके पतन का कारण बन रही है। स्वतंत्रता के बाद से मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति की समीक्षा करने का भी प्रयास नहीं किया गया। वर्ष 2014 के चुनाव में मानमर्दन के बाद हार के कारणों की समीक्षा के लिए गठित एंटनी समिति ने अपनी पड़ताल में पाया था कि मुस्लिमों की ओर झुकाव का पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बावजूद कांग्रेस ने उससे कोई सबक नहीं लिया। आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कुछ मुद्दों पर भी उसका रवैया उसे संदिग्ध बनाता है। पार्टी देश के बदलते मानस और राजनीतिक परिदृश्य को समझ नहीं पा रही और अपना जनाधार एवं प्रासंगिकता खोती जा रही है।

आंकड़े बताते हैं कांग्रेस के गिरते ग्राफ की हकीकत

साल 1962 से 1984 के बीच कांग्रेस का देश में स्ट्राइक रेट 50 फीसदी से ज्यादा था। इन वर्षों में केवल 1977 अपवाद था। आपातकाल के बाद कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 31 फीसदी रहा और इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी। साल 1984 में कांग्रेस सबसे मजबूत स्थिति में थी, तब पार्टी को 491 में से 404 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद कांग्रेस कभी 50 फीसदी का स्ट्राइक रेट हासिल नहीं कर पाई। साल 1989 में स्ट्राइक रेट 39 फीसदी रहा। साल 1991 में यह आधे के करीब पहुंचा और स्ट्राइक रेट 48 फीसदी रहा। साल 1996 से 2004 के बीच पार्टी मुश्किल से एक तिहाई सीटें (29 फीसदी) जीत पाई। साल 2004 में कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई, तब पार्टी को 35 फीसदी सीटें मिली। साल 2009 में पार्टी का स्ट्राइक रेट 47 फीसदी तक पहुंचा था।

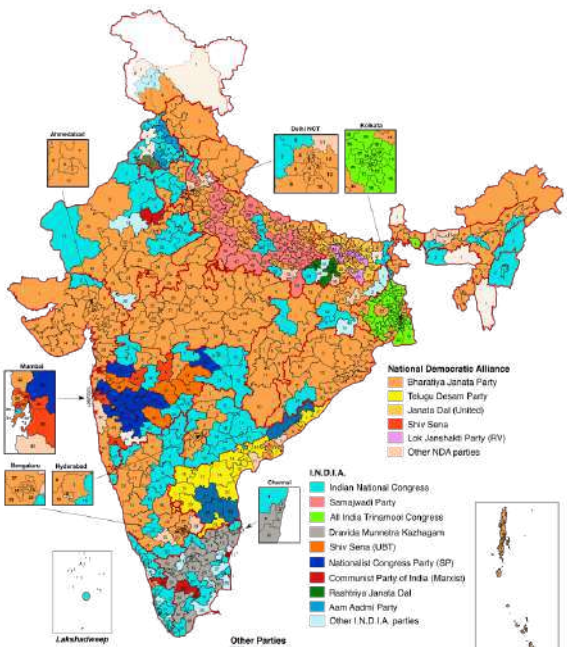

साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। उस साल कांग्रेस का स्ट्राइक रेट घटकर नौ फीसदी रह गया। कांग्रेस ने 464 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, लेकिन पार्टी को 420 सीटों (91 फीसदी) पर हार का सामना करना पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में 421 सीटों में से 369 सीटों (88 फीसदी) पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने अपना स्ट्राइक रेट सुधाकर 8 फीसदी से 28 फीसदी किया। उसने भाजपा के साथ सीधे मुकाबलों की कुल 214 में से 61 सीटें जीतीं। इस चुनाव में कांग्रेस को ऑक्सीजन मिली और उसने 53 नई सीटें जीतीं और पार्टी को 47 सीटों का लाभ मिला। 2019 में 52 सीटें जीतीं थीं जो 99 हो गईं। यानी 90.38 प्रतिशत का इजाफा किया। इसके बावजूद इस जीत के क्रम को वे बरकरार नहीं रख पाए।

राजस्थान की राजनीति में सियासी मोर्चेबंदी

भाजपा में वर्चस्व की लड़ाई, कांग्रेस में सुलह की मजबूरी

अनुराग
वरिष्ठ पत्रकार और
राजनीतिक विश्लेषक

राजस्थान की मौजूदा सियासत में भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के भीतर गहरे अंतर्विरोध उभर रहे हैं। भाजपा में वसुंधरा राजे ने सांवरलाल जाट की मूर्ति अनावरण सभा में अपनी सक्रियता और बयानों के ज़रिये पार्टी की मौजूदा सरकार पर सवाल खड़े किए। उनका इशारा सत्ता और फैसलों में आम कार्यकर्ता व वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा की ओर था। वहीं कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच वर्षों बाद मेलजोल दिखा, जो चुनावी मजबूरी के तहत ही सही, पर पार्टी में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश है। हालांकि दोनों ही दलों में भीतरखाने सत्ता संघर्ष और नेतृत्व का संकट जारी है। भाजपा में वसुंधरा समर्थकों की नाराज़गी और कांग्रेस में गुटबाज़ी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। आने वाले महीनों की राजनीतिक हलचलों से तय होगा कि अगला दांव किसके हक़ में जाएगा।

राजस्थान की राजनीति हमेशा से ही जमीनी पकड़, जातीय समीकरण और नेतृत्व की जिद पर टिकी रही है। चाहे भैरोंसिंह शेखावत का दौर रहा हो या अशोक गहलोत की सधी हुई रणनीति, या फिर वसुंधरा राजे का करिश्मा— यहां राजनीति कभी लयबद्ध नहीं रही। इस बार भी वही हाल है। भाजपा की सरकार ने अपने साठ माह के कार्यकाल में बीस माह पूरे कर लिए हैं। यानी एक चौथाई समय। इसी बीच न सिर्फ सत्तारूढ़ भाजपा में बल्कि कांग्रेस में भी सियासी हलचल ने नई करवट लेना शुरू कर दिया है। चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन सियासत का चरित्र यही है कि ये कभी ठहरती नहीं। राजनीति चुनाव के वक्त नहीं होती, चुनाव तो उस अंतिम परीक्षा की तरह है, जिसमें पूरे सत्र की राजनीति का आकलन होता है। इसके पहले कई छोटे-मोटे टेस्ट, हाफ इयरली एग्जाम और मिड टर्म असाइनमेंट चलते रहते हैं। अभी वही दौर चल रहा है।

भाजपा के सत्ता में होने के बाद भी बेचैनी

सत्तारूढ़ भाजपा में वसुंधरा राजे के इर्द-गिर्द सियासत फिर से गोलबंदी कर रही है। हाल ही में सांवरलाल जाट की मूर्ति अनावरण सभा में वसुंधरा राजे ने जिस अंदाज़ में अपनी बात रखी, उसने भाजपा के भीतर चल रहे असंतोष की तस्वीर को और साफ कर दिया। इस असंतोष को अगर समय रहते शांत नहीं किया गया तो तीन साल बाद विधानसभा चुनाव में सरकार बदलने का सिलसिला रोका न जा सकेगा। ऐसे में फिर से मुख्यमंत्री बनने की वसुंधरा राजे की इच्छा पूरी नहीं होगी। वसुंधरा अगर सक्रिय रहेगी, तभी पार्टी में उनका नाम संभावित मुख्यमंत्री में लिया जाता रहेगा। वसुंधरा राजे को इसी कारण हर कदम बहुत संभलकर उठाना पड़ रहा है। दरअसल, वो ये भी चाहती है कि पार्टी में सत्ता में आए और उनका नाम भी मुख्यमंत्री की दौड़ में बना रहे। अगर तीन साल बाद वाला मौका हाथ से निकल गया तो अगले पांच साल इंतजार करना होगा।

वसुंधरा का सियासी संदेश

भैरोंसिंह शेखावत का हवाला

वसुंधरा राजे ने सभा में भैरोंसिंह शेखावत का नाम लेकर कहा कि अगर आज शेखावत होते तो राजस्थान की राजनीति कुछ और होती। यह बयान केवल श्रद्धांजलि नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक संदेश था। दरअसल, वसुंधरा भाजपा की मौजूदा सरकार की कार्यशैली से असंतुष्ट हैं। उनका संकेत साफ था कि भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली सरकार महज मुख्यमंत्री और कुछ खास मंत्रियों तक सिमट कर रह गई है। पार्टी का आम कार्यकर्ता, छोटे नेता और ज़मीनी नेता हाशिए पर हैं। इन्हीं नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए वसुंधरा ने अगर बीड़ा उठाया है तो पार्टी हित की सोच रखने वाले नेताओं को उनका साथ देना पड़ेगा।

सरकारी कामकाज से असंतोष, ट्रांसफर-पोस्टिंग में गुटबाजी और राजनीतिक नियुक्तियों में देरी से कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ रही है। वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने की नीति भाजपा में कई छोटे-छोटे विरोध पैदा कर रही है। वसुंधरा का बयान इस नाराज़गी को आवाज देने जैसा था। अब तो काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ही कह रहे हैं कि दो साल बाद भी नहीं लग रहा कि राजस्थान में राज बदल गया है। पश्चिमी राजस्थान में तो कई कार्यकर्ता, पार्टी पदाधिकारी सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि उनकी पार्टी का राज आ गया है, इसका अहसास नहीं है। अभी भी कांग्रेस राज के लोग ही फायदा उठा रहे हैं।

क्या फिर खड़ी होगी वसुंधरा की चुनौती?

सवाल उठता है कि क्या वसुंधरा फिर से पार्टी के भीतर नेतृत्व की चुनौती देने वाली हैं? मौजूदा स्थिति को देखें तो वसुंधरा अब पार्टी के लिए खुली चुनौती बनने की स्थिति में नहीं हैं। न पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उन्हें समर्थन देगा, न परिस्थितियां इसकी इजाजत देती हैं। मगर वसुंधरा को इस बात का पूरा अहसास है कि यदि शेष बचे 40 महीनों में उनके समर्थकों को राजनीतिक नियुक्तियों और सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिली तो उनके जनाधार पर असर पड़ सकता है। ऐसे में वो अपने नेताओं को आगे करने में जुटी है। सरकार के लिए कोई समस्या बनने के बजाय वसुंधरा अपना जनाधार मजबूत कर रही है। उन्हें पता है कि पार्टी सिर्फ टिकट देती है, जीत कार्यकर्ता और जनता पर निर्भर है। वो जानती है कि वसुंधरा के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री पद से ज्यादा ज़रूरी अपने समर्थकों को राजनीतिक संरक्षण दिलाना है। ताकि अगले चुनाव तक उनके खेमे की ताकत बची रहे। अगर वे अभी चुप रहीं तो अगले विधानसभा चुनाव तक उनकी हैसियत पार्टी के भीतर और भी सीमित हो जाएगी।

भजनलाल सरकार

अब तक की उपलब्धि और असंतोष

भजनलाल शर्मा सरकार ने बीस महीनों में कई घोषणाएं कीं। जल जीवन मिशन के तहत पेयजल योजनाओं को तेज़ी से लागू करने, ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने, बजट में युवाओं के लिए भर्तियां लाने, और महिलाओं के लिए कुछ योजनाओं की शुरुआत हुई। मगर ज़मीनी कार्यकर्ताओं और भाजपा के परम्परागत वोट बैंक तक इसका असर नहीं दिखा। आरपीएससी का स्वरूप बदलने, एसआई भर्ती परीक्षा रद्द नहीं करने जैसे कई निर्णय किए हैं। शिक्षा विभाग से बड़ी भर्ती की उम्मीद अभी बनी हुई है। डॉक्टर्स की बड़ी नियुक्ति करके बेरोजगारों को सहयोग करने के साथ ही ग्रामीण चिकित्सा प्रबंध बेहतर कर सकती है।

हताश हैं आम कार्यकर्ता... अभी तक राजनीतिक नियुक्तियों में देरी, मंत्रियों के असंतोष और ब्यूरोक्रेसी के वर्चस्व से आम कार्यकर्ता हताश है। भाजपा में एक बड़ा वर्ग मानता है कि सत्ता का अहसास कार्यकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाया। नतीजा, भाजपा के जिलास्तरीय नेताओं में भी असंतोष है। यहां तक कि स्थानीय निकाय के चुनाव भी लंबित हैं। इससे स्वयं भाजपा के कार्यकर्ताओं में ही असंतोष साफ नजर आ रहा है। एक चुनाव कराने की सोच के बहाने चुनाव से बचने की कोशिश बताई जा रही है। कांग्रेस इसका प्रचार इसी तरीके से कर रही है।

छवि बेहतर, पर करीबियों का वर्चस्व खटक रहा

भजनलाल शर्मा अपनी सादगी, संगठन से जुड़ाव और साफ-सुथरी छवि के लिए जाने जाते हैं। मगर राजनीतिक संतुलन साधने में वो अपेक्षित तेजी नहीं दिखा पाए। वहीं मुख्यमंत्री और उनके करीबियों का वर्चस्व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं को खटक रहा है। कभी मोदी और कभी अमित शाह के राजस्थान में कार्यक्रम कर भजनलाल दिल्ली में अपनी छवि चमका सकते हैं, लेकिन अगले विधानसभा चुनाव में ये खर्च काम नहीं आने वाला है। वहां तो पार्टी कार्यकर्ता को ही मजबूत और संतुष्ट करना पड़ेगा।

वसुंधरा व भजन के दिल्ली दौरे से हुई हलचल... दिल्ली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हाल के दौरे को लेकर सियासी गलियारों में जमकर हलचल मची हुई हैं। वसुंधरा ने एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से करीब 20 मिनट तक मुलाकात की थी। उधर, मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी उसी दिन प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारों में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। इसे प्रदेश की सियासत को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि सीएम ने प्रदेश के विकास कार्यों और संरचनात्मक फीडबैक समेत विभिन्न विषयों के बारे में प्रधानमंत्री को अवगत करवाया हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी से मुलाकात की एक तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं।

कांग्रेस : अंदरूनी सुलह या दिखावटी मेल?

दूसरी तरफ कांग्रेस में हाल ही में जो सियासी नजदीकियां दिखी हैं, वे आने वाले समय के संकेत हैं। सचिन पायलट का अशोक गहलोत के घर जाना और गहलोत का उनके कार्यक्रम में मंच साझा करना— इन दोनों घटनाओं को यूं ही सामान्य मुलाकात नहीं माना जा सकता।

दरअसल, कांग्रेस को अब यह समझ आ चुका है कि अगर 2028 के चुनाव में सत्ता में वापसी करनी है तो आपसी गुटबाजी का त्याग करना ही पड़ेगा। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को इस हकीकत का एहसास है कि अलग-अलग चलकर कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं लौट सकती। दोनों को एक साथ मिलकर राजस्थान के हर हिस्से में आयोजन करने होंगे। पार्टी के अंदरखाने चल रही राजनीति से बचना होगा। अगर कांग्रेस को फिर से सत्ता में आना है तो इन दोनों नेताओं की भूमिका को स्पष्ट करना होगा। पार्टी आलाकमान को अब ये तय करना होगा कि वो अगला चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। कांग्रेस अब अगर टालमटोल करती रही तो यहां भी कार्यकर्ताओं में असंतोष मुखर हो जाएगा।

संतुलन बना रहा तो भाजपा के लिए चुनौती

पिछले चुनावों में कांग्रेस को जितनी सीटें मिली थीं, उनमें गहलोत के गढ़ जोधपुर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में मजबूत पकड़ थी। वहीं दौसा, अलवर, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर में पायलट खेमे का प्रभाव था। यही संतुलन ही कांग्रेस की ताकत है। दोनों तरफ साफ संदेश देना होगा कि दोनों मिलकर सत्ता को वापस लेकर आएंगे। अगर ये दोनों नेता साथ आते हैं तो भाजपा के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि गहलोत की संगठन पर मजबूत पकड़ और पायलट की युवा नेतृत्व वाली छवि— मिलकर भाजपा के परम्परागत वोट बैंक में सेंध लगा सकती है।

गहलोत की रणनीति : दिल भी रखना, दूरी भी बनाए रखना

अशोक गहलोत अपने पूरे राजनीतिक जीवन में संयमित भाषा, सधे हुए कदम और बारीक राजनीतिक चाल के लिए जाने जाते हैं। वे जानते हैं कि फिलहाल पायलट के साथ नजदीकी का संदेश देना जरूरी है। ताकि कार्यकर्ता और जनता को एकजुटता का अहसास हो। गहलोत ये भी भली-भांति समझते हैं कि पार्टी का पूरा नियंत्रण उनके हाथ में रहे। इसलिए वो पायलट को साइडलाइन करने की नीति भी नहीं छोड़ रहे। कांग्रेस में संगठन से जुड़े फैसलों में गहलोत अभी भी पूरी तरह हावी हैं।

सचिन पायलट की मजबूरी और महत्वाकांक्षा

सचिन पायलट अब तक कांग्रेस नेतृत्व से बार-बार संघर्ष कर चुके हैं। बगावत कर चुके हैं, हाईकमान से मनमाफिक पद और सत्ता की मांग कर चुके हैं। लेकिन अब सचिन को भी यह स्पष्ट हो गया है कि बिना गहलोत की छाया में, प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व हासिल कर पाना संभव नहीं। इसीलिए पिछले दिनों अपने पिता से जुड़े कार्यक्रम में वो गहलोत के साथ आए। उन्हें न्यौता देने भी गए और कार्यक्रम में उनके साथ भी रहे। सचिन पायलट अपनी राजनीतिक हैसियत बनाए रखने के लिए अब समझौते की नीति अपना रहे हैं। अगर वे अब भी बगावत करते हैं तो कांग्रेस नेतृत्व उन्हें पार्टी से बाहर कर सकता है और इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है।

प्रदेश कांग्रेस की दूसरी पंक्ति : निष्क्रिय या अवसरवादी?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंदसिंह डोटासरा लगातार बयानबाजी कर चर्चा में बने रहते हैं। वहीं टीकाराम जूली भी अपने बयानों और यात्राओं के जरिये खुद को अगली पंक्ति में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों इन दोनों नेताओं के बीच भी तालमेल कम नजर आया। दोनों ने एक दूसरे की खिलाफत भी की। डोटासरा का विधानसभा में नहीं आना भी मुद्दा बना। ऐसे में गहलोत-पायलट की तरह डोटासरा-जुली में भी समन्वय होना जरूरी है, जिसकी फिलकाल कमी नजर आ रही है। बाकी कांग्रेस नेतृत्व लगभग निष्क्रिय है। वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल, बीडी कल्ला जैसे पुराने नेता अपने क्षेत्र तक सीमित हो गए हैं। विधानसभा में भी धारीवाल की सक्रियता बेहद कम है। कांग्रेस की पूरी रणनीति गहलोत-पायलट समीकरण के इर्द-गिर्द ही सिमट गई है।

कौन किस पर भारी?

- अभी तस्वीर अधूरी है। भाजपा में वसुंधरा राजे और मुख्यमंत्री के बीच सत्ता की रस्साकशी जारी है। भाजपा के लिए चुनौती है कि कार्यकर्ता को सक्रिय और संतुष्ट कैसे रखा जाए। अगर वसुंधरा के समर्थकों को उपेक्षित रखा गया तो इसका असर भाजपा के वोट बैंक पर दिखेगा।
- वहीं कांग्रेस में गहलोत-पायलट का मेल सियासी मजबूरी है। यह सच्चा मेल है या दिखावटी, ये अगले साल तक साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि अगर कांग्रेस में गुटबाजी जारी रही तो फिर सत्ता वापसी मुश्किल होगी।
- राजस्थान की राजनीति अभी शतरंज की उस बिसात पर है, जहां हर मोहरा अपनी चाल चलने की फिराक में है। कौन वजीर बनेगा और कौन प्यादा— इसका फैसला आने वाले महीनों की राजनीतिक हलचलों से होगा।

अब मजबूरी का नाम महात्मा नहीं...ठाकरे बंधु कहिए

मानसून इस बार जल्दबाजी में हैं। अपना कोटा जल्द से जल्द पूरा करने पर मूसलाधार बरसने पर उतारू है। उधर संसद के मानसून सत्र में विपक्षी भी सवालों के नश्तर लेकर कमर कसे हुए हैं तो सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद और तैयार हैं। यह अलग बात है कि रणनीति बनाने के लिए इंडी अलायंस के दल एक जगह जुट नहीं पाए तो एकजुटता दिखाने के लिए ऑनलाइन बैठक करनी पड़ गई। कुछ भी कहिए इस बार दोनों ही मानसून जबरदस्त रहने वाले हैं...

हरीश मलिक
लेखक और व्यंग्यकार

पता नहीं शिवसेना सुप्रीमो रहे बाला साहेब ठाकरे की आत्मा अपने बच्चों के कदम से खुश होगी या खफा...., लेकिन यह फिर साबित हुआ है कि सत्ता की निगोड़ी कुर्सी चीज ही ऐसी करामाती है, जो नेताओं से जो चाहे करा सकती है। क्योंकि सारी कोशिशों के बावजूद बाला साहेब अपने जीते-जी जो ना करा सके, वो अब हो गया। यानी दो दशक के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का पुनर्मिलन! दोनों ने अलग-अलग कई दलों से दोस्ती गांठी, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात। दोनों को ही सत्ता दूर और दूर जाती नजर आ रही है। सो, अब दोनों मिलन को बेताब थे, लेकिन कोई बहाना नहीं सूझ रहा था। इनकी किस्मत से महाराष्ट्र में हिंदी का फव्वारा फूटा तो इन्हें आमची मराठी भाषा याद आ गई। जो बाला साहेब की मान-मनुहार और अस्मिता पर एक नहीं हुए, वे अब मराठी अस्मिता पर कंधे से कंधा मिलाने में लगे हैं। गुलाम भारत में एक मुहावरा बना था- मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। आजाद भारत में नेताओं की करतूतों से यह बदलकर हो गया है- मजबूरी का नाम ठाकरे बंधु!

कर्नाटक के नाटक में इस बार पुत्र-मोह की सियासत

कर्नाटक के नाम में ही नाटक शब्द समाहित है। इसलिए यहां सरकार किसी की भी हो, नाटक होते रहना आम बात है। जब कभी सियासी नाटक नहीं होता तो ऐसा लगता है कि सरकार कोपभवन में है या फिर सियासत स्वर्ग सिधार गई है! लेकिन परम्परा कायम रखते हुए इस बार तो यहां राजस्थान की टक्कर का नाटक चल रहा है। दरअसल, गहलोत-पायलट की तरह कर्नाटक में भी ढाई साल के फार्मूले को लेकर सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार नाटक-नाटक खेलने में लगे हैं। सियासी शीत युद्ध में दोनों ही वार पर वार कर रहे हैं और दोनों ही हाईकमान को यह जताने की कोशिश में हैं कि सब कुछ ठीक-ठाक है। इधर सीएम बदलने की चर्चाओं पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे बोल गए- 'हाईकमान फैसला लेगा!' अब कोई बताए कि अध्यक्ष के ऊपर भी कोई हाईकमान होता है क्या? असल में खरगे को दो बिल्लियों की लड़ाई की कहानी याद है। सियासी खींचतान में भी तीसरे का भला हो जाता है। इसलिए वो मन से चाहते हैं कि इन दोनों के बीच सियासत की यह अदावत इतनी बढ़ जाए कि उसमें से पुत्र प्रियांक खरगे को सीएम बनाने की गली निकल आए।

केजरीवाल बोले तो 'अपने मुंह मियां मिट्ठू'

नोबेल पुरस्कार की जितनी किरकिरी अब हो रही है, उतनी पहले कभी नहीं हुई। हर ऐरा-गेरा नत्थू खेरा नोबेल पर दावा ठोंक रहा है। इन्हें देख अल्फ्रेड नोबेल भी स्पेस में पुरस्कार शुरू करने को लेकर पछता रहे होंगे। पहले दुनिया के स्वयंभू दारोगाजी ने दावा ठोंका कि उनने इतनी क्रांति की है कि 4-5 बार नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। अब दिल्ली वाले अपने सर'जी ने 'अपने मुंह मियां मिठ्ठू' बनते हुए खुद के लिए ही नोबेल पुरस्कार की वकालत कर डाली है। वो दिल्ली में करारी हार के लिए नहीं, मोहल्ला क्लिनिक के लिए नोबेल पुरस्कार मांग रहे हैं। भाजपा को पता नहीं क्यों लगता है कि सर'जी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिल सकता था, अगर इसकी कैटेगरी में भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता, कुशासन और अराजकता इत्यादि भी शामिल होते। मानसिक संतुलन खोने के दावे पर कांग्रेस भी तब भाजपा से सहमत हो गई, जब सर'जी ने बिहार में एकला चलो रे का राग अलापना शुरू किया!

राजस्थान तक आ पहुंचा शशि थरूर का सुरूर

कांग्रेस की ऐतिहासिक खामियों को गिनाने के लिए अब विपक्षी नेताओं की जरूरत नहीं रही है। कांग्रेस के अपने नेता ही पार्टी हाईकमान को गलतियों का आईना दिखाने में लगे हैं। कांग्रेस हाईकमान भले ही आंखों पर पट्टी बांधकर 'दूध पीती बिल्ली' बना रहे, लेकिन एक के बाद एक नेता तो कांग्रेस की 'दादी' और 'युवराज' को निशाने पर ले ही रहे हैं। तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने काला अध्याय बताकर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी की पोल खोल दी। सीधे दिल पर चोट लगने के बावजूद कांग्रेस के अलंबरदार मन-मसोसकर रह गए और थरूर का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसका असर ये हुआ कि थरूर की बगावत सुदूर राजस्थान तक आ पहुंची है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र व्यास ने अपनी किताब में इंदिरा की इमरजेंसी को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय बताया है। व्यास ने तो राहुल गांधी के विदेशों में जाकर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने पर भी सवाल उठा दिए हैं!

चलते-चलते.. केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी।
करारी हार के बाद जब कोई साथ आने को तैयार ना हो तो ऐसा ही ऐलान करना पड़ता है...

चुनाव से पहले 'वोटबंदी' के आरोपों पर विपक्ष का हमला, अपराध और अव्यवस्था पर सरकार घिरी

बिहार में हंगामा क्यों है बरपा..?

राधा रमण
वरिष्ठ पत्रकार
एवं राजनीतिक विश्लेषक

बिहार विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन राजनीतिक हलचल चरम पर है। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) ने विपक्ष को 'वोटबंदी' जैसे आरोप लगाने का मौका दे दिया है। महागठबंधन इसे भाजपा के इशारे पर विपक्ष के वोटरों को हटाने की साजिश बता रहा है, वहीं भाजपा और एनडीए इसे पारदर्शिता का कदम कह रहे हैं। इस बीच राज्य में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बदहाल है और नीतीश सरकार चुनावी ऐलान के जरिए नुकसान की भरपाई करने में जुटी है। क्या ये मुद्दे इस बार बिहार के चुनावी समीकरण बदल देंगे?

बिहार में नई विधानसभा का गठन भले ही इस साल 22 नवम्बर से पहले होने हैं, लेकिन सियासी तापमान अभी से बढ़ा हुआ है। इसका कारण चुनाव की घोषणा के ठीक पहले चुनाव आयोग का मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कराने का फैसला है। इसे लेकर बिहार के विपक्षी दलों में भूचाल सा आ गया है। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव और राबड़ी देवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर, माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य, निर्दलीय सांसद राजेश रंजन ऊर्फ पप्पू यादव समेत कई नेताओं ने इसे नोटबंदी की तर्ज पर 'वोटबंदी' करार देते हुए बिहार के मतदाताओं की हकमारी कहा है। उनका यह भी कहना है कि राज्य के कुल 7 करोड़ 89 लाख 22 हजार 933 में से दो करोड़ 93 लाख से ज्यादा मतदाता रोजी-रोटी कमाने बिहार से बाहर रहते हैं। पुनरीक्षण के बहाने उनका मताधिकार समाप्त करने की कोशिश है। दूसरी बात यह कि फिलहाल बिहार के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए जद्दोजहद करेंगे या मतदाता पुनरीक्षण कराएंगे..? तीसरी बात, इस पुनरीक्षण में आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, राशन कार्ड, बिजली का बिल आदि को नहीं मानकर मतदाताओं पर ही नागरिकता साबित करने का दबाव है। जमीन का कागज दिखाने की मांग की जा रही है, जबकि बिहार में भूमि रिकॉर्ड का बुरा हाल है। अधिकांश जमीन के कागज पुरखों के नाम है। नाम स्थानान्तरण के लिए पूर्व में कम्प्यूटराइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन लालफीताशाही के कारण उसे अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका। विपक्ष कहता है, यदि पुनरीक्षण ही कराना था तो यह काम जनवरी में शुरू कर देना चाहिए था। अब चुनाव के समय जब वोटर वोट देने और सियासी दल सीटों के बंटवारे में लगे हुए हैं, ऐसे में मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का क्या मतलब है? उनका आरोप है कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर विपक्ष के वोट खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई है। हालांकि सुप्रीम अदालत ने संवैधानिक संस्था होने के कारण चुनाव आयोग के आदेश पर फौरी रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन एसआईआर में आधार कार्ड और वोटर आईडी को शामिल करने का सुझाव दिया है। मामले की सुनवाई आगे भी चलती रहेगी।

65 लाख नाम हटाए जाने का दावा

इस बीच, चुनाव आयोग ने 25 जुलाई को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के पहले चरण का काम पूरा कर लेने का दावा किया है। बताया जाता है की इसमें 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। यानी प्रत्येक विधानसभा सीट से औसतन 26 हजार मतदाताओं के नाम हटे हैं। ज्ञात रहे कि 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार की कुल 243 सदस्यीय विधानसभा सीटों में से 189 सीटों पर 26 हजार से कम वोटों से हार-जीत हुई थी। इनमें 99 सीटें एनडीए के खाते में और 85 सीटें महागठबंधन के खाते में गई थीं। शेष 5 सीटों पर अन्य दलों को विजय मिली थी। अब मतदाता सूचियों में सुधार का अगला चरण एक अगस्त से एक सितंबर तक चलेगा।

विपक्ष का कहना है कि चुनाव आयोग पीछे के दरवाजे से महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली विधानसभाओं के चुनाव में वोटरों की संख्या बढ़ाकर भाजपा की मदद कर चुका है। अब बिहार में भाजपा की मदद कर रहा है। उधर, अपने फैसले पर अडिग चुनाव आयोग का कहना है कि सिर्फ बिहार नहीं, बल्कि आने वाले समय में जहां कहीं चुनाव होंगे, वहां मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कराया जाएगा। इससे चिंतित पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी से मोर्चा खोल दिया है। मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण पर जहां विपक्षी नेता लामबंद हैं तो भाजपा नेता पुरजोर समर्थन कर रहे हैं।

बिहार विधानसभा के मानसून सत्र (इस विधानसभा के आख़िरी सत्र) में विपक्ष ने मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण, बिगड़ती क़ानून व्यवस्था और मंत्री जीवेश मिश्र के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा किया। जीवेश को राजस्थान की एक अदालत ने नकली दवा की आपूर्ति में दोषी करार दिया है और वह फिलहाल जमानत पर हैं। विपक्ष के हंगामें के बीच सरकार ने अनुपूरक बजट समेत कई विधेयक पारित करा लिया। 5 दिनों के आख़िरी सत्र में महज 4 घंटा 44 मिनट विधानसभा और 2 घंटा 10 मिनट विधान परिषद् की कार्यवाही चल सकी।

चुनाव से पहले अपराधियों का तांडव

इस बीच, विधानसभा चुनाव से पहले अपराधियों का तांडव सिर चढ़कर बोल रहा है। अकेले पटना जिले की बात की जाए तो पिछले 4 माह में 116 से ज्यादा हत्या की वारदातें हो चुकी हैं। पिछले दिनों भाजपा समर्थित राज्य के प्रमुख व्यापारी गोपाल खेमका की घर के सामने गोली मारकर हत्या कर दी गई तो पटना के एक नामी अस्पताल के आईसीयू रूम में घुसकर एक बड़े हिस्ट्रीशीटर की हत्या कर दी गई। राज्य में हत्या के अलावा अपहरण की वारदातें भी खूब हो रही हैं। पुलिस– प्रशासन का इकबाल समाप्त होता दिख रहा है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) कुंदन कृष्ण इसके लिए मौसम और किसानों पर दोष मढ़ते हैं। मध्य जुलाई में वह कहते हैं कि अप्रैल से जून तक किसानों के पास खेती का कोई काम नहीं होने से वह अपराध में लिप्त हो जाते हैं। हालांकि विपक्ष के दबाव और सरकार की नसीहत पर तीन दिन बाद वह अपने बयान के लिए माफी भी मांग लेते हैं। लेकिन इतना तय है कि पिछले 20 वर्षों से लालू के 'जंगलराज' की दुहाई देकर सत्ता की मलाई खाने वाले एनडीए के नेताओं को इस बार अपने 'जंगलराज' पर सफाई देने में दिक्कत आएगी।

संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा में हर साल बिहारियों का दबदबा रहता है। मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी बिहारी अव्वल रहते हैं। हालांकि पर्चा लीक में भी इनका कोई सानी नहीं है। प्रशांत किशोर के शिक्षा व्यवस्था में सुधार के वादे के बाद अब सत्ता पक्ष समेत सभी दल शिक्षा में सुधार पर जोर दे रहे हैं, लेकिन हालात इसके उलट हैं। पिछले दिनों पहली बार पटना विश्वविद्यालय के कालेजों में प्राचार्य की नियुक्ति लॉटरी के माध्यम से की गई, क्योंकि इसमें भाजपा- जदयू के बीच सहमति नहीं बन पाई थी। स्कूलों में शिक्षकों के हजारों रिक्त पदों को लेकर मुख्यमंत्री कहते हैं, अगली बार मौका मिला तो बहाली कर देंगे।

चौपट होती शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था

- स्वास्थ्य सेवाओं में पिछड़े बिहार के अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। कोरोना महामारी से भी सबक नहीं सीखा। डॉक्टरों के 6000 हजार से अधिक पद खाली हैं। ये ही हाल नर्सिंग स्टाफ का है। दो बड़े अस्पतालों पटना मेडिकल कालेज अस्पताल और नालंदा मेडिकल कालेज अस्पताल की भी हालत खराब है। दूरदराज के अस्पतालों का तो कोई पुरसाहाल नहीं है।
- सड़कों की बेहतरी के कारण 'सुशासन बाबू' के नाम से सुशोभित नीतीश कुमार के राज में पुल-पुलिया गिरने का नया रिकॉर्ड बन रहा है। उधर, जहानाबाद में अफसरों और ठेकेदारों की मिलीभगत से हरे पेड़ों के बीच सड़क बना दी गई है। विपक्ष इस बार चुनाव में इसे निश्चित रूप से मुद्दा बनाएगा। राज्य की नौकरियों में डोमिसाइल नीति बनाने की मांग भी इस बार मुद्दा बनेगा। पिछले दिनों डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे छात्रों को पुलिस ने दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। राजद ने अपने घोषणा-पत्र में डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कही है।

- उधर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले राज्य में 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 60 से अधिक उम्र के पत्रकारों की पेंशन बढ़ाकर 15 हजार करने और विधवा व वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपए करने की घोषणा की है। तीनों फैसले तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गए। विपक्ष इसको लेकर सरकार को घेर रहा है। उसका कहना है कि मुख्यमंत्री चुनाव में हार के डर से विपक्ष की चुनावी घोषणाओं को लागू कर रहे हैं। अगर उनकी नीयत सही है तो 20 वर्षों तक शासन करने के बाद मुख्यमंत्री को मुफ्त बिजली, बुजुर्ग पत्रकारों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की याद क्यों आई है?

प्रधानमंत्री के इस साल अब तक पांच दौरे

▪ बिहार में राजनीतिक दलों ने गतिविधियां बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री इस साल जनवरी से अब तक पांच बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। बीते 18 जुलाई को मोतिहारी की अपनी जनसभा में प्रधानमंत्री ने मोतिहारी को मुंबई, पटना को पुणे व गयाजी को गुरुग्राम सरीखा बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि आने वाले पांच वर्षों में नया बिहार बनाया जाएगा। उसी दिन दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) की सभा में प्रधानमंत्री ने नया बंगाल बनाने की बात कही। इससे पहले वह नया इंडिया बनाने की बात कहा करते थे। इस पर लालू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर प्रधानमंत्री से पूछा, 'बताइए ना, अगली बार जुमला सुनाने कब आइएगा।'

▪ आठ अगस्त को गृहमंत्री अमित शाह बिहार के सीतामढ़ी जाने वाले हैं। वह पुनौराधाम में 882 करोड़ से बनने वाले जानकी मंदिर का शिलान्यास करेंगे। भाजपा की कोशिश अयोध्या के राम मंदिर की तरह जानकी मंदिर को चुनावी मुद्दा बनाने की है। बिहार में हर तीसरे दिन कोई न कोई केंद्रीय मंत्री डेरा डाले रहता है। जनसम्पर्क में भाजपा सबसे आगे दिखाई देती है। विपक्ष की कौन कहे, जदयू के नेता भी भाजपा की गतिविधियों से भौंचक्के हैं।

▪ एनडीए में ऊपरी तौर पर एकता है, लेकिन भीतरी तौर पर असंतोष है। पिछले दिनों एनडीए की बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने जदयू के नेता और राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री अशोक चौधरी को सार्वजनिक रूप से फटकार दिया था, तब भी बैठक में मौजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुप रहे। लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के सुप्रीमो चिराग पासवान क़ानून व्यवस्था को लेकर कहते हैं, 'शर्म आती है की मुझे ऐसी सरकार का समर्थन करना पड़ रहा है जो अपराध रोकने में विफल है।' बता देना जरूरी है कि राज्य में गृह विभाग नीतीश कुमार के पास है। हालांकि हिन्दुस्तान अवाम मोर्चा (हम) के नेता और केन्द्रीय मंत्री जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री का बचाव करते रहते हैं। उधर, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा उम्र का हवाला देकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री अथवा जदयू अध्यक्ष में से एक पद छोड़ने की सलाह देते हैं। यह सब कुछ सीटों की हिस्सेदारी के लिए ताकत बढ़ाने की खातिर हो रहा है।

बिहार में चतुष्कोणीय मुकाबले की आहट

इधर, महागठबंधन में सीटों का पेंच सुलझने के संकेत मिले हैं। राजद के वोट बैंक में सेंधमारी के डर से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को महागठबंधन में शामिल करने से मना कर दिया गया है। ऐसे में इस बार बिहार में चतुष्कोणीय मुकाबले के आसार बन रहे हैं। इसमें एनडीए, महागठबंधन, प्रशांत किशोर की जनसुराज और बाकी बचे अन्य दल हैं। इस बीच चुनाव सर्वेक्षण करने वाली संस्था 'सी वोटर' के सर्वे में प्रशांत किशोर की लोकप्रियता में करीब 6 फीसदी का उछाल बताया गया है।

झालावाड़ में 7 बच्चों की मौत, नागौर में अगली सुबह स्कूल की छत गिरी, शिक्षा मंत्री के स्वागत ने बढ़ाया आक्रोश

झालावाड़ और नागौर हादसेः जर्जर स्कूल भवनों से बच्चों की जान पर खतरा

राजस्थान टुडे
न्यूज डेस्क

झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में सरकारी स्कूल भवन गिरने से 7 बच्चों की मौत और 21 घायल हो गए, वहीं अगली सुबह नागौर में भी एक सरकारी स्कूल की छत गिर गई। सौभाग्य से वहां कोई बच्चा मौजूद नहीं था। ये घटनाएं राजस्थान में जर्जर स्कूल भवनों के गंभीर संकट को उजागर करती हैं। राज्य सरकार ने 7,500 स्कूल भवनों को जर्जर घोषित कर मरम्मत या गिराने के आदेश दिए हैं और इसके लिए 150 करोड़ रुपए का बजट तय किया है, लेकिन कार्रवाई में देरी बच्चों की सुरक्षा पर भारी पड़ रही है। हादसे के ठीक अगले दिन शिक्षा मंत्री के भव्य स्वागत ने पीड़ित परिवारों के जख्मों पर नमक छिड़क दिया और संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में स्कूल भवन गिरने के बाद सहायता कार्य में जुटे ग्रामीण।

झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में गत माह 25 जुलाई को सवेरे हुआ दर्दनाक हादसा एक बार फिर शिक्षा व्यवस्था की नींव को झकझोर गया है। एक सरकारी स्कूल की जर्जर इमारत गिरने से सात मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी और 21 बच्चे घायल हो गए। यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि इसे वर्षों से चली आ रही अनदेखी, लापरवाही और ढिलाई का परिणाम मान सकते हैं। इस घटना ने राजस्थान में शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हर पांच साल में नई सरकार आती है, बड़े-बड़े वादे करती है, लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं आता। यहां तक कि संबंधित अधिकारी कागजी खानापूर्ति कर इतिश्री कर लेते हैं। नतीजतन मासूमों पर हर वक्त जान का खतरा मंडराता रहता है।

नागौर में भी हादसा, सौभाग्य से बची जनहानि

झालावाड़ हादसे की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अगले ही दिन नागौर जिले के खारियावास गांव में एक सरकारी स्कूल की छत का हिस्सा गिर गया। उस समय स्कूल में बच्चे मौजूद नहीं थे, इसलिए कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। लेकिन इस घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि राज्य के जर्जर स्कूल भवन हर दिन बच्चों की जान के लिए खतरा बने हुए हैं। झालावाड़ में जहां सात बच्चों की लाशें घर लौटीं, वहीं नागौर में यह महज किस्मत थी कि हादसा बच्चों की जान नहीं ले पाया।

मुस्कुराते हुए आए थे, चिर निंद्रा में लौटे बच्चे

▪ झालावाड़ जिले के पीपलोदी गांव में स्थित यह प्राथमिक विद्यालय कई वर्षों से खराब हालत में था। दीवारों पर दरारें साफ दिख रही थीं और छत टपकती थी। शिक्षकों ने कई बार संबंधित विभाग को इसकी मरम्मत या नई इमारत निर्माण की मांग की थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। घटना वाले दिन अचानक तेज बारिश के बीच सवेरे इमारत का एक हिस्सा भरभराकर गिर पड़ा, जिससे सात बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई और 21 घायल हो गए।

▪ पीड़ित परिवारों में मातम पसरा है। जिन बच्चों ने सुबह मुस्कुराते हुए स्कूल की ओर कदम बढ़ाए थे, शाम को वे चिर निंद्रा में घर लौटे। यह हादसा हर अभिभावक के मन में यह सवाल छोड़ गया है कि क्या उनके बच्चे स्कूल में सुरक्षित हैं?

दर्द के बीच संवेदनहीनता का प्रदर्शन

झालावाड़ हादसे के बाद जब पूरे प्रदेश में शोक और गुस्से का माहौल था, उसी समय भरतपुर में हुए एक कार्यक्रम में शिक्षामंत्री मदन दिलावर का भारी-भरकम मालाओं से स्वागत किया जा रहा था। हादसे के अगले दिन आयोजित इस भव्य स्वागत पर विपक्ष ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। पीड़ित परिवारों का दर्द और प्रशासन की संवेदनहीनता का यह विरोधाभास समाज के सामने बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या सत्ता प्रतिष्ठान बच्चों की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर गंभीर है?

राजस्थान में स्कूल भवनों के हालात

▪ झालावाड़ और नागौर की ये घटनाएं अपवाद नहीं हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में 7,500 से अधिक स्कूल भवनों को जर्जर घोषित कर मरम्मत या गिराने के आदेश दिए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने इसके लिए लगभग 150 करोड़ रुपए का बजट भी तय किया है, लेकिन ज्यादातर जगह यह कार्यवाही अब तक पूरी नहीं हो पाई है। कई स्कूल भवन ऐसे हैं, जिनकी उम्र 50 से 60 साल से अधिक हो चुकी है, और न तो उनकी समय पर मरम्मत होती है और न ही पुनर्निर्माण।

▪ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में यह स्थिति ज्यादा गंभीर है। यहां के स्कूल अक्सर एक या दो कमरों में चल रहे हैं। बरसात के दिनों में हालात बदतर हो जाते हैं, क्योंकि छतें टपकती हैं, दीवारें कमजोर हैं और बिजली की व्यवस्था न होने से बच्चों को अंधेरे में पढ़ना पड़ता है।

स्कूल में लोहे का गेट व पिलर बच्चे पर गिरा, मौत

जैसलमेर जिले के पूनमनगर गांव में एक बालिका स्कूल का गेट व पिलर गिरने से एक बालक की मौत हो गई। बालक छुट्टी होने के बाद स्कूल के बाहर गेट के पास अपनी बहन के इंतजार में खड़ा था। इसी दौरान लोहे का गेट व पिलर उस पर गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस जर्जर पिलर व गेट की सूचना भी उच्च अधिकारियों को दी हुई थी।

चेतावनियों के प्रति गंभीरता नहीं

▪ शिक्षा विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग पर इसकी बड़ी जिम्मेदारी है। जब किसी भवन के जर्जर होने की रिपोर्ट आती है तो इसे मरम्मत या गिराने के लिए सूचीबद्ध कर दिया जाता है, लेकिन अक्सर फण्ड की कमी या प्रक्रियात्मक देरी के कारण सालों तक काम नहीं हो पाता।

▪ शिक्षकों और ग्राम पंचायतों की चेतावनी को भी गंभीरता से नहीं लिया जाता। कई जगहों पर भवन को खतरनाक घोषित करने के बावजूद बच्चे उन्हीं में पढ़ने को मजबूर होते हैं, क्योंकि कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती। इस लापरवाही का खामियाजा झालावाड़ और नागौर जैसे हादसों के रूप में सामने आ रहा है।

नियमित जांच व मरम्मत जरूरी

- प्रदेश के सभी स्कूली भवनों का हर साल तकनीकी निरीक्षण जरूरी है। कमजोर या खतरनाक घोषित भवनों की सूची सार्वजनिक की जाए, ताकि अभिभावक भी सतर्क रहें
- जर्जर भवनों की मरम्मत या पुनर्निर्माण के लिए शिक्षा विभाग को विशेष फण्ड उपलब्ध कराना जरूरी
- जब तक भवन तैयार न हो जाए, तब तक बच्चों के लिए सुरक्षित वैकल्पिक जगह पर पढ़ाई की व्यवस्था हो
- इस तरह के हादसों में जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। सिर्फ निलंबन या नोटिस से बात नहीं बनेगी, बल्कि लापरवाही को दंडनीय अपराध की श्रेणी में लाना होगा

समाज की भूमिका भी जरूरी

अब सवाल ये उठता है कि क्या यह केवल सरकार की जिम्मेदारी है? बिल्कुल नहीं, समाज, अभिभावक और पंचायत स्तर पर भी जागरूकता बढ़नी चाहिए। यदि किसी स्कूल भवन की हालत खराब है तो समय रहते इसकी सूचना प्रशासन तक पहुंचाई जाए और कार्रवाई के लिए दबाव बनाया जाए। कई जगह पंचायत फण्ड या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भी भवनों का नवीनीकरण किया जा सकता है।

सबक और भविष्य की दिशा

▪ झालावाड़ और नागौर के हादसे सरकार व प्रशासन के लिए एक सबक हैं। ये हादसे हमें याद दिलाते हैं कि विकास केवल बड़ी-बड़ी योजनाओं या शहरों की चमक-दमक से नहीं होता। असली विकास तब है जब गांव का बच्चा भी सुरक्षित वातावरण में पढ़ सके।

▪ राजस्थान सरकार को इन हादसों को चेतावनी की तरह लेना होगा। जिन 2,000 स्कूल भवनों को मरम्मत या गिराने के आदेश हो चुके हैं, उन पर तत्काल कार्रवाई भी जरूरी है। साथ ही बाकी भवनों के लिए एक समयबद्ध पुनर्निर्माण योजना बनानी होगी। यह काम केवल कागजों पर नहीं, जमीनी स्तर पर दिखना चाहिए।

▪ शिक्षा का अधिकार तभी सार्थक है जब स्कूल बच्चों के लिए सुरक्षित हों। सरकार व प्रशासन को यह याद रखना चाहिए कि हर बच्चा देश का भविष्य है और उनकी सुरक्षा पर समझौता किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए।

'घर का काम नहीं, जो जेब से रुपए दें'

झालावाड़ जिले में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 मासूमों बच्चों की मौत के बाद लगातार जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत की मांग उठ रही है। इसी बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकारी स्कूलों की मरम्मत को लेकर मीडिया के सवाल पर कहा कि ये कोई घर का काम तो है नहीं कि जेब से पैसे निकाल कर दें। भरतपुर दौरे के दौरान दिलावर ने स्कूलों को मिलने वाले बजट के सवाल पर कहा, 'ये सरकारी प्रोसेस होता है, टेंडर होता है। मैंने नैतिकता के आधार पर घटना की जिम्मेदारी ली है। हमारे पास जर्जर स्कूलों की सूची आई, उसमें झालावाड़ के स्कूल का नाम नहीं था। पिछली बार मरम्मत के लिए 80 करोड़ रुपए दिए और इस बार भी 80 करोड़ रुपए दिए थे।'

बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा पर असर

▪ जर्जर स्कूल भवन न केवल बच्चों की जान के लिए खतरा हैं, बल्कि उनकी शिक्षा पर भी गहरा असर डालते हैं। जब बच्चे असुरक्षित महसूस करते हैं तो उनका ध्यान पढ़ाई में नहीं लग पाता। कई बार अभिभावक भी डर के कारण बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं।

▪ इसके अलावा जब किसी स्कूल भवन को अस्थायी रूप से बंद किया जाता है तो बच्चों को दूसरे गांवों के स्कूलों में भेजना पड़ता है। लम्बी दूरी और परिवहन की समस्या के कारण कई बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। यह स्थिति विशेषकर बालिकाओं के लिए गंभीर हो जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई बालिकाएं दूरी के कारण स्कूल छोड़ने को मजबूर हो जाती है।

स्कूल के पुराने स्टोर रूम की छत गिरी... पिड़ावा (झालावाड़) में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दांता के एक पुराने स्टोर रूम की छत की पट्टियां तेज बारिश के कारण टूट गईं। रविवार का अवकाश होने के कारण वहां कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। यह कमरा 13 वर्ष पहले ही जर्जर घोषित कर दिया गया था।

उदयपुर जिले में गिरी स्कूल की छत

झालावाड़ में हुए स्कूल हादसे के बाद हर रोज किसी न किसी स्कूल की छत, दीवार, प्लास्टर या बरामदा गिरने की खबरें आ रही हैं। उदयपुर जिला मुख्यालय से सटे वल्लभनगर क्षेत्र के रूपावली गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि रविवार को छुट्टी होने से स्कूल बंद था। वरना वहां पढ़ने वाले करीब 90 बच्चों की जान पर बन आती। प्रधानाध्यापक के अनुसार भवन की जर्जर स्थिति के बारे में शिक्षा विभाग को पहले ही अवगत कराया जा चुका था और मरम्मत के लिए बजट भी स्वीकृत हो गया है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ।

छुट्टी होने से टला हादसा... आनंदपुरी (बांसवाड़ा) के सल्लोपाट थाना क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कलाजी मंदिर, मोनाडूंगर में स्कूल भवन के आगे का बरामदा भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि अवकाश था, अन्यथा हादसा गंभीर हो सकता था। जिले में कई सरकारी स्कूलों की इमारतें वर्षों पुरानी हो चुकी हैं और लगातार उपेक्षा के कारण अब जानलेवा बनती जा रही हैं।

स्मार्ट मीटर और 'स्मार्ट' राजनीति

राजस्थान में अब बिजली सिर्फ मीटर से नहीं, राजनीति से भी तपी हुई है। एक तरफ मीटर है जो हर यूनिट का हिसाब मांगता है। दूसरी तरफ नेता'जी हैं जो हर आरोप का जवाब सवाल से देते हैं। कांग्रेस कहती है ये स्मार्ट मीटर गरीबों की जेब पर बोझ हैं, और भाजपा कहती है 'भैया, ये तो तुम्हारी ही रसोई से पका पकाया आइडिया है!' अब जनता सोच रही है कि मीटर स्मार्ट है या सियासत? और एक नेता'जी के सरकारी बंगले का बिल देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बिजली नहीं, राजनीति करंट दे रही हो। मंत्री'जी कह रहे हैं 'मैं तो अभी डेढ़ महीने पहले ही आया हूं', जैसे बंगले के मीटर ने उनका स्वागत नहीं किया, बल्कि बिल का बवाल दे दिया। कुल मिलाकर मीटर हो या मंत्री सभी चालू हैं। और जनता... वह अब समझ नहीं पा रही कि मीटर बदले या मतदाता!

सरिस्का में बाघ कम, बयान ज्यादा

सरिस्का के जंगल में असली बाघ हैं या नहीं, ये तो कैमरे गिनते हैं। पर सियासत के जंगल में बाघों से भी बड़े शिकारी घूम रहे हैं बयानवीर नेता! पूर्व मुख्यमंत्री'जी को अचानक याद आया कि बाघ तो उन्होंने बचाए थे! जैसे जंगल में नहीं, घर की बालकनी में पाला हो। बोले– 'हमने तो सरिस्का को जीवित किया!' अब कौन बताए कि बाघ बचाने के साथ-साथ कितने वनवासी उजड़े, और कितनी फाइलों ने जंगल की रफ्तार दबा दी? नई सरकार ने प्लान क्या बनाया, विपक्ष ने उसी में राजनीति का शिकार ढूंढ लिया। बाघों के नाम पर वोटों की बिसात बिछ गई। कभी सरिस्का को पर्यटन हब बनाने की बात, कभी सुरक्षा बढ़ाने की। और बाघ बेचारा सोचता रह गया 'कभी शिकारी से डरते थे, अब नेता से डरते हैं।'

इतिहास की छंटनी और पाठ्यपुस्तकों की सफाई

राजस्थान में शिक्षा अब ज्ञान का नहीं, विचारधारा का विषय बन चुकी है। मंत्री'जी को लगता है कि गांधी-नेहरू की बातें बच्चों के दिमाग में 'बेकार का बोझ' हैं। अरे भैया! परीक्षा में नंबर नहीं आते तो क्या, बच्चों के मन में विचार तो आते थे। पर अब पाठ्यपुस्तकें भी पार्टी लाइन पर चलाई जाएंगी, जिनमें नेता वही होंगे, जो सत्ता पक्ष को सुहाते हों। मंत्री'जी का तर्क है: "अगर हड्डी में ज़हर हो, तो उसे खाना नहीं चाहिए।" यानी इतिहास वो पढ़ाया जाए जो मंत्री'जी के स्वाद के अनुकूल हो। बाकी गांधी-नेहरू तो अब पुराने चावल हो गए। नए इतिहास में फोटो सिर्फ स्वच्छ भारत और नोटबंदी के होंगे। बच्चे चाहे ये समझें ना समझें कि नोटबंदी में लाईन में खड़े होना क्रांति थी या सजा! कुल मिलाकर, अब पाठ्यपुस्तकें नहीं, पाठ्य-पट्टी बंधेगी, ताकि बच्चे वही याद करें, जो सत्ता चाहे। इतिहास अब सवालों से नहीं, सत्ता की सहूलियत से लिखा जाएगा।

सेल्फी से सेवानिवृत्ति

जोधपुर के सरकारी कर्मचारियों की आजकल सबसे बड़ी चिंता ये नहीं कि फाइल समय पर पूरी हो रही है या नहीं, बल्कि ये है कि कहीं विधायक के कैमरे की नजर न पड़ जाए। विधायक'जी जब मुस्कराते हुए कहें 'आओ सेल्फी लें,' तो सामने वाले की मुस्कान गायब हो जाती है। अब ये सेल्फी साधारण फोटो नहीं रही, ये तो तबादले का ट्रिगर बन चुकी है। हाल ही में नगर निगम के तीन कर्मचारियों ने मुस्कराकर फोटो क्या खिंचवाई, कुछ ही घंटों में एपीओ के आदेश आ गए। अब शहर में विधायक के कैमरे की आहट भी किसी इमरजेंसी अलार्म जैसी लगती है। कर्मचारी एक-दूसरे को सतर्क करते हैं 'मोबाइल निकला है, सर आ रहे हैं, पीछे हो लो!' घंटाघर से त्रिपोलिया तक जहां-जहां गंदगी और अतिक्रमण फैला था, वहां अब डर की सफाई चल रही है। जोधपुर में फिलहाल विकास का नया मंत्र चल रहा है 'सेल्फी लो और सुधर जाओ!

छुट्टियों वाला शासक और आदेशों की आंधी

एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर में इन दिनों इंजीनियरिंग से ज़्यादा 'इंटरनल पॉलिटिक्स' का कोर्स चल रहा है। कुलपति'जी छुट्टियों का सुख लेने सिंगापुर रवाना हो गए और पीछे छोड़ गए 12 आदेश, जैसे छुट्टी पर नहीं, कोई 'विकास योजना' पर निकले हों। इन आदेशों में नियुक्तियों से लेकर स्टोर विभाग तक हर चीज़ को 'ठीक' करने का फरमान है। और इस 'सुधार' रूपी तूफान के बीच अकेले जूझ रहे हैं एक उच्च अधिकारी, जिनके पास हर घंटे नई जांच कमेटी गठित करने का काम है। अब एमबीएम कॉलेज पढ़ाई के लिए नहीं, फाइलें उलटने और साइन ढूंढने की प्रयोगशाला बन गया है। छात्र हैरान हैं, शिक्षक परेशान हैं और कर्मचारी सोच में हैं कि अगला आदेश किसके गले पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था छुट्टियों में है, और आदेश व्यवस्था 'हॉलीडे मोड' में क्रांतिकारी बन गई है।

राजनीति में गाना और संविधान का बहाना

सीकर के धोद की रैली में कांग्रेस ने 'संविधान बचाओ' का झंडा उठाया, और नेता प्रतिपक्ष ने गाना गाया- "तेरे जैसा यार कहां..." अब समझ नहीं आया, ये रैली संविधान के लिए थी या दोस्ती की महफिल? विपक्ष के नेता बोले, बीजेपी ने डेढ़ साल में कुछ नहीं किया। मानो खुद ने पांच साल में संसद की छत पर संविधान की गारंटी लिख दी थी! नेता प्रतिपक्ष तो और भी आगे निकले, बोले 'बिजली-पानी काट देते हैं विरोधियों की!' भाईसाहब, जनता की तो पहले ही उम्मीदें कटी पड़ी हैं, अब कनेक्शन की दुहाई क्यों? कई दूसरे नेता'जी भी मंच पर थे, पर असली नज़ारा था राजनीति का तमाशा और संविधान का नाम। गाना चल रहा था, जनता सोच रही थी 'संविधान बचे न बचे, नेता तो अच्छे से नाचे!'

▪ बलवंत राज मेहता

कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस नए युग में कोडिंग से अधिक ज़रूरी है विज्ञान और गणित की गहरी समझ

सिर्फ कोडिंग नहीं, आगे बढ़ने के लिए तार्किक सोच जरूरी

एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग और टेस्ला के एलोन मस्क जैसे दिग्गजों का मानना है कि एआइ के युग में केवल कोडिंग जानना पर्याप्त नहीं है। आने वाले वर्षों में भौतिकी और गणित की गहरी समझ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तार्किक सोच ही वह आधार होंगे, जो नई पीढ़ी को तकनीकी नेतृत्व दिला सकते हैं।

राकेश गांधी
वरिष्ठ पत्रकार

> कोडिंग से ज्यादा जरूरी है विज्ञान की समझ —**जेनसन हुआंग**
>
> फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग की जरूरत —**एलोन मस्क**

तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में हाल ही में एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग का एक बयान चर्चा में रहा। बीजिंग में छात्रों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, "यदि मैं आज 22 साल का छात्र होता, तो कंप्यूटर विज्ञान (कम्प्यूटर साइंस) की बजाय भौतिक विज्ञान (फिजिक्स) पढ़ता।" यह कथन केवल एक व्यक्तिगत राय नहीं, बल्कि तकनीकी दुनिया के गहरे बदलाव की ओर संकेत करता है। हुआंग का कहना है कि भविष्य की कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) अब केवल कोडिंग पर आधारित नहीं रहेगी, बल्कि यह वास्तविक दुनिया को समझने और उसमें कार्य करने की क्षमता पर केंद्रित होगी।

हुआंग ने एआई विकास की चार लहरों का जिक्र किया, इनमें परसेप्शन एआइ यानी इमेज, वॉइस और पैटर्न पहचानने वाली एआइ, जेनेरेटिव एआइ जो चैटजीपीटी या इमेज जेनरेटिंग टूल्स जैसे टेक्स्ट और कंटेंट बना सके, रिजनिंग एआइ यानी एआइ का तार्किक सोच विकसित करना और चौथा है फिजिकल एआइ, जो वास्तविक दुनिया में मौजूद भौतिक परिस्थितियों को समझकर कार्य कर सके। उनका तर्क है कि इस नई लहर में इंसानों को ऐसी मशीनें विकसित करनी होंगी जो जड़त्व, घर्षण, कारण–परिणाम और वास्तविक दुनिया के अन्य नियमों को समझें। ऐसे में मैथ्स और फिजिक्स की गहरी समझ अनिवार्य है।

कोडिंग का बदलता स्वरूप

- एआइ का सबसे बड़ा प्रभाव कोडिंग पर पड़ा है। आज जनरेटिव एआइ टूल्स, प्राकृतिक भाषा को प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। एनवीडिया प्रमुख ने कहा कि अब "प्रॉम्प्ट" ही नई प्रोग्रामिंग भाषा है। इसका अर्थ यह है कि एक साधारण व्यक्ति भी एआइ से कह सकता है कि उसे क्या करना है, ठीक वैसे जैसे हम गुगल से कुछ सर्च करने को कहते हैं।
- यानी कल तक जहां कोड लिखना विशेषज्ञता की मांग करता था, आज एआइ की मदद से बिना कोड लिखे ही जटिल काम हो सकते हैं। यही कारण है कि हुआंग का कहना है, "अब बच्चों को कोडिंग सिखाना जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें समस्या की गहरी समझ और सही दिशा में सोचने की क्षमता देनी चाहिए।"

एलोन मस्क और अन्य नेताओं का समर्थन

- हुआंग की राय अकेली नहीं है। टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलोन मस्क भी लम्बे समय से कहते रहे हैं कि छात्रों को "फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग" यानी मौलिक सिद्धांतों से समस्या हल करना सीखना चाहिए। मस्क ने हाल ही में पावेल डुरोव (टेलीग्राम के संस्थापक) के इस सुझाव का समर्थन किया कि छात्रों को मैथेमेटिक्स और फिजिक्स में महारत हासिल करनी चाहिए, क्योंकि यही वैज्ञानिक सोच की नींव है।
- मस्क का यह तर्क है कि तकनीकी चुनौतियों को हल करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्राकृतिक नियम क्या कहते हैं, न कि यह कि "अभी तक क्या किया जाता रहा है।" यह सोच कोडिंग के रटे-रटाए तरीकों से आगे जाकर नए आविष्कारों की राह खोलती है।

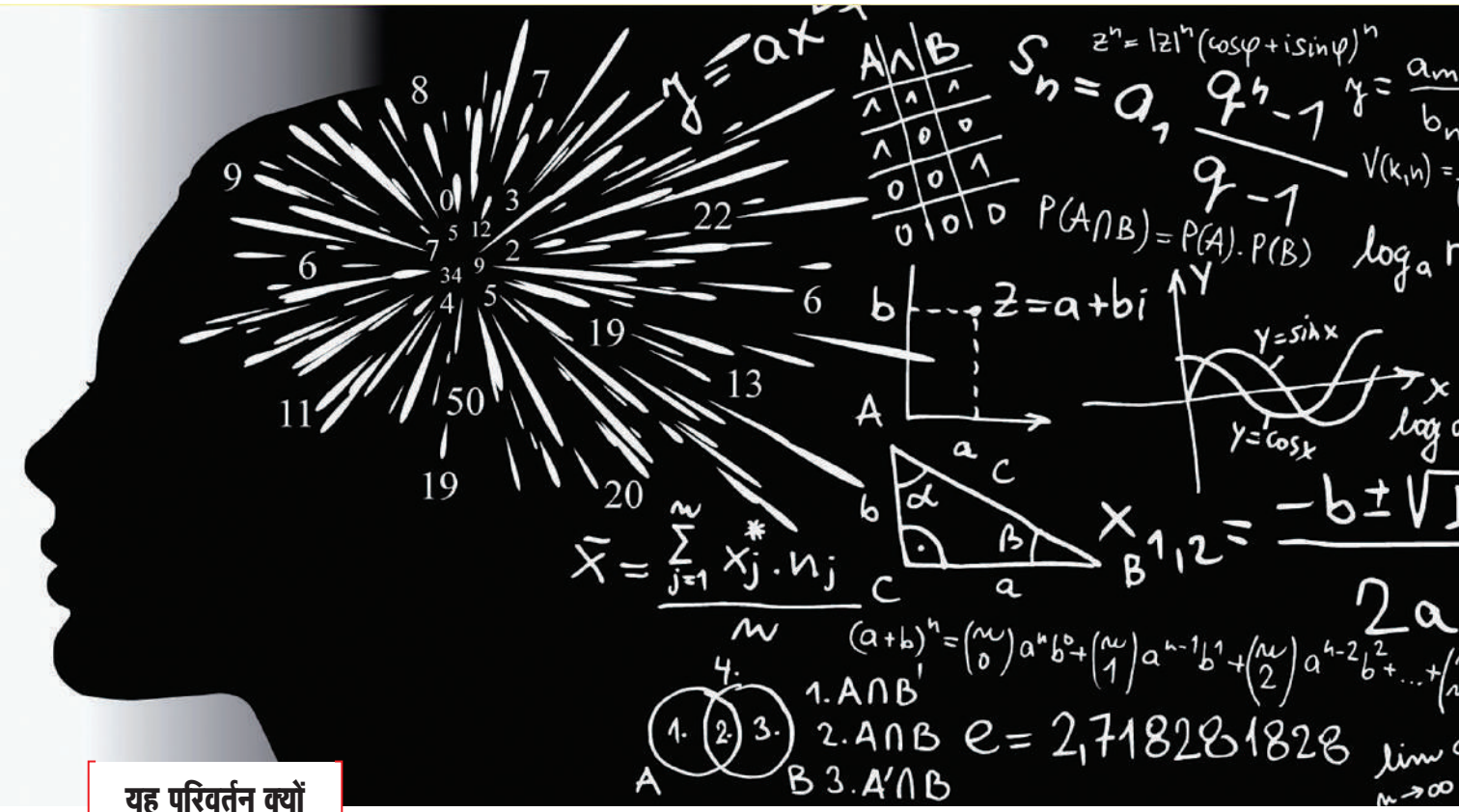

यह परिवर्तन क्यों महत्वपूर्ण है?

- अब एआइ सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग या कंटेंट जनरेट करने तक सीमित नहीं है। यह रोबोटिक्स, स्वायत्त वाहनों, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और मेडिकल डायग्नोसिस जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। इन सब क्षेत्रों में मशीन को वास्तविक दुनिया के नियमों के अनुसार काम करना होता है।

- एआइ अब इंसानी भाषा को समझता है और उसके अनुसार कार्य कर सकता है। इसलिए तकनीकी भाषाओं का महत्व कुछ हद तक कम होता जा रहा है।

- जटिल समस्याओं का समाधान केवल कोडिंग से नहीं हो सकता। इसके लिए गणितीय मॉडलिंग, तार्किक सोच और भौतिक नियमों की समझ जरूरी है।

क्या कोडिंग अप्रासंगिक हो जाएगी?

- यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि कोडिंग का महत्व पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। मशीनों को कैसे चलना है, इसका ढांचा तैयार करने के लिए प्रोग्रामिंग भाषाओं की भूमिका हमेशा रहेगी। लेकिन यह भूमिका "बैकएंड" में चली जाएगी। उपयोगकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए मुख्य चुनौती यह होगी कि वे समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकें, सही एल्गोरिदम चुन सकें और एआइ को सही दिशा में प्रशिक्षित कर सकें।

- इसलिए भविष्य में केवल कोड लिखना जानना पर्याप्त नहीं होगा। बल्कि यह समझना जरूरी होगा कि किसी समस्या को किस तरह डिजाइन और मॉडल किया जाए। यही कौशल मैथ्स और फिजिक्स की गहरी समझ से आता है।

> कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मौजूदा दौर ने तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास के मानदंड बदल दिए हैं। अब यह जरूरी है कि हम बच्चों को केवल कोडिंग सिखाने के बजाय उन्हें सोचना सिखाएं, समस्या को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की आदत डालें। जेनसन हुआंग और एलोन मस्क जैसे नेताओं के ये संदेश हमें भविष्य के लिए चेतावनी देते हैं कि अगर हम आज भी पुराने ढर्रे पर अटके रहे तो कल की तकनीक में पिछड़ जाएंगे। भौतिकी, गणित और वैज्ञानिक तर्कशक्ति ही वह आधार हैं जो हमें एआइ की अगली पीढ़ी में नेतृत्व दिला सकते हैं।

संयुक्त परिवार से न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ता झुकाव

बदलता समाज और मानसिक स्वास्थ्यः रिश्तों में बढ़ते खालीपन से कैसे निपटें?

आज का समाज तेजी से बदल रहा है। संयुक्त परिवारों का विघटन, वर्क-लाइफ बैलेंस की चुनौतियां, सोशल मीडिया का दबाव और रिश्तों में संवाद की कमी मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित कर रही है। कभी बच्चों में अचानक बढ़ता गुस्सा, कभी बुजुर्गों की खामोश उदासी और कभी पति-पत्नी के बीच बढ़ती दूरी– ये सभी महज घटनाएं नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक ताने-बाने में दरार का संकेत हैं।

***'Insight with Ra..Ga' के तहत डॉ. सुरेंद्र कुमार और डॉ. सृष्टि देथा से वरिष्ठ पत्रकार राकेश गांधी ने** मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा की। पढ़ें यह विस्तृत संवाद जो बताता है कि बदलते समाज में रिश्तों को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता क्यों देनी चाहिए।*

? आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है? हमें बार-बार यह सवाल सुनाई देता है कि क्या हम सही दिशा में हैं या कहीं कुछ छूट रहा है?

डॉ. सृष्टि देथाः समाज को लेकर आज जो सबसे बड़ी चुनौती है वह है वर्क-लाइफ बैलेंस। लोग अपने काम में इतने व्यस्त हैं कि सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करना कठिन होता जा रहा है। परिवार और रिश्तों पर समय नहीं दे पाने से दबाव बढ़ रहा है। इस बदलाव में कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं। जितना एक्सपोजर बढ़ता है, उतना समाज में बदलाव आता है। जब तक हम बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक परेशानियां बढ़ती रहेंगी।

? तो आपको लगता है कि यह बदलाव सकारात्मक है या नकारात्मक? खासकर युवाओं में जो दृष्टि बदल रही है, उसका असर क्या है?

डॉ. सृष्टि देथाः युवाओं की सोच में सकारात्मक बदलाव भी है लेकिन सोशल मीडिया ने समस्याएं भी बढ़ा दी हैं। पहले भी गलत रास्तों पर जाने की घटनाएं होती थीं लेकिन अब सोशल मीडिया ने उन्हें बढ़ा दिया है। युवाओं का फोकस सतही हो गया है– उन्हें लगता है कि सब कुछ ऊपर से सही दिखना चाहिए। वे खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। परिवार में भावनात्मक जुड़ाव कम हो रहा है।

विस्तृत बातचीत के लिए देखें... https://www.youtube.com/watch?v=uHPnlL8J3V0

? डॉ. सुरेंद्र जी, आज के समय में न्यूक्लियर फैमिली की ओर झुकाव बढ़ रहा है। इसका समाज पर क्या असर है?

डॉ. सुरेंद्र कुमारः न्यूक्लियर फैमिली समाज में एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इसका पहला कारण आर्थिक है। पति-पत्नी दोनों ही काम पर जाते हैं। अक्सर शहर से बाहर भी जाना पड़ता है। बुजुर्ग माता-पिता अकेले रह जाते हैं और अकेलापन बढ़ने लगता है। बच्चों का ध्यान आर्थिक सम्पन्नता पर केंद्रित हो जाता है, लेकिन उसके दुष्परिणाम भी सामने आते हैं। पहले संयुक्त परिवार में बच्चे कई लोगों से सीखते थे, उनका सर्वांगीण विकास होता था। अब वे दूसरों के भरोसे छोड़ दिए जाते हैं, कई बार सीसीटीवी कैमरों से निगरानी करनी पड़ती है। बच्चों को अधिकांश समय दूसरों के सहारे गुजारना होता है। यह बच्चों के मानसिक विकास के लिए घातक है।

? कभी-कभी ऐसा लगता है कि विवाह एक तरह की "डील" बन गया है। क्या आप इससे सहमत हैं?

डॉ. सुरेंद्रः हां, आजकल विवाह को कई लोग जिम्मेदारी की बजाय समझौते के रूप में देखने लगे हैं। यही कारण है कि मेट्रो शहरों में विवाह की उम्र बढ़ रही है और लिव-इन रिलेशनशिप को प्राथमिकता दी जा रही है। उसमें प्यार है लेकिन जिम्मेदारियां कम हैं, जबकि विवाह में कई जिम्मेदारियां निभानी होती हैं।

? आपको नहीं लगता कि आज कई नौकरीपेशा पति-पत्नी अपने माता-पिता को साथ नहीं रखना चाहते? "हम दो-हमारे दो" की सोच क्यों बढ़ रही है?

डॉ. सुरेंद्रः आज समाज में निज स्वतंत्रता का चलन बढ़ गया है। कपल को लगता है कि यदि माता-पिता उनके साथ रहेंगे तो उनकी स्वतंत्रता बाधित होगी– समय पर घर आना पड़ेगा, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना होगा, और कुछ सामाजिक मर्यादाएं निभानी होंगी। इसी वजह से वे अलग रहना पसंद करते हैं। यह एक तरह से यूरोपियन कल्चर का प्रभाव है, जहां माता-पिता को खर्चा भेज दिया जाता है, लेकिन साथ नहीं रखा जाता।

? ऐसे हालात में महिलाओं को क्या करना चाहिए? क्या यह पुरुषों की या महिलाओं की ज्यादा जरूरत होती है कि वे स्वतंत्र रहें?

डॉ. सृष्टि: आजादी सबका हक है, लेकिन रिश्तों में बैलेंस जरूरी है। न तो किसी की स्वतंत्रता पूरी तरह खत्म होनी चाहिए और न ही हर बात पर डिक्टेट करना चाहिए। दोनों पीढ़ियों को समझना होगा कि परिवार में हर किसी को अपना स्पेस चाहिए। तभी सब लोग साथ रहते हुए भी खुश रह सकते हैं।

? मुझे लगता है कि इस बदलाव का खामियाजा बच्चों और महिलाओं को सबसे अधिक भुगतना पड़ रहा है।

डॉ. सुरेंद्र कुमार: सही कहा आपने। महिला का भावनात्मक वेंटिलेशन नहीं हो पाता। पहले महिलाएं प्रसव के समय मायके जाती थीं, परिवार का सहयोग मिलता था। अब न्यूक्लियर फैमिली के कारण वे हॉस्पिटल तक सीमित हो गई हैं। महिला पूरे घर- परिवार की धुरी होती है। जब वह खुद को दरकिनार कर सबकी खातिर बलिदान देती है और बदले में सहयोग नहीं मिलता तो अवसाद बढ़ता है। वो काम काम के बोझ तले इतनी दब सी गई है कि वे कहीं न कहीं कुंठा की शिकार हो रही है और वो कुंठा उसमें एक अराजकता की भावना पैदा कर रही है। चिड़चिड़ापन, नींद न आना, काम में मन न लगना जैसे मानसिक लक्षण नजर आने लगते हैं।

डॉ. सृष्टि देथा: समाज की अपेक्षाएं महिलाओं से कम नहीं हुई हैं। पहले लड़का- लड़की में फर्क होता था, अब इंडिविजुअल लेवल में आप परिवारों में देखेंगे तो बेटा- बेटी को एक ही तरीके से बड़ा किया जाता है। उनको उतनी ही अच्छी परवरिश दी जा रही है। उनको एक जैसे ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन शादी के बाद जेंडर रोल्स वही पुराने हैं। महिलाएं बच्चे की परवरिश और नौकरी दोनों को संतुलित करती हैं लेकिन सहयोग कम मिलता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का कारण यही है – परिवार का सपोर्ट सिस्टम कमजोर हो गया है। बेसिकली जो जेंडर रोल्स सोसाइटी ने डिफाइन किए हुए हैं, उन्हें थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है।

? क्या पुरुष भी मानसिक दबाव का सामना कर रहे हैं?

डॉ. सुरेंद्र कुमार: कई बार पुरुष सैंडविच बन जाते हैं। वे जिस मां के दामन में बड़े हुए हैं, उस मां को कैसे छोड़ सकते हैं और दूसरी ओर पत्नी को भी नाराज नहीं कर सकते। शादी रिश्तों की जननी है, लेकिन जब पति-पत्नी के विचारों में तालमेल नहीं होता तो पुरुष मानसिक दबाव में आ जाता है। अगर स्त्री समझदार है, सोशल इंजीनियरिंग उसकी स्ट्रांग है तो बहुत अच्छे से तालमेल बना लेती है। ऐसे में पुरुष सैंडविच बनने से बच जाता है।

डॉ. सृष्टि देथा: रिश्तों में संवाद की कमी तनाव का सबसे बड़ा कारण है। दोनों पीढ़ियों को एक-दूसरे को समझना होगा। जो पुरानी पीढ़ी है उसे नई जिम्मेदारियों को समझना चाहिए और नई पीढ़ी को भी माता-पिता का अनुभव मानना चाहिए। तभी इन समस्याओं का निवारण संभव होगा।

? क्या मोबाइल फोन कहीं न कहीं हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा रहे हैं?

डॉ. सृष्टि देथा: बिल्कुल। फोन का उद्देश्य हमें जोड़ना था, लेकिन यह हमें disconnect कर रहा है। परिवार में सब लोग एक ही टेबल पर बैठे हैं लेकिन हर कोई अपने-अपने फोन में खोया है। पति-पत्नी एक कमरे में हैं लेकिन डिजिटल रूप से अलग-अलग स्क्रीन पर।

? क्या यह सच है कि लोग अपनी परेशानियां शेयर नहीं करते और यही मानसिक रोगों का कारण बनता है?

डॉ. सुरेंद्र कुमार: मन शरीर का कोई अंग नहीं है, इसलिए उसकी परेशानी छिप जाती है। लोग अपनी समस्याएं बताते नहीं, उन्हें डर होता है कि शेयर करने पर उनका मजाक उड़ाया जाएगा। यही घुटन डिप्रेशन, एंग्जायटी और अन्य मानसिक रोगों को जन्म देती है।

? तो मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए?

डॉ. सृष्टि देथा: हमें सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखना होगा। परिवार में बातचीत का दायरा बढ़ाना होगा। साथ ही वर्क-लाइफ बैलेंस पर काम करते रहना चाहिए। जजमेंट हटाकर सुनें और एक-दूसरे को स्पेस दें।

डॉ. सृष्टि देथा: पुरुषों से बचपन से कहा जाता है कि रोना नहीं चाहिए। भावनाएं दबाने से मन का बोझ बढ़ता है। जब तक हम एक-दूसरे को सुनेंगे नहीं, तब तक रिश्तों में खामोशी बढ़ेगी। यही कारण है कि पारिवारिक समस्याओं के चलते सुसाइड के मामले सबसे अधिक सामने आते हैं।

डॉ. सुरेंद्र कुमार: योग, ध्यान, व्यायाम और संगीत को जीवन का हिस्सा बनाएं। हेल्दी डाइट और नियमित दिनचर्या अपनाएं। मद्यपान से दूरी रखें और दोस्तों व परिवार के साथ समय बिताएं। अपनी भावनाएं शेयर करें।

"मनुष्य अकेलेपन में जी नहीं सकता। परिवार वह पहली पाठशाला है जहां हम प्रेम, त्याग और धैर्य सीखते हैं। संयुक्त परिवार केवल दीवारों का साझा करना नहीं है, यह दिलों का जुड़ना है।"
- महात्मा गांधी

"परिवार ही जीवन का सबसे बड़ा विद्यालय है। यदि वहां प्रेम और समझ नहीं होगी तो दुनिया के किसी कोने में भी शांति नहीं मिल सकती।"
- लियो टॉलस्टॉय

"मैं जो कुछ भी हूं, या बनने की आशा करता हूं, उसका श्रेय मेरे परिवार को जाता है। घर ही वह जगह है, जहां व्यक्ति सबसे पहले जीवन के मूल्यों को सीखता है।"
- अब्राहम लिंकन

"हमारा स्वभाव ही हमें एक-दूसरे से जोड़ता है। परिवार में रहते हुए हम सहनशीलता, प्रेम और करुणा को आत्मसात करते हैं। यही भाव समाज को मजबूत बनाते हैं।"
- स्वामी विवेकानंद

"सच्चा परिवार वह है जहां हर व्यक्ति को अपना महत्व महसूस हो। जब घर के सभी लोग एक-दूसरे के सुख-दुख में सहभागी बनते हैं, तभी समाज में सामंजस्य आता है।"
- रवींद्रनाथ ठाकुर

"संयुक्त परिवार केवल आर्थिक सहयोग नहीं देता, यह मनुष्य को सहनशीलता, त्याग और परस्पर सहयोग का अभ्यास कराता है। यही गुण समाज को जीवंत बनाते हैं।"
- विनोबा भावे

राजस्थानी: जिसे गियर्सन ने 'भाषा' कहा, पर हम चुप क्यों हैं?

माटी, संगीत व संवाद में सुनाई देती है 'राजस्थानी' की गूंज

बलवंत राज मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

क्या 'राजस्थानी' सचमुच कोई पुरातन भाषा-नाम है, या यह उपनिवेशकालीन प्रयोगशाला की उपज? यह आलेख एक रोचक भाषिक यात्रा है, जो 'राजस्थानी' शब्द के जन्म, इसके ऐतिहासिक सन्दर्भ और सांस्कृतिक विकास की परतें खोलता है। 1912 में अंग्रेज़ भाषाविद् गियर्सन द्वारा पहली बार प्रयुक्त यह शब्द, आज एक पूरे जनसमूह की चेतना, आत्मगौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन चुका है। आलेख यह भी बताता है कि कैसे यह नाम विविध बोलियों की एकता का सूत्र बन गया — माटी की गूंज बनकर।

कभी आपने सोचा है कि हम जिस भाषा को आत्मगौरव से "राजस्थानी" कहते हैं, वह शब्द अस्तित्व में कब आया..? क्या हमारे दादाजी या उनके पूर्वजों ने इसे इसी नाम से जाना..? क्या किसी राजा की ताम्रपत्री आज्ञा "राजस्थानी भाषा" में लिखी गई थी..? या किसी लोकदेवता की ही वाणी इस नाम से पहचानी जाती थी..?

इन सवालों के उत्तर चौंकाते हैं। "राजस्थानी" शब्द, जैसा हम आज जानते हैं, प्रथम बार 1912 में एक अंग्रेज़ भाषाविद् जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा प्रयोग में लाया गया। इससे पहले राजस्थान की सांस्कृतिक स्मृतियों, शिलालेखों, अभिलेखों, काव्य रचनाओं, मंदिरों की भाषा या दरबारों के आदेश, कहीं भी इस शब्द का उल्लेख नहीं मिलता। और यही बात इस शब्द को रहस्यमय, राजनीतिक और भाषाई विमर्श का केंद्र बना देती है।

गियर्सन ब्रिटिश राज के अधीन एक भाषाशास्त्री थे, जिन्हें भारत की भाषाओं के सर्वेक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया था। यह कार्य उन्होंने अपने विशाल ग्रंथ "लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया" के अंतर्गत किया, जो 1894 से 1928 तक विभिन्न खण्डों में प्रकाशित हुआ। उन्होंने 1912 में इस सर्वेक्षण के एक खण्ड में पहली बार "राजस्थानी" शब्द का प्रयोग किया और इसे राजस्थान क्षेत्र में बोली जाने वाली अनेक बोलियों के लिए एक सामूहिक नाम के रूप में प्रस्तुत किया।

गियर्सन ने राजस्थानी भाषा को पांच उपशाखाओं में बांटा। पश्चिमी राजस्थानी जिसमें मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी और बागड़ी आती हैं; उत्तर-पूर्वी में मेवाती और अहीरवाटी; मध्य-पूर्वी में ढूंढाड़ी और हाड़ौती; दक्षिणी-पूर्वी में मालवी और निमाड़ी; तथा दक्षिणी राजस्थानी में डांग क्षेत्र की बोलियां। यह वर्गीकरण दर्शाता है कि उन्होंने भाषा को केवल राजनीतिक सीमाओं से नहीं, बल्कि उसके ध्वन्यात्मक, व्याकरणिक और सामाजिक आधार पर समझा।

लेकिन गियर्सन द्वारा दिए गए इस नाम से पहले राजस्थानी भाषा के अस्तित्व को किसी

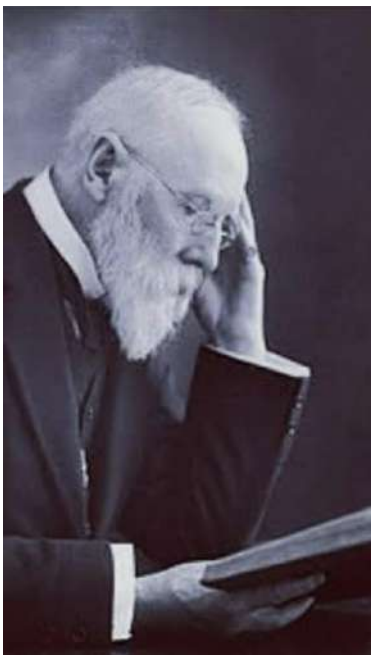

ने इस रूप में नहीं देखा था। शिलालेखों में भाषा संस्कृत, प्राकृत या क्षेत्रीय लोकभाषा में होती थी। दरबारों में जो भाषा प्रचलित थी, वह मारवाड़ी या ब्रज मिश्रित शैली में होती थी। लोककथाओं, लोकगीतों और देववाणियों में तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी की कथाएं क्षेत्रीय बोलियों में होती थीं, राजस्थानी नाम से नहीं। जैन ग्रंथों में भी भाषा को 'मरुभाषा' या क्षेत्र के नाम से जाना गया है।

प्राचीनतम साक्ष्य आठवीं शताब्दी में जैन आचार्य उद्योतन सूरी की "कुवलयमाला" में मिलता है, जहां भाषा को "मरुभाषा" कहा गया है। राजस्थानी का पहला ग्रंथ जैन आचार्य वज्रसेन सूरी द्वारा रचित "भरतेश्वर बाहुबलि घोर" माना जाता है। राजस्थानी साहित्य का स्वर्ण युग 1450 से 1850 के बीच माना गया है, जिसमें भक्ति आंदोलन, नाथपंथ, संत काव्य, जैन उपदेश और वीर रस की रचनाएं शामिल हैं। अबुल फज़ल की "आईन-ए-अकबरी" में भी मारवाड़ी को भारत की प्रमुख भाषाओं में स्थान मिला है। सत्रहवीं और अठारहवीं सदी की अनेक रचनाओं में भी "मरुभाषा" शब्द का प्रयोग होता है, "राजस्थानी" नहीं।

साहित्यिक चेतना का प्रतीक 'राजस्थानी'

यानी 'राजस्थानी' नाम कोई पुरातन लोक-उद्गार नहीं था, बल्कि एक औपनिवेशिक दृष्टि से किया गया भाषावैज्ञानिक वर्गीकरण था। परंतु यह नाम धीरे-धीरे एक चेतना, एक सांस्कृतिक पहचान और एक जनवाणी बन गया। राजस्थानी अब केवल भाषाशास्त्र का विषय नहीं, बल्कि सांस्कृतिक स्वाभिमान, साहित्यिक चेतना और लोक की अभिव्यक्ति का प्रतीक बन चुकी है।

- आज भी लोग स्वयं को मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती या शेखावाटी भाषी कहते हैं, लेकिन "राजस्थानी" उस छतरी शब्द के रूप में स्थापित हो चुका है जो इन सभी विविधताओं को एक पहचान देता है। यह विविधता इस नाम के लिए चुनौती भी है और उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी।
- भले ही यह शब्द औपनिवेशिक प्रयोगशाला में जन्मा हो, लेकिन अब इसकी गूंज माटी, संगीत और संवाद में सुनाई देती है। भाषा का नाम चाहे जैसा हो, अगर लोग उसमें अपने मन की बात कहें, तो वह नाम भी असली हो जाता है। राजस्थानी अब केवल एक नाम नहीं, वह जन की वाणी बन चुकी है , गियर्सन की लेखनी से निकलकर माटी के मन तक।

यूनिकॉर्न के पीछे छिपा संकट: नवाचार से प्रतिस्पर्धा तक

सपनों का कारोबार, किसकी कीमत पर?

डॉ. पी.एस. वोहरा
आर्थिक मामलों के जानकार

भारत में स्टार्टअप्स की तेज़ रफ्तार ने दुनिया का ध्यान खींचा है। 2016 में 500 से शुरू हुई यह गिनती आज 1.59 लाख तक पहुंच चुकी है और 115 यूनिकॉर्न तैयार हो चुके हैं। लेकिन यह चमक एक गहरे संकट को भी जन्म दे रही है। छोटे व्यापारी दबाव में हैं, कर रियायतों और जीएसटी की हानि से सरकार का खजाना प्रभावित हो रहा है और निवेशकों के दबाव में कई स्टार्टअप्स आक्रामक मूल्यांकन की ओर बढ़ रहे हैं। क्या यूनिकॉर्न का यह सपना भारतीय व्यापारिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा बन सकता है? सरकार भी संकेत दे रही है कि आने वाले समय में नीतिगत सख्ती देखने को मिल सकती है।

'स्टार्टअप' शब्द अब युवाओं के सपनों के शब्दकोश का हिस्सा बन चुका है। भारत आज वैश्विक स्तर पर स्टार्टअप्स की दौड़ में अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर है। 16 जनवरी 2016 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की शुरुआत के बाद पिछले नौ वर्षों में इनकी संख्या 500 से बढ़कर करीब 1,59,000 हो गई है। रोजगार के मोर्चे पर ये लगभग 17 लाख अवसर उपलब्ध करा चुके हैं। 70 हजार से अधिक स्टार्टअप्स में महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, जो महिला सशक्तिकरण का भी संकेत है। जिन स्टार्टअप्स का वित्तीय मूल्यांकन एक अरब डॉलर से अधिक हो गया, उन्हें 'यूनिकॉर्न' कहा जाता है। आज भारत में 115 यूनिकॉर्न हैं और कई स्टार्टअप्स ने स्टॉक मार्केट में उतरकर खुद को सार्वजनिक कम्पनियों में भी बदला है।

कड़वी सच्चाई... स्टार्टअप्स की शुरुआत समाज की बड़ी समस्याओं को तकनीकी नवाचारों से हल करने के उद्देश्य से होती है। लेकिन धीरे-धीरे इनमें बड़े औद्योगिक घरानों का निवेश बढ़ता है और मुनाफे की होड़ हावी होने लगती है। स्टार्टअप्स मुख्यतः दो स्रोतों से कमाई करते हैं– ग्राहकों के व्यवहार और पसंद-नापसंद से जुड़ा डाटा इकट्ठा करना तथा निवेशकों से वित्तीय निवेश। समय के साथ ये छोटे व्यापारों के लिए बड़ी चुनौती बन जाते हैं, जिससे लघु व्यापारों की आजीविका प्रभावित होती है।

सरकार को आर्थिक नुकसान... स्टार्टअप्स को सरकार ने कर रियायतों के रूप में कई प्रोत्साहन दिए हैं, लेकिन अब इनके तौर-तरीके सरकारी राजस्व को भी प्रभावित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, पहले एक स्थानीय व्यापारी 100 रुपये में कोई उत्पाद बेचता था तो उस पर 18 रुपये जीएसटी लगता था। अब बड़े स्टार्टअप्स वही उत्पाद 50 रुपये में बड़े पैमाने पर खरीदते हैं, जिससे उसका मुनाफा घटता है और सरकार को जीएसटी राजस्व में कमी आती है। छोटे व्यापारों को तकनीकी प्लेटफार्म से जोड़ने के बजाय कई स्टार्टअप्स आज उनसे प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और अपने खुद के रिटेल स्टोर स्थापित कर रहे हैं। वे डिस्काउंट पर उत्पाद बेचकर निवेशकों का नुकसान कर रहे हैं और बाजार में पकड़ बनाने के बाद डिलीवरी चार्ज के रूप में ग्राहकों से अतिरिक्त वसूली कर रहे हैं। यह भारतीय व्यापार परम्परा को कमजोर कर रहा है।

यूनिकॉर्न बनने की होड़

स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बनने का रास्ता पूरी तरह वित्तीय मूल्यांकन पर निर्भर करता है। वित्तीय विशेषज्ञ भी मानते हैं कि मूल्यांकन के लिए पारदर्शी नियम अभी मौजूद नहीं हैं। कुछ वर्ष पहले एक प्रसिद्ध भारतीय स्टार्टअप में चीनी निवेश के बाद उसका मूल्यांकन अचानक बढ़ गया था, जो निवेशकों के हितों को सुरक्षित करने के लिए किया गया था। आईपीओ के बाद कई यूनिकॉर्न के मूल्यांकन में गिरावट देखने को मिली है। यह भी देखा गया है कि सार्वजनिक कम्पनियां बनने के बाद संस्थागत इक्विटी की जगह रिटेल निवेशकों की इक्विटी आ जाती है और स्टार्टअप मालिक समय रहते भारी मुनाफा सुरक्षित कर लेते हैं। शोध और विकास में कम निवेश भी भारतीय स्टार्टअप्स की बड़ी कमजोरी है।

अब बदलाव का संकेत

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का यह बयान कि "भारतीय स्टार्टअप्स ने बेरोजगार युवाओं को सस्ते मजदूरों में बदल दिया है, जो अमीरों के घरों में खाना पहुंचाने की कतार में खड़े हैं", एक सच्चाई को उजागर करता है। बेरोजगार युवाओं के पास सीमित विकल्प हैं, लेकिन यह बयान साफ संकेत देता है कि सरकार अब नीतियों में बदलाव की तैयारी कर रही है। आने वाले समय में स्पेस टेक्नोलॉजी, कृषि क्षेत्र और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों पर सरकार का ध्यान बढ़ेगा। कर प्रोत्साहन और अन्य वित्तीय सुविधाओं से जुड़ी नई नीतियां भी लागू हो सकती हैं।

बचाव से पुनर्वास तकः प्रवासी भारतीयों के लिए भारत की नीति को फिर से सोचने का समय

प्रवासी नहीं पराएः पुनर्वास की जरूरत

हर बार जब विश्व में कोई नया संकट उभरता है, यूक्रेन में युद्ध, गाज़ा में गोलाबारी, या महामारी का कहर, भारत अपने नागरिकों को साहस और समन्वय से निकाल लाता है। ये बचाव अभियान हमारी विदेश नीति की परिपक्वता का प्रमाण हैं। पर क्या हर बार सिर्फ बचा लाना ही पर्याप्त है? लौटे हुए छात्र, श्रमिक और नागरिक, जो जोखिम और अनिश्चितता से जूझकर घर लौटते हैं, क्या उन्हें सिर्फ एक आंकड़ा समझ लिया जाए? यह आलेख एक जरूरी सवाल उठाता हैः क्या भारत को अब एक ऐसी नीति नहीं चाहिए, जो प्रवासियों को केवल बचाए नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक पुनर्वास भी करे? क्योंकि प्रवासी पराए नहीं होते... वे राष्ट्र के ही विस्तार होते हैं।

धीरज श्रीवास्तव
पूर्व आईएएस

बार-बार किए गए बचाव अभियान भारत की परिपक्व होती विदेश नीति को दर्शाते हैं, लेकिन वे प्रवासन प्रबंधन की प्रणालीगत कमजोरियों को भी उजागर करते हैं। हाल के वर्षों में भारत ने संकटग्रस्त देशों से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कई बड़े अभियान चलाए हैं। चाहे वह यूक्रेन में 'ऑपरेशन गंगा' हो, सूडान में 'ऑपरेशन कावेरी', या हाल में इजराइल-गाज़ा जैसे युद्धग्रस्त क्षेत्रों से निकासी। इन अभियानों की तेज़ी और समन्वय की खूब प्रशंसा हुई है। लेकिन यह भी गंभीर सवाल उठाते हैं, आखिर इतनी बड़ी संख्या में भारतीय हर बार संघर्षों के बीच क्यों फंसे मिलते हैं? वे वहां इतनी संख्या में होते ही क्यों हैं और उनकी वापसी हर बार आपात प्रतिक्रिया क्यों होती है? छात्र हों, पेशेवर हों या प्रवासी श्रमिक, आज भारतीय नागरिक वैश्विक अस्थिरता के सामने बेहद असुरक्षित हैं। अब वक्त आ गया है कि भारत केवल बचाव पर केंद्रित सोच से आगे बढ़े और दीर्घकालिक रणनीति अपनाए, जिसमें पुनर्वास, जोखिम न्यूनीकरण और सतत जुड़ाव शामिल हो।

असुरक्षा का व्यापक दायरा

- दुनिया की सबसे बड़ी प्रवासी आबादी भारत के पास है, 1.8 करोड़ से अधिक, लेकिन यह समुदाय एकसमान नहीं है। अमेरिका या यूके में बसे उच्च-शिक्षित एनआरआई पर ध्यान जाता है, लेकिन बड़ी संख्या में भारतीय निम्न या अर्ध-कुशल कामगार के रूप में खाड़ी देशों, पश्चिम एशिया और अफ्रीका में कार्यरत हैं। साथ ही, सस्ती मेडिकल शिक्षा के कारण यूक्रेन, चीन, रूस और अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों में छात्र वर्ग भी लगातार बढ़ रहा है।
- यही वर्ग सबसे अधिक असुरक्षित होता है। वे राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों में रहते हैं, उनके पास मज़बूत कानूनी सुरक्षा नहीं होती, और कई बार अनौपचारिक या शोषणकारी अनुबंधों के तहत काम करते हैं। जब संकट आता है, वो युद्ध हो, अशांति हो या प्राकृतिक आपदा, तो उनके पास सुरक्षा के बहुत कम साधन होते हैं।

कोविड-19 : एक भूला सामूहिक पलायन

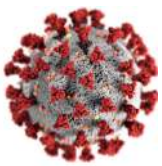

युद्ध या संघर्ष की परिस्थितियों से पहले, भारत ने कोविड-19 के दौरान एक अपूर्व पलायन देखा था। लगभग 1.8 करोड़ भारतीयों ने न केवल विदेशों से, बल्कि भारत के बड़े शहरों से भी अपने राज्यों में वापसी की। प्रवासी श्रमिकों के हजारों किलोमीटर पैदल लौटने से लेकर वंदे भारत मिशन के चार्टर्ड विमानों तक। यह केवल एक लॉजिस्टिक चुनौती नहीं थी, बल्कि यह एक सामाजिक झटका भी था। फिर भी, उस वापसी की नीति-निर्माण में कहीं चर्चा नहीं होती। न उनके कौशल का आकलन हुआ, न उन्हें पुनः समायोजित करने की कोई राष्ट्रीय रणनीति बनी। वे या तो फिर अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में खो गए, या परिस्थितियां सामान्य होते ही वापस विदेश जाने की राह देखने लगे।

प्रतीकात्मकता नहीं, ठोस नीति चाहिए

भारत के बचाव अभियान सराहनीय हैं, लेकिन वे स्थायी नीति का विकल्प नहीं बन सकते। हमें अब इन नीतिगत पहलों की ज़रूरत है:

1. जोखिमग्रस्त भारतीयों की पहचान व मानचित्रण

▪ भारतीय मिशनों, श्रम मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के समन्वय से उन भारतीयों का डेटा तैयार होना चाहिए जो संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में हैं, विशेषकर श्रमिक और छात्र।

2. वापसी के बाद पुनर्वास को संस्थागत रूप दें

▪ संकट से लौटे नागरिकों के पास न काम होता है, न मानसिक संतुलन, और अक्सर कर्ज़ में डूबे होते हैं। एक राष्ट्रीय योजना होनी चाहिए, जिसमें मनो-सामाजिक परामर्श, स्किल मैपिंग, नौकरी मिलान, और अल्पकालिक वित्तीय सहयोग हो।

3. द्विपक्षीय श्रम समझौतों को मज़बूत करें

▪ भारत से श्रमिकों का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक माध्यमों से विदेश जाता है। भारत को औपचारिक समझौतों को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें बीमा, सुरक्षा प्रावधान और आपात स्थिति में निकासी की व्यवस्था हो।

4. विदेश में पढ़ रहे छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित हो

▪ सस्ती शिक्षा का मतलब असुरक्षित शिक्षा नहीं होना चाहिए। भारत को विदेशों में संस्थानों की गुणवत्ता, सुरक्षा और छात्र कल्याण की निगरानी करनी चाहिए।

5. प्रवासी नीति में हाशिए के लोगों को शामिल करें

▪ अक्सर प्रवासी नीति केवल सफल एनआरआई या उद्योगपतियों को केंद्र में रखती है। लेकिन असली प्रवासी चेहरे हैं— इज़राइल में नर्सें, दुबई में राजमिस्त्री, खारकीव में छात्र और बेरूत में ड्राइवर। नीति में इस विविधता की झलक होनी चाहिए।

मिशन समर्थ की शुरुआत जरूरी

भारत को केवल बचाव नहीं, बल्कि दीर्घकालिक प्रवासन नीति की ज़रूरत है। 'मिशन समर्थ' एक राष्ट्रीय पहल के रूप में शुरू किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य कुशल भारतीयों को आकर्षित करना, बनाए रखना और पुनः एकीकृत करना हो। यह मिशन स्टार्टअप इंडिया या स्किल इंडिया की तरह हो और प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में संचालित हो।

ये शामिल हो सकते हैं

रिटर्नी पोर्टल • एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जहां लौटे भारतीयों को नौकरी मिलान, दस्तावेज़ मान्यता, कर सलाह, और आवास सहायता मिले।

रिवर्स टैलेंट फेलोशिप्स • भारतीय मूल के वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और नीति विशेषज्ञों के लिए संरचित कार्यक्रम, जो उन्हें 3-5 वर्षों के लिए भारत में काम करने का अवसर दें।

वैश्विक गतिशीलता कार्यबल • विदेश मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, राज्य सरकारों और प्रवासी नेटवर्क के समन्वय से एक टास्क फोर्स।

सरकारी तंत्र के बाहर के विशेषज्ञों को शामिल करें • सिविल सोसायटी, शिक्षाविद्, पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह और प्रवासी संगठनों से जुड़े लोगों को भी निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

पुनर्वास = राष्ट्र निर्माण

• **जो लाखों** भारतीय संकट में लौटते हैं, वे केवल समस्याएं नहीं, बल्कि कौशल, अनुभव और आकांक्षाएं लेकर लौटते हैं। उन्हें नजरअंदाज करना केवल उनकी नहीं, भारत के विकास की भी हानि है। यह कल्याण नहीं, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है।

समन्वित नीति की आवश्यकता

• **प्रवासन नीति** को केवल विदेश मंत्रालय या श्रम मंत्रालय के सीमित दायरे से बाहर लाना होगा। नीति आयोग की निगरानी में एक अंतर-मंत्रालयीय टास्क फोर्स बननी चाहिए जो राज्यों, उद्योगों और सिविल सोसायटी के साथ मिलकर समेकित रणनीति बनाए।

"हर बार जब कोई वैश्विक संकट आता है, भारत अपने नागरिकों को निकालता है। लेकिन इन सुर्खियों के पीछे एक गहरी नीतिगत खामोशी है- अनियंत्रित प्रवासन, लौटे नागरिकों को लेकर सरकारी उदासीनता, और यह मान्यता कि वे लौटे हैं, तो अस्थायी मेहमान हैं। लेकिन भारत के लोग, चाहे वे मजबूरी में जाएं या महत्वाकांक्षा में, अगर लौटते हैं, तो वे केवल सहायता नहीं, सम्मान और पुनर्वास के भी हकदार हैं।

स्वरोजगार, महिला स्व-सहायता समूह और पंचायत राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका

रेत की रेखाओं से खींची नई लकीरें

कभी चौखट तक सीमित मानी जाने वाली महिलाएं आज पंचायत से लेकर प्रबंधन तक में अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज करवा रही हैं। ये महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही हैं, बल्कि गांव की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दिशा भी बदल रही हैं। चाहे बात स्वरोजगार की हो या स्थानीय नेतृत्व की—राजस्थान की ये ग्रामीण महिलाएं अब सिर्फ भूमिका नहीं निभा रहीं, बदलाव की मुख्य धुरी बन चुकी हैं।

मधु बनर्जी
पत्रकार व लेखिका

राजस्थान की मिट्टी में सिर्फ रेत के टीले नहीं, संघर्ष और सशक्तिकरण की कहानियां भी गहराई से दबी हैं। एक समय था जब ग्रामीण महिलाएं परम्पराओं की बेड़ियों में जकड़ी हुई थीं, लेकिन आज वे इन्हीं परम्पराओं को चुनौती देती हुई नए सामाजिक प्रतिमान रच रही हैं। सिलाई, बुनाई, कृषि, दुग्ध उत्पादन, पंचायती नेतृत्व से लेकर डिजिटल साक्षरता तक, इन महिलाओं ने अपने सामर्थ्य से सिद्ध कर दिया है कि बदलाव केवल शहरों से नहीं आता, गांव की गली से भी क्रांति जन्म ले सकती है। रेतीली धरती पर जब कोई महिला आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाती है, तो वह अपने साथ- साथ पूरे गांव और समाज की दिशा का रुख भी बदल देती है। यह बदलाव केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और मानसिक चेतना का परिचायक है।

वह समय अब काफी पीछे छूटता जा रहा है, जब ग्रामीण महिला का कार्यक्षेत्र केवल घर-आंगन तक सीमित था। लेकिन अब वह खेती से लेकर हस्तशिल्प, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्राम शासन तक में निर्णायक भूमिका निभा रही है। राजस्थान के गांवों में यह बदलाव न केवल महिला सशक्तिकरण की मिसाल है, बल्कि एक नया सामाजिक विमर्श भी गढ़ रहा है, जिसमें नारी अब 'दया की पात्र' नहीं, बल्कि 'निर्णय की धुरी' बन रही है।

स्वरोजगार की नई राहें

- राजस्थान के कई जिलों में महिलाएं पारम्परिक शिल्प और घरेलू उत्पादों को व्यावसायिक रूप देकर स्वरोजगार की मिसाल पेश कर रही हैं। जयपुर, जोधपुर, बाड़मेर, बांसवाड़ा और उदयपुर जैसे इलाकों में महिलाएं आज मनरेगा से लेकर डेयरी फार्मिंग, जैविक खेती, बुटीक, मसाला उद्योग, पापड़-अचार निर्माण और यहां तक कि ऑनलाइन सेलिंग में भी भागीदारी निभा रही हैं।
- बाड़मेर की महिला बुनकरों द्वारा बनाए गए ऊनी शॉल और कालीन देश-विदेश में सराहे जा रहे हैं। वहीं उदयपुर की आदिवासी महिलाएं अपने परम्परागत जंगल उत्पादों को स्थानीय बाजारों तक पहुंचाकर आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं।

स्वयं सहायता समूह

- महिला स्वयं सहायता समूह ने राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं के जीवन को नई दिशा दी है। ये समूह महिलाओं को आपसी सहयोग से बचत करने, ऋण लेने, उत्पादन कार्य शुरू करने और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रशिक्षण देते हैं।
- राजीविका योजना के तहत गठित हजारों एसएचजी आज लाखों महिलाओं के जीवन में बदलाव ला चुके हैं। अकेले जोधपुर जिले में हजारों महिलाएं विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर परचून, सिलाई, फूड प्रोसेसिंग और हस्तकला जैसे कामों से सालाना लाखों की आमदनी अर्जित कर रही हैं।

पंचायत राजनीति में भागीदारी

- 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को मिले आरक्षण ने राजस्थान में सत्ता के समीकरण बदल दिए हैं। अब महिलाएं केवल नाम भर की सरपंच नहीं रहीं, बल्कि नीतिगत निर्णयों में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। 'सरपंच पति' की छवि को तोड़ते हुए अब महिलाएं खुद फील्ड में जाकर स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, पेयजल योजनाओं, सड़कों और विकास कार्यों की निगरानी कर रही हैं। जैसलमेर की सरपंच जेस्सी देवी, टोंक की अनिता मीणा, और चूरू की रुबीना खातून जैसी महिलाओं ने अपने नेतृत्व से यह साबित कर दिया है कि राजनीतिक मंच अब केवल पुरुषों का एकाधिकार नहीं रहा।

तकनीक से मिली नई दृष्टि

- आज ग्रामीण महिलाएं न केवल साक्षर हो रही हैं, बल्कि डिजिटल दुनिया से जुड़कर शासन और बाजार से सीधा संवाद स्थापित कर रही हैं। ई-मित्र, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल ट्रेनिंग, यूपीआई पेमेंट और सोशल मीडिया के ज़रिए वे अपने उत्पाद बेच रही हैं और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी ले रही हैं।
- 'दिग्गज दादी' जैसे उदाहरण, जो अपने फोन से ऑर्डर बुक करती हैं या ऑनलाइन बुटीक चलाती हैं, यह साबित करते हैं कि तकनीक ने गांव की महिला को नई दृष्टि दी है।

चुनौतियां अभी बाकी हैं... हालांकि ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, पर अब भी कई चुनौतियां कायम हैं, जैसे पारिवारिक विरोध, संसाधनों की कमी, वित्तीय सहायता की जटिलता, लैंगिक असमानता और सामाजिक रूढ़ियां। इसके अलावा, कई बार महिलाएं प्रतिनिधि तो बन जाती हैं, लेकिन पुरुष निर्णयों में हस्तक्षेप करते हैं।

गांव की शक्ति ही देश की असल शक्ति

- राजस्थान सरकार की कई योजनाएं जैसे राजीविका योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, भामाशाह योजना, सखी योजना, और महिला स्वरोजगार योजना ने महिलाओं को आर्थिक, तकनीकी और सामाजिक रूप से मजबूत बनाने का प्रयास किया है। इन योजनाओं का सही क्रियान्वयन और निगरानी ही बदलाव की स्थायित्व की गारंटी बन सकता है। राजस्थान की ग्रामीण महिलाएं अब सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं हैं। वे सुई से लेकर संविधान तक, हर स्तर पर बदलाव की वाहक बन चुकी हैं। उनकी मेहनत, एकजुटता और आत्मबल ने यह दिखा दिया है कि गांव की शक्ति ही असल में देश की शक्ति है।
- अब समय आ गया है कि हम सिर्फ "नारी सशक्तिकरण" की बात न करें, बल्कि "नारी नेतृत्व" को पहचानें, स्वीकारें और सम्मान दें। राजस्थान का भविष्य उन गांवों से निकलेगा, जहां महिलाएं केवल चूल्हा नहीं जलातीं, बल्कि समाज को दिशा देने वाली मशाल भी बन चुकी हैं।

स्वयं सहायता समूह में महिलाएं

- राजस्थान में लगभग 3.2 लाख स्वयं सहायता समूह सक्रिय हैं (राजीविका योजना के अंतर्गत), जिनसे 40 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं।
- अकेले जोधपुर ज़िले में 25,000 से अधिक एसएचजी कार्यरत हैं, जो कृषि, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, सिलाई, वाणिज्य आदि में सक्रिय हैं।

मनरेगा में महिला भागीदारी

- राजस्थान में मनरेगा के तहत कुल कार्यदिवसों का लगभग 55 प्रतिशत कार्य महिलाओं द्वारा किया गया, जो राष्ट्रीय औसत (50 प्रतिशत) से अधिक है।

राजस्थान में पंचायती राज में महिला प्रतिनिधित्व

- 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू होने के बाद,
- 33,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में महिलाएं निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।
- राज्य में 60 प्रतिशत से अधिक सरपंच पदों पर अब महिलाएं काबिज हैं, जिनमें अनुसूचित जाति, जनजाति और मुस्लिम वर्ग की महिलाएं भी बड़ी संख्या में हैं।

महिला उद्यमिता और कौशल विकास

- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और भामाशाह योजना के तहत 2019-2024 के बीच 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण और प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- "सखी" योजना के तहत राजस्थान के 33 जिलों में डिजिटल साक्षरता शिविरों के माध्यम से 1.2 लाख महिलाओं को डिजिटल ट्रेनिंग दी गई।

महिलाओं की तकनीकी में भागीदारी

- ई-मित्र पोर्टल से जुड़ने वाली महिलाओं की संख्या में पिछले 5 वर्षों में 220 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
- 60 प्रतिशत महिला वेंडर्स अब मोबाइल बैंकिंग और UPI पेमेंट का इस्तेमाल कर रही हैं (विशेषकर शहरी-ग्रामीण सीमा क्षेत्रों में)।

झुर्रियों का डर, इंजेक्शन का जादू: क्या वाकई है ये फॉर्मूला ऑफ यंग?

झुर्रियां अनुभव तो मुस्कान सबसे बड़ा ब्यूटी ट्रीटमेंट

मधुलिका सिंह
पत्रकार व लेखिका

बाहरी देखादेखी में अगर आप भी सौंदर्य प्रक्रिया करवा रहे हैं, तो यह आपकी चॉइस है। लेकिन यह चॉइस सोच-समझकर, पूरी जानकारी के साथ और डॉक्टर की निगरानी में होगी तो ही ठीक है। वरना यह 'सुंदरता' आपको स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों से दूर कर सकती है। ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि झुर्रियां अगर अनुभव की लकीरें हैं, तो मुस्कान सबसे बड़ा ब्यूटी ट्रीटमेंट।

एक समय था जब चेहरे की झुर्रियां अनुभव का प्रतीक मानी जाती थीं। लेकिन अब, सोशल मीडिया की दुनिया में हर कोई 'युवा' दिखने की चाह में दौड़ा चला जा रहा है। इंस्टाग्राम फिल्टर्स की चमक और 'फ्लॉलेस स्किन' के दबाव ने एक नई इंडस्ट्री को जन्म दिया है— एंटी-एजिंग और कॉस्मेटिक सर्जरी की इंडस्ट्री। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग अब अपने चेहरे और शरीर को 'फिक्स' करने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं।

ऐसे शुरू हुआ ट्रेंड

- एंटी-एजिंग की शुरुआत कोई नई नहीं है। मिस्र की रानी क्लियोपेट्रा गधे के दूध से स्नान करती थीं, ताकि त्वचा को जवां बनाए रखा जा सके। लेकिन मॉडर्न एरा में इस ट्रेंड को असली पंख 1990 के दशक में तब मिले, जब हॉलीवुड और बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने कैमरे के सामने 'परफेक्ट लुक' के लिए बोटॉक्स और फेसलिफ्ट्स को अपनाया।
- भारत में यह ट्रेंड 2000 के बाद तेजी से बढ़ा, और 2015 के बाद इंस्टाग्राम और सेल्फी कल्चर के साथ तो ये एक बिजनेस इंडस्ट्री बन गया। आज भारत एशिया के टॉप 5 कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट बाजार में से एक है।

कोरियन ब्यूटी ट्रेंड्स की चमक और भारतीय दीवानगी

हाल के वर्षों में कोरियन ब्यूटी यानी 'के ब्यूटी' ट्रेंड्स ने भारतीय युवाओं पर गहरा प्रभाव डाला है। ग्लास स्किन, डबल क्लेंजिंग, मल्टी-स्टेप स्किनकेयर रूटीन और बीबी/सीसी क्रीम जैसे ट्रेंड्स अब भारतीय मार्केट में आम हो चुके हैं। 'के ड्रामा' और 'के पॉप सितारों' की बेदाग और चमकती त्वचा को देखकर भारतीय युवा उसी 'परफेक्ट' लुक की चाह में महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ट्रीटमेंट्स और सर्जरी तक का सहारा लेने लगे हैं। ऑनलाइन ब्यूटी रिटेलर्स के अनुसार, 'के-ब्यूटी' से प्रेरित प्रोडक्ट्स की बिक्री भारत में हर साल 30 फीसदी से अधिक की दर से बढ़ रही है।

इस इंडस्ट्री का साइज और खर्च

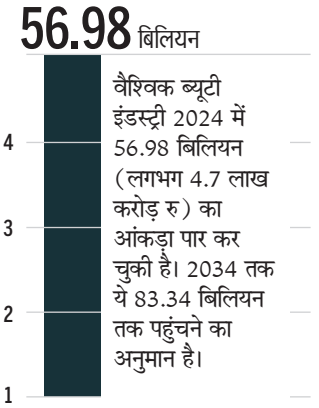

वैश्विक ब्यूटी इंडस्ट्री 2024 में 56.98 बिलियन (लगभग 4.7 लाख करोड़ रु) का आंकड़ा पार कर चुकी है। 2034 तक ये 83.34 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।

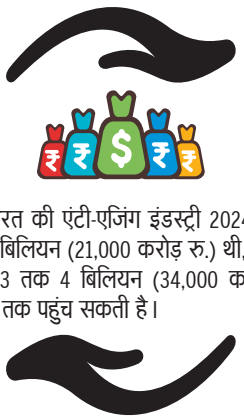

- भारत की एंटी-एजिंग इंडस्ट्री 2024 में 2.5 बिलियन (21,000 करोड़ रु.) थी, जो 2033 तक 4 बिलियन (34,000 करोड़ रु.) तक पहुंच सकती है।

कौन-कौन सी प्रक्रियाएं हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर?

प्रक्रिया	लागत (भारत)	प्रभाव की अवधि	जोखिम
बोटॉक्स इंजेक्शन	15,000–30,000	5–6 महीने	सूजन, मांसपेशियों में अकड़न
फिलर इंजेक्शन	18,000–45,000	6–18 महीने	गांठ
फेसलिफ्ट	1 लाख–3 लाख	5–10 साल	स्कार, सुन्न त्वचा
लेज़र हेयर रिमूवल	20,000–50,000	(6 सत्रों के लिए)	स्थायी जलन, रंग में अंतर
स्किन टाइटनिंग	25,000–60,000	1–2 साल	त्वचा में झनझनाहट

क्यों ले रहे हैं लोग इतने जोखिम?

कई हॉलीवुड, बॉलीवुड सितारे और कई अन्य सेलिब्रिटी ऐसे ट्रीटमेंट कराते रहते हैं। इनसे प्रेरित होकर आम लोग भी अब यह सोचते हैं कि अगर सेलेब्रिटी ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? लेकिन इस 'युवा दिखने की होड़' में कई लोग जान तक गंवा रहे हैं। शेफाली जरीवाला की हालिया असामयिक मौत के पीछे ग्लूटाथियोन इंजेक्शन जैसे अनप्रूव्ड एंटी-एजिंग इंजेक्शन को लेकर सवाल उठे हैं। ऐसे इंजेक्शन्स पर भारत में पूरी तरह से रोक नहीं है, और कई सैलून में बिना डॉक्टरी निगरानी के ये दवाइयां दी जा रही हैं।

सोशल मीडिया का दबाव और आकर्षक दिखने की चाह

इंस्टाग्राम फेस (चिकनी त्वचा, मोटे होंठ, बिल्लीनुमा आंखें) अब एक आदर्श बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक पर 'फिल्टर-संस्कृति' ने लोगों को असलियत से दूर कर दिया है। अब हर कोई आकर्षक दिखने की इस डिजिटल दौड़ में शामिल होना चाहता है। 95 प्रतिशत से ज़्यादा लोकप्रिय इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स फेसट्यून या बोटॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब 17 साल का कोई लड़का या लड़की इन्हीं चेहरों को देखता है, तो उसे अपनी स्किन 'नॉर्मल' नहीं लगती।

मनोवैज्ञानिक प्रभाव

- बाहर से खूबसूरत दिखने की चाह भीतर की बेचैनी को छुपा नहीं सकती। कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के बाद कुछ में आत्मविश्वास जरूर बढ़ता है, लेकिन कई बार यह खुशी अस्थायी साबित होती है। जो लोग पहले से ही अपने शरीर या चेहरे को लेकर असंतुष्ट होते हैं, उनके लिए यह प्रक्रियाएं कभी-कभी 'संतोष का झांसा' बन जाती हैं। उनमें असमर्थता की भावना और गहराई से बैठ जाती है।
- बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर (बीडीडी) जैसी मानसिक स्थितियों में व्यक्ति को अपने रूप में बार-बार खामी नजर आती है, चाहे वह दुनिया की नजर में सुंदर ही क्यों न हो। ऐसे लोग बार-बार सर्जरी कराते हैं, लेकिन फिर भी आत्मसंतुष्ट नहीं हो पाते।
- मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब व्यक्ति का आत्म-मूल्य केवल लुक्स पर आधारित हो जाता है, तो उसके असफल होने की आशंका बढ़ जाती है। यह लगातार तुलना, असंतोष और आत्म-अस्वीकार जैसी मानसिक चुनौतियों को जन्म देता है, जिससे डिप्रेशन और एंग्जायटी भी हो सकती है।

चेहरा आपका, चॉइस भी आपकी... अगर आप सौंदर्य प्रक्रिया करवा रहे हैं, तो यह आपकी चॉइस है। लेकिन यह चॉइस सोच-समझकर, जानकारी के साथ और डॉक्टर की निगरानी में होनी चाहिए। वरना यह 'सुंदरता' आपको स्वास्थ्य और मानसिक शांति दोनों से दूर कर सकती है। झुर्रियां अगर अनुभव की लकीरें हैं, तो मुस्कान सबसे बड़ा ब्यूटी ट्रीटमेंट।

संसाधन जीवन को सुविधाजनक बना सकते हैं, लेकिन सच्ची प्रगति के लिए आत्मा का विकास जरूरी

प्रगति का असली पैमाना 'भौतिकता से परे आध्यात्मिकता'

डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी
सहायक निदेशक, बीएपीएस स्वामीनारायण अनुसंधान संस्थान, अक्षरधाम, नई दिल्ली

आज की दुनिया में बड़ी गाड़ी, आलीशान मकान और विदेशी यात्राएं ही सफलता का प्रतीक मानी जाने लगी हैं। लेकिन इतिहास और वर्तमान यह बताते हैं कि भौतिक संपत्ति के बावजूद मानसिक शांति का अभाव जीवन को अधूरा बना देता है। गुरु नानक जी, डॉ. राधाकृष्णन और प्रमुख स्वामी महाराज जैसे महापुरुषों ने स्पष्ट कहा कि अध्यात्म के बिना बाकी उपलब्धियां भी अंततः शून्य हो जाती हैं। डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक भी मानते थे कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आध्यात्मिकता और ईश्वर में आस्था को विकास के मूल में रखना जरूरी है।

आज की तेज़ दौड़ती दुनिया में धन, संपत्ति और भौतिक सुख-सुविधाएं ही सफलता का मुख्य मापदंड मानी जा रही हैं। जिसे जितनी बड़ी गाड़ी, महंगा बंगला या विदेशी दौरे हैं, वह उतना ही 'प्रगतिशील' कहलाता है। आर्थिक वृद्धि और तकनीकी विकास को ही 'समृद्धि' का पर्याय मान लिया गया है। पर क्या यह सच है..?

सन 1923, शिकागो। एडवाटर बीच होटल में बैठक के लिए नौ व्यक्ति एकत्र हुए। इन नौ व्यक्तियों में 'विश्व के सबसे सफल वित्तीय महारथियों, जिन्होंने धन के बल पर लगभग पूरी दुनिया को नियंत्रित किया'', वे दुनिया के सबसे सफल पूंजीपति और निवेशक थे। अपार संपत्ति के धनी ये नौ व्यक्ति उस समय दुनिया पर राज कर रहे थे।'

ग्लेन ब्लैंड नाम के एक लेखक ने अपनी पुस्तक 'सक्सेस' में इस घटना का उल्लेख किया है। इन नौ व्यक्तियों के जीवन के उत्तरार्ध जीवन की जांच से पता चला कि 25 साल बाद, इन नौ व्यक्तियों में से तीन ने आत्महत्या की, 2 लोग जैल में थे और तीन दिवालिया हो गए थे।

आप भी ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो कभी अपने क्षेत्र में बेताज बादशाह थे, लेकिन जल्द ही असफलता के गर्त में गिरे और फिर विलीन हो गए।

यहां स्वाभाविक रूप से एक प्रश्न उठता है कि उनके विनाश का कारण क्या था? शिक्षा, सत्ता और धन के शीर्ष पर बैठे इन प्रभावशाली लोगों के जीवन में क्या कमी थी? असीमित संसाधनों का अनवरत योग करने वालों का योगफल शून्य क्यों हुआ? केवल भौतिक संपत्ति, साधनों, सुविधाओं को प्रगति का आधार मानने वाले अंततः निराश तथा निःशेष क्यों होते जा रहे हैं? तो आखिर क्या है प्रगति का सच्चा पैमाना?

अध्यात्म के बिना सब शून्य

इस प्रश्न के उत्तर में मध्यकालीन संत गुरु नानकजी कहते हैं-

राम नाम एक अंक है, सब साधन है शून्य;
एक गए सब गए, एक रहे दस गुन;

- इस पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार एक अंक के बिना शून्य का कोई मूल्य नहीं है, उसी प्रकार अध्यात्म के बिना अन्य साधन भी अर्थविहीन हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राधाकृष्णन कहते हैं- "हमारी प्रगति की आत्मा हमारी आत्मा की प्रगति है", आध्यात्मिक विकास ही सच्चा विकास है।
- इन महापुरुषों, विचारकों या कवियों का प्रगति के साधन या उपकरणों से कोई विरोध नहीं है। पर हां, उनका मत है कि ये साधन-उपकरण भी मूल्यवान होंगे, यदि इन्हें आध्यात्मिकता के साथ जोड़ दिया जाए।

कलाम और प्रमुख स्वामी महाराज का संवाद : छठा बिंदु – आध्यात्मिकता

भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए विश्व प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक और खगोलशास्त्री अब्दुल कलाम के नेतृत्व में देश के 500 बुद्धिजीवियों ने एक साथ विचार-विमर्श और अनुसंधान करके विकास के पांच क्षेत्रों को निश्चित किया। कलाम साहब इस विषय को लेकर 30 जून 2001 को दिल्ली में स्वामी महाराज से मिलने पहुंचे। कलाम ने देश के विकास के पांच बिन्दुओं को स्वामीजी के समक्ष रखा- 1. शिक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा, 2. कृषि और संबंधित क्षेत्र, 3. सूचना और संचार, 4. बुनियादी ढांचा (इंफ्रास्ट्रक्चर) और 5. महत्त्वपूर्ण तकनीकी संरचना। उनकी बात सुनकर प्रमुख स्वामी महाराज ने तुरंत कहा, "पांच बिंदुओं के साथ छठा बिंदु जोड़ें- ईश्वर में श्रद्धा और आध्यात्मिकता। इससे ही ऐसे योग्य नागरिक तैयार होंगे जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देंगे। आध्यात्मिक धन जितना मजबूत होगा, उतना ही यह सांसारिक धन उसके साथ आएगा।"

कलाम ने कहा, "श्रेष्ठ नागरिक केवल सरकारी नियमों से नहीं बनते, यह तो आप जैसे संतों के आशीर्वाद से ही बनते हैं, आपके द्वारा निर्मित अक्षरधाम जैसे संस्कार केन्द्रों को देखकर ऐसा लगता है कि आप प्रतिवर्ष एक लाख संस्कारी युवा तैयार कर सकते हैं।"

श्रेष्ठ नागरिक निर्माण का आधार : संस्कार और सद्गुण

स्वामी महाराज ने अपनी कीर्ति और प्रशंसा के पुष्पों को गुरु योगीजी महाराज के चरणों में अर्पण करते हुए बताया, "हमारे गुरु कहते थे कि संस्कार और सद्गुणों को बाल-मानस में ही दृढ़ करवाकर एक पूर्ण विकसित राष्ट्र की नींव रखी जा सकती है।"

कलाम साहब ने भी इस मार्गदर्शन को सहर्ष स्वीकार कर लिया और फिर आगे पूछा, "पहले लोगों को धार्मिक बनाकर काम शुरू करना चाहिए या फिर दोनों कार्य समानांतर करें?" स्वामीजी ने कहा, "दोनों समानांतर करें, विकास के कार्य को जारी रखना आवश्यक है। परा और अपरा विद्या दोनों को स्वीकार कर हमारी संस्कृति ने विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।"

खोजबीन व विश्लेषण में डिजिटल औजारों पर बढ़ी निर्भरता

AI से धारदार हो रहे जासूसी औजार

प्रो. (डॉ.) सचिन बत्रा
वरिष्ठ पत्रकार

हमारे देश में भी अब बहुत खामोशी से भ्रष्टाचार पर नकेल डालने के लिए एल्गोरिदम और AI आधारित डिजिटल जासूस और डिटेक्टिव टूल अपनी धार तेज करते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए 'आइ—रश' नामक एप सरकारी योजनाओं की निगरानी करता है। वहीं 'विजिलेंस एप' के माध्यम से जनता भ्रष्टाचार के मामलों को रिपोर्ट कर सकती है। इसी प्रकार 'ओजीडीपी' यानी ओपन गवर्नमेंट डाटा प्लेटफार्म सरकारी डाटा की निगरानी करते हुए असामान्य गतिविधियों की पहचान करता है।

AI यानी कृत्रिम मेधा के इस दौर में खोजबीन, पड़ताल, विश्लेषण और आकलन के लिए डिजिटल औजारों पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। इसका कारण है कि एक तरफ कम लागत के लाभ और दूसरी ओर सीमित समय में परिणाम प्राप्त किए जा रहे हैं। लिहाजा अब तो भ्रष्टाचार को भांपने के लिए पूरी दुनिया में AI औजारों का उपयोग और खोज चरम पर है। दिलचस्प बात यह है कि भ्रष्टाचार को चिन्हित करने से लेकर सबूत हासिल करने में भी AI अपनी डिटेक्टिव भूमिका का निर्वाह कर रही है, जिससे जन के धन का दुरुपयोग पाबंद करते हुए सुशासन व पारदर्शिता के लक्ष्य हासिल किए जाने लगे हैं।

वैश्विक स्तर पर भ्रष्टाचार को भंग करने के लिए कदम उठाना, एक ओर साहस तो दूसरी ओर मजबूरी बनती जा रही है। इसका मुख्य कारण प्रक्रियाओं का लगातार ऑनलाइन होना है। जर्मनी में वित्त संबंधी धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले उजागर करने के लिए 'हॉक' AI नामक टूल विकसित किया है। पेरू की सरकार ने सार्वजनिक खरीद की अनियमितताओं की पहचान करने के लिए 'प्रोक्योर नेट' औजार ईजाद किया है। इसी प्रकार अफ्रीकी देशों में भ्रष्टाचार की शिकायतों की निगरानी और विश्लेषण के लिए 'इंटिग्रिटी वॉच' एप का उपयोग किया जा रहा है। ऐसे ही मनी लॉन्ड्रिंग का पता लगाने सहित वित्तीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सिंगापुर के बैंक 'साइलेंट ऐट' AI का सफल इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं न्यूजीलैंड में धन संबंधी धांधली की शिनाख्त के लिए 'वीका' नामक डेटा माइनिंग टूल बहुत उपयोगी साबित हो रहा है। इसी तरह अमेरिका में सरकारी स्तर पर अनुबंधों में अनियमितता या धोखेबाजी को चिन्हित करने के लिए 'पोलरिस AI' बहुत कारगर माना गया है। ऐसे ही यूक्रेन में एंटी करप्शन एक्शन सेंटर ने 'प्रो—जोरो' नामक AI संचालित टूल के जरिए सरकारी अधिकारियों ही नहीं, जनता को भी फर्जीवाड़े व संभावित अनियमितताओं की अग्रिम चेतावनी देना शुरू कर दिया है। मजेदार बात तो यह है कि ब्राजील में तो विविध परियोजनाओं में भ्रष्टाचार के जोखिम को जानने और उसकी मैपिंग के लिए 'करप्शन रिस्क मैप' नामक AI औजार को तो हेराफेरी की भविष्यवाणी करने वाला सार्थक ज्योतिषी माना जा रहा है।

सरकारी योजनाओं पर 'आइ—रश' से निगरानी

यही नहीं हमारे देश में भी अब बहुत खामोशी से भ्रष्टाचार पर नकेल डालने के लिए एल्गोरिदम और AI आधारित डिजिटल जासूस और डिटेक्टिव टूल अपनी धार तेज करते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए 'आइ—रश' नामक एप सरकारी योजनाओं की निगरानी करता है। वहीं 'विजिलेंस एप' के माध्यम से जनता भ्रष्टाचार के मामलों को रिपोर्ट कर सकती है। इसी प्रकार 'ओजीडीपी' यानी ओपन गवर्नमेंट डाटा प्लेटफार्म सरकारी डाटा की निगरानी करते हुए असामान्य गतिविधियों की पहचान करता है। दूसरी ओर 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' इंडिया नामक संगठन भ्रष्टाचार के विविध पहलुओं का अध्ययन और पहचान करते हुए उसका समाधान मुहैया कराने सहित AI उपकरण विकसित करता है। ऐसे ही स्टेक्यू टेक्नोलॉजी नामक कंपनी ने 'क्राइम जीपीटी' नामक एक AI टूल तैयार किया है, जो पुलिस के लिए भ्रष्टाचार के मामलों की जांच में बहुत सहयोगी माना जाता है। उल्लेखनीय है कि इसका सफल इस्तेमाल जी—20 सम्मेलन के दौरान किया गया था। इससे पुलिस को साक्ष्य जुटाने में भी मदद मिली थी। हालांकि यह सच है कि एंटी—करप्शन के मामले बहुत पेचीदा होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस, 'प्रिडिक्टिव पोलिसिंग AI' औजार के माध्यम से वित्तीय प्रक्रियाओं का विश्लेषण करते हुए भ्रष्टाचार के मामलों की पहचान कर रही है। यही नहीं, इन नवविकसित औजारों की मदद से अदालतों में अपराधियों के खिलाफ साक्ष्य पेश करना भी अब संभव हो गया है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने आधार डाटा एनालिसिस में एल्गोरिदम AI का उपयोग कर भ्रष्टाचार ही नहीं, नकली लाभार्थियों की पहचान करते हुए फर्जीवाड़े रोकने के सराहनीय प्रयास किए हैं। उधर तेलंगाना सरकार भी 'टी—स्केन' AI टूल का उपयोग करते हुए सरकारी विभागों में वित्तीय अनियमितताओं और संदिग्ध गतिविधियों को बेनकाब करते हुए गबन और घपलेबाजी की रोकथाम करने में जुटी है।

गबन के जटिल मामले सुलझाना आसान

दुनिया भर के विशेषज्ञों की माने तो अब धन गबन के जटिल मामले भी AI की मदद से सुलझाना बेहद आसान हो गया है। एक बहुत ही रोचक उदाहरण पेरू के समाचार संस्थान 'ओजो पब्लिको' का है, जिसके विकसित किए गए 'फ्यून' नामक एल्गोरिदम आधारित औजार ने ढाई लाख पब्लिक कांट्रेक्ट की जांच करते हुए भ्रष्टाचार के खतरे का प्रतिशत भी बताया और मामले भी उजागर किए। इसे वर्ष 2020 में श्रेष्ठ नवाचार की श्रेणी में सिग्मा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार आइसीआइजे यानी इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टीगेटिव जर्नलिस्टस ने AI की मदद से लाखों दस्तावेजों की जांच करते हुए बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा करते हुए पनामा पेपर्स और पापर पेपर्स जैसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। इसके चलते अब भ्रष्टाचार की पड़ताल के लिए AI समाधानों की मांग भी बढ़ती जा रही है। लिहाजा औजार ईजाद करके समाधान सुलभ कराने का एक नया कारोबार करवट ले रहा है। दुनिया भर में ग्लोबल इंटीग्रिटी, ग्लोबल विट्नेस, सनलाइट फाउंडेशन, द इन्वेस्टिगेटिव फंड और स्टेक्यू टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां भ्रष्टाचार के विरुद्ध औजार बनाने में जुटी हैं तो दूसरी ओर कई कंपनियां लालफीताशाही और गबन की जांच सुविधा और सेवाएं देने में जुट गई हैं।

कुल मिलाकर मिलीभगत, मुनाफाखोरी, मिलावट और मनमानी के खेल को AI औजार जेल तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। वहीं एल्गोरिथम आधारित डिजिटल औजार सरकारी योजनाओं में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार को चिन्हित करने में सक्षम माने जा रहे हैं। इन AI एप्स के माध्यम से डाटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग, पैटर्न रिकॉग्निशन, एल्गोरिथम डिटेक्शन और डाटा माइनिंग करते हुए संदिग्ध लेनदेन और रहस्यमय घोटाले भी सार्वजनिक करना बेहद आसान हो गया है।

राजस्थान टुडे

आपकी पत्रिका, आपकी बात

मासिक समाचार पत्रिका के लिए सदस्यता प्रपत्र

नमस्कार,

हम आपको हमारी मासिक समाचार पत्रिका के साथ जोड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। हमारी पत्रिका में आपको देश और दुनिया की नवीनतम खबरें, विशेषज्ञों के लेख और विश्लेषण, और विशेष सामग्री मिलेगी।

सदस्यता विवरण

- सदस्यता शुल्कः 1000 पोस्टल चार्ज सहित प्रति वर्ष (12 अंक)
- सदस्यता अवधिः 1 वर्ष (12 अंक)
- भुगतान विकल्पः ऑनलाइन UPI भुगतान

सदस्यता प्रपत्र

नाम : _____

पता : _____

शहर : _____

राज्य : _____

पिन कोड : _____

मोबाइल नंबर : _____

ईमेल आईडी : _____

भुगतान विवरण

ऑनलाइन भुगतान

UPI QR code

8107800000@pz

हमारा पता

राजस्थान टुडे

बी-4, एम आर हाईट्स,
भास्कर सर्कल, रातानाडा,
जोधपुर- 342011

संपर्क जानकारी

वाट्सएप नंबर : +91 8107800000
ईमेल : rajasthantoday@gmail.com

धन्यवाद,
राजस्थान टुडे टीम

RNI No.- RAJHINDI/2020/11485

सदस्यता के लिए आवेदन करें : यदि आप हमारी मासिक समाचार पत्रिका के लिए सदस्यता लेना चाहते हैं, तो कृपया इस प्रपत्र को भरें और हमारे WhatsApp नंबर पर भेजें। हम आपको जल्द ही अपनी पत्रिका के साथ जोड़ देंगे।

इंग्लैंड पर ऐतिहासिक जीत के बाद अब ऑस्ट्रेलिया की चुनौती– भारतीय महिला क्रिकेट का आत्मविश्वास ऊंचा

हरमन-स्मृति की छत्रछाया में युवा शक्ति ने दिखाया दमखम

इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 से जीती गई वनडे सीरीज़ ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। निर्णायक मुकाबले में हरमनप्रीत कौर के शतक और क्रांति गौड़ की घातक गेंदबाजी इस जीत की पहचान बनी। इस सीरीज़ ने यह साबित किया कि टीम इंडिया अब केवल प्रतिभा पर नहीं, बल्कि मानसिक मजबूती और सामूहिक प्रदर्शन पर भी खड़ी है। अब पूरी दुनिया की नजरें टीम के अगले बड़े इम्तिहान— ऑस्ट्रेलिया के आगामी दौरे और 2025 विश्व कप पर होंगी, जहां टीम को अपनी स्थिरता और क्षमता को साबित करना होगा।

अजय अस्थाना ✍
वरिष्ठ पत्रकार

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जुलाई 2025 में इंग्लैंड को उसकी ही सरजमीं पर 2-1 से हराकर इतिहास रचा। पहले मैच में जीत हासिल करने के बाद टीम दूसरे वनडे में पिछड़ गई थी, लेकिन निर्णायक तीसरे मुकाबले में शानदार वापसी की। भारत ने 318/5 का मजबूत स्कोर खड़ा किया और इंग्लैंड को 13 रन से हराकर सीरीज़ अपने नाम की।

इस जीत में कप्तान हरमनप्रीत कौर का शतक (102 रन) और तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ की घातक गेंदबाजी (6/52) निर्णायक रही। क्रांति को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज़' चुना गया। इंग्लैंड को घरेलू सरजमीं पर हराना हमेशा चुनौतीपूर्ण माना जाता है, इसलिए यह जीत टीम के आत्मविश्वास को नई दिशा दे गई।

स्मृति मंधाना का भरोसेमंद प्रदर्शन

टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने सीरीज़ में भरोसेमंद शुरुआत दी। निर्णायक तीसरे वनडे में उनकी 77 रनों की तेजतर्रार पारी ने जीत की नींव रखी। स्मृति की शख्सियत उसके आंकड़े साबित करते हैं। मंधाना ने अपने खेल में निरन्तरता बनाए रखी है।

- वनडे करियर : 4,588 रन (औसत 46.3), 11 शतक और 31 अर्धशतक
- इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमेशा अच्छा प्रदर्शन

स्मृति दबाव वाली परिस्थितियों में टीम को स्थिरता देने के लिए जानी जाती हैं। उनकी निरंतरता टीम इंडिया की सबसे बड़ी ताकत है।

VS

टीम की प्रेरणास्रोत है हरमनप्रीत

हरमनप्रीत कौर का नेतृत्व इंग्लैंड सीरीज़ में टीम की वापसी का आधार बना। निर्णायक तीसरे वनडे में उन्होंने न सिर्फ शतक लगाया, बल्कि वनडे करियर में 4,000 रन पूरे करने वाली तीसरी भारतीय महिला बल्लेबाज भी बनीं। उनके खेल आंकड़े भी किसी से कमतर नहीं हैं।

- वनडे करियरः 4,049 रन (औसत 37.5), 7 शतक, 19 अर्धशतक

उनका शांत स्वभाव और रणनीतिक सोच टीम को सही दिशा देता है। युवा खिलाड़ियों के लिए हरमनप्रीत का नेतृत्व प्रेरणा स्रोत है।

युवा खिलाड़ियों की चमक व दमखम

इंग्लैंड सीरीज़ ने यह साबित कर दिया कि टीम अब केवल वरिष्ठ खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं है। उनके युवा खिलाड़ियों ने अब अपनी जगह तय कर ली है।

■ **क्रांति गौड़**
निर्णायक मैच में 6 विकेट

■ **रिचा घोष**
फिनिशर के रूप में तेज रन बनाए

■ **श्रीयंका पाटिल**
बीच के ओवरों में लगातार विकेट

■ **शफाली वर्मा**
सीरीज़ में आक्रामक शुरुआत दी

इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन टीम की गहराई और भविष्य की ताकत दिखाता है।

अब नजरें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर

इंग्लैंड सीरीज़ की जीत से मिली ऊर्जा अब टीम को ऑस्ट्रेलिया के आगामी दौरे पर ले जाएगी, जो 2026 में खेला जाएगा। इसमें तीन टी-20, तीन वनडे और एक टेस्ट मैच शामिल होंगे।

- ऑस्ट्रेलियाई पिचें तेज और बाउंस वाली होती हैं, जो बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण होंगी।
- झूलन गोस्वामी के संन्यास के बाद तेज गेंदबाजी में क्रांति गौड़ और रेणुका सिंह को जिम्मेदारी उठानी होगी।

हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
(भारत VS ऑस्ट्रेलिया)

- **वनडे**: 40 मैच – **भारत ने 12 जीते**
- **टी20**: 31 मैच – **भारत ने 7 जीते**

इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीं पर हराना कठिन होगा।

भविष्य की तैयारी : 2025 विश्व कप

- इसी वर्ष होने वाला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप टीम इंडिया का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इंग्लैंड सीरीज़ ने टीम की क्षमता को साबित कर दिया है, लेकिन निरंतरता की परीक्षा अभी बाकी है।
- स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर का अनुभव, शफाली वर्मा और रिचा घोष की ऊर्जा तथा क्रांति गौड़ और श्रीयंका पाटिल की गेंदबाजी टीम को खिताब का दावेदार बना सकती है।

दबाव में बेहतर प्रदर्शन

भारतीय महिला क्रिकेट टीम अब मानसिक रूप से भी मजबूत हो चुकी है। इंग्लैंड में जीत ने यह साबित किया कि यह टीम दबाव की परिस्थितियों में भी बेहतर खेल सकती है। ऑस्ट्रेलिया का दौरा इस मजबूती की अगली परीक्षा होगा।

इंग्लैंड सीरीज़ की जीत भारतीय महिला क्रिकेट के लिए नई शुरुआत है। अब ऑस्ट्रेलिया दौरा और 2025 विश्व कप वह अवसर हैं, जहां यह टीम इतिहास रच सकती है। स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर के नेतृत्व में टीम इंडिया के पास युवा ऊर्जा और अनुभव का ऐसा संयोजन है, जो आने वाले वर्षों में स्वर्ण युग की नींव रख सकता है।

सकारात्मक दृष्टिकोण और सही जीवन प्रबंधन से ही मिल सकता है सच्चा सुख

सुखी जीवन का सूत्रः कम तनाव, अधिक संतुलन

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में तनाव एक स्वाभाविक साथी बन चुका है। लेकिन इसे अपनी सोच और जीवन पर हावी होने देना सबसे बड़ी भूल है। तनाव को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है कि हम अपने जीवन में स्पष्ट प्राथमिकताएं तय करें। 40-30-20-10 का सिद्धांत हमें सिखाता है कि किन कार्यों और संबंधों में ऊर्जा लगानी है और किनसे दूरी बनानी है। गीता की शिक्षाएं हमें संयम, निष्काम कर्म और इच्छाओं पर नियंत्रण का महत्व बताती हैं। पॉजिटिविटी, आत्मबल, हंसी, स्वस्थ रिश्ते और वर्क-लाइफ बैलेंस अपनाने से हम तनाव को न सिर्फ कम कर सकते हैं, बल्कि सुखमय जीवन जी सकते हैं।

डॉ. गौरव बिस्सा,
मैनेजमेंट ट्रेनर,
मोटिवेशनल स्पीकर

तनाव और जिंदगी लगभग समानार्थक शब्द बन गए हैं। जीवन में यदि सकारात्मक तनाव न हो तो हम कोई भी कार्य करने की प्रेरणा ही नहीं पाएंगे। सकारात्मक तनाव को यूस्ट्रेस कहा जाता है, जो हमें लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। दौड़ के अंतिम क्षणों में पूरी ताकत लगाना, कठिनाइयों से जूझकर आगे बढ़ना, चुनौतियों को अपनाना, ये यूस्ट्रेस के उदाहरण हैं। लेकिन हमें डिस्ट्रेस यानी नकारात्मक तनाव से बचना चाहिए। यह कार्य का अत्यधिक बोझ, बॉस या सहकर्मियों से कटु संबंध, पारिवारिक क्लेश आदि के रूप में सामने आता है। हाल ही में बिड़ला एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा किए गए मेंटल हेल्थ एंड वेलनेस क्वोशेंट एट वर्कप्लेस सर्वे से यह साफ हुआ कि डिस्ट्रेस तेजी से बढ़ रहा है।

- **73%** कॉर्पोरेट जगत के कर्मचारी मानते हैं कि नकारात्मक तनाव उनकी सेहत व कार्यक्षमता को प्रभावित कर रहा है।
- **48%** कर्मचारी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंताजनक स्थिति में हैं।
- **82%** कर्मचारियों का कहना है कि मानसिक स्वास्थ्य सुधार के लिए छुट्टी और आराम आवश्यक हैं।
- **51%** कर्मचारियों में कार्यस्थल पर प्रेरणा की कमी देखी जा रही है।

तनाव को खुद पर हावी न होने देने के लिए हमें जीवन में एक सार्वभौमिक सिद्धांत अपनाना होगा–

40-30-20-10 का सिद्धांत

यह सिद्धांत तनाव को कम करने का एक सरल और प्रभावी उपाय है।

- **40%** कार्य और लोग- आपके नियंत्रण में होते हैं। इन कार्यों में आप निपुण होते हैं और सफलता लगभग सुनिश्चित होती है। आपके मित्र मंडल में भी लगभग 40 फीसदी लोग ऐसे होते हैं जो वास्तव में आपके अपने होते हैं और आपको बिना शर्त सहयोग देते हैं।
- **30%** कार्य और लोग- इन पर सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मित्रों या रिश्तेदारों का यह वर्ग "हैंडल विद केयर" वाला है। इनसे अत्यधिक तनाव नहीं होता, बस धैर्य की आवश्यकता होती है।
- **20%** कार्य और लोग- इनमें आप चाहे जितना प्रयास कर लें, अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। इस 20 फीसदी पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करें, क्योंकि ये आपके नियंत्रण से बाहर हैं।
- **10%** कार्य- ये आपके दायरे से पूरी तरह बाहर हैं। जैसे एक अध्यापक चाहकर भी पनडुब्बी को रिपेयर नहीं कर सकता।

अब सोचिए, जब आपका नियंत्रण केवल 40 फीसदी कार्यों और लोगों पर है, तो शेष पर तनाव लेने का क्या लाभ? व्यर्थ का तनाव कहीं एल्विस प्रेस्ली जैसी स्थिति न पैदा कर दे।

एल्विस की कथा

रॉक एंड रोल के सितारे एल्विस प्रेस्ली के 500 मिलियन रिकॉर्ड बिक चुके थे। उसके नाम से 70 से अधिक प्रोडक्ट्स बाजार में मौजूद थे। अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा सम्पत्ति का मालिक होने के बावजूद एल्विस ने 33 वर्ष की आयु में तनाव और अकेलेपन के चलते नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या कर ली। यही है तनाव का सबसे खतरनाक रूप— जब व्यक्ति जीवन के उन 70 फीसदी कार्यों और संबंधों को छोड़कर उन 30 फीसदी में उलझ जाता है जो उसके नियंत्रण से बाहर हैं।

पॉजिटिविटी की ताकत

- तनाव से लड़ने का सबसे पहला कदम है खुद को पॉजिटिव बनाना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टी.एन. चान ने 70,000 महिलाओं पर शोध कर बताया कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाली महिलाएं गंभीर बीमारियों से कम ग्रसित होती हैं और अधिक स्वस्थ व युवा दिखती हैं। इस रिसर्च में यह भी पाया गया कि पॉजिटिविटी के समय शरीर में निकलने वाले सेरोटोनिन और एंडोर्फिन हार्मोन त्वचा को निखारते हैं और व्यक्ति आकर्षक नजर आता है।
- अमेरिकी सोशल साइंटिस्ट जेम्स फौलर की स्टडी कहती है कि यदि आपका साथी खुश और पॉजिटिव है तो आपकी उदासी 25 फीसदी तक कम हो जाती है। भारत में लिंक्डइन की रिपोर्ट के अनुसार, 55 फीसदी कर्मचारी नकारात्मकता से परेशान हैं। यही कारण है कि आज मल्टीनेशनल कम्पनियां कर्मचारियों के लिए म्यूजिकल थेरेपी, हैप्पीनेस गेम्स और माइंडफुल एक्सरसाइज जैसे कार्यक्रम चला रही हैं।

तनाव कम करने के उपाय

तनाव को पूरी तरह खत्म करना असंभव है, लेकिन इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- अस्पताल जाकर गम्भीर रोगियों को देखकर समझें कि आपका तनाव उनसे बड़ा नहीं है।
- इंट्रोस्पेक्शन के लिए अपनी उपलब्धियां लिखें, पुरानी यादें ताज़ा करें, तस्वीरें देखें। यह आत्मबल बढ़ाता है।
- मनोरोगियों की दशा को समझें, जैसे उनके उल-जुलूल शब्दों पर आप ध्यान नहीं देते, वैसे ही आलोचकों की बातों से विचलित न हों।
- उम्मीदें कम करें, हर किसी से अपेक्षा न रखें। ईसा मसीह को भी सैकड़ों रोगियों में से केवल एक ने धन्यवाद दिया था।
- रबर बैंड तकनीक अपनाएं। नकारात्मक विचार आते ही कलाई में बंधे रबर बैंड को खींचें और छोड़ें। हल्का दर्द दिमाग को सतर्क करेगा।
- हंसना भी जरूरी है। बच्चे दिन में 500 बार हंसते हैं, जबकि वयस्क सिर्फ 5-7 बार। लाफ्टर थेरेपी तनाव घटाने में बेहद कारगर है।
- 60 फीसदी समय दूसरों को सुनने में लगाएं और केवल 40 फीसदी बोलें।
- नकारात्मक बातें न कहें और न सुनें। कुछ दिनों में लोग समझ जाएंगे कि आप नेगेटिविटी पसंद नहीं करते।

गीता और तनाव प्रबंधन

श्रीमद्भगवद्गीता स्पष्ट कहती है कि अत्यधिक इच्छाएं ही तनाव का मूल कारण हैं।

- अनियंत्रित इच्छाएं विवेक को ढक देती हैं और व्यक्ति को परेशानियों की ओर ले जाती हैं।
- अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना ही स्वधर्म है। इसे निभाने वाला व्यक्ति तनाव से दूर रहता है।

गीता का यही संदेश है कि निष्काम भाव से कर्म करें, परिणाम की चिंता न करें। यही सुखी जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है।

वर्क-लाइफ बैलेंस

- आजकल कार्यस्थल पर लम्बे समय तक काम करने की चर्चाएं तेज हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि काम और आराम में संतुलन रहना चाहिए। जर्मनी में फिएराबैंड नामक परम्परा के तहत कानून है कि 24 घंटे में से 11 घंटे केवल आराम के लिए तय होंगे। चर्च की घंटी बजते ही लोग काम छोड़कर घर लौट आते थे।
- हम भी इस सिद्धांत को अपनाएं। न तो काम से भागें और न ही इतना बोझ लें कि "बैल मार खेती" की तरह अपनी ही ऊर्जा खत्म कर लें।

जीवन प्रबंधन का मूल

आनंदित होकर कार्य करना, परिवार और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखना ही जीवन प्रबंधन का सबसे बड़ा रहस्य है। याद रखिए—खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में है।

गज़ल का स्वभावः भारतीयता और हिंदी गज़ल

ईरान में लुप्त हो रही गज़ल को हिन्दुस्तान में मिली सांसें

भारतीयता का अर्थ- वसुधैव कुटुंबकम की भावना, भारतीयता का अर्थ- जीवंतता, भारतीयता का अर्थ- समसामयिक संस्कृति है। गज़ल भले ही अरबी- फारसी से हिंदी में आई, पर हिंदी में आने के बाद वह भारतीय संस्कृति व भारतीय चेतना के साथ एक रूप हो गई। हिंदी गज़ल को राज्याश्रय प्राप्त नहीं हुआ। उसने सड़क वासी राम की भाषा को अपनाया। आम आदमी की बोली में बात करने लगी। वह फुटपाथ पर पली- बढ़ी और संस्कारित हुई। वह जन साधारण की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। यही भाषा हिंदी गज़ल की ताकत बनी।

दिनेश सिंदल
कवि, लेखक व गीतकार

ग़ज़ल प्रेम की कविता है। लगभग आठ सौ वर्ष पहले अरबी- फारसी से चलकर भारत में आई यह विधा अब पूरी तरह भारतीय बनाकर हिन्दी में पनप रही है। गज़ल की संरचना ऐसी है कि इसमें समसामयिकता होते हुए भी शाश्वतता का भाव पैदा कर देती है। यह भारतीय काव्य परम्परा के अनुरूप है। यही कारण है कि आज गज़ल ईरान में (जहां से चली थी) धीरे-धीरे लुप्त हो गई और हिन्दुस्तान में तरक्की करती जा रही है। फल- फूल रही है।

भारतीयता का अर्थ- वसुधैव कुटुंबकम की भावना, भारतीयता का अर्थ- जीवंतता, भारतीयता का अर्थ- समसामयिक संस्कृति है। गज़ल भले ही अरबी- फारसी से हिंदी में आई, पर हिंदी में आने के बाद वह भारतीय संस्कृति व भारतीय चेतना के साथ एक रूप हो गई।

हिंदी गज़ल को राज्याश्रय प्राप्त नहीं हुआ। उसने सड़क वासी राम की भाषा को अपनाया। आम आदमी की बोली में बात करने लगी। वह फुटपाथ पर पली- बढ़ी और संस्कारित हुई। वह जन साधारण की अभिव्यक्ति का माध्यम बनी। यही भाषा हिंदी गज़ल की ताकत बनी।

गजल का अर्थ ' स्त्रियों से बातचीत' है। कहीं- कहीं पर गज़ल का अर्थ 'स्त्रियों की बातचीत' भी कहा गया है। स्त्री का स्वर प्रेम का स्वर है। दया, करुणा, प्रार्थना व समर्पण उसका स्वभाव है जो गज़ल व भारतीयता की सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से मेल खाता है।

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार- 'गज़ल प्राचीन गीत- काव्य की ऐसी विधा है, जिसकी प्रकृति सामान्यतः प्रेम परख होती है।' प्रेम का स्वभाव समर्पण का है, झुकने का है, विनम्रता का है, प्रार्थना का है। हमारे सभी प्राचीन ग्रंथ प्रार्थना से ही आरम्भ होते हैं। अतः गज़ल भारतीय जनमानस के बहुत करीब है।

गजाला से बना गज़ल

गज़ल शब्द गजाला से बना है। जिसका अर्थ है हिरण का बच्चा। उसके तीर लगे और उस तीर को निकलते वक्त पीड़ा से जो कराह निकलती है वह गज़ल है। लेकिन हिंदी में आकर उस पीड़ा ने विस्तार लिया। नीरज कहते हैं-

मुझे मिला है वहां अपना ही बदन जख्मी
कहीं जो तीर से घायल कोई हिरण देखा

गज़ल प्रेम की कविता है, लेकिन अब वो मात्र दैहिक प्रेम नहीं रहा। एक वह जमाना था कि लोग औरत के गोश्त पर राज्य और विवेक सब निसार कर देते थे। राजाओं और नवाबों को अफीम और गज़ल का नशा था। तब गज़ल में मखमल पर चलने से पैर छिल जाने की बातें हुआ करती थी। पुरानी दिल्ली में ऐसा कहा जाता था कि जब एक पड़ोसन जवान होती थी तो मोहल्ले में दस गजलें कही जाती थी। किंतु हिंदी ग़ज़ल में उस प्रेम ने विस्तार लिया। हिंदी गज़ल में निहित प्रेम मात्र प्रेमी- प्रेमिका या स्त्री- पुरुष का प्रेम नहीं रहा। अब वह प्रेम कहीं राष्ट्र के प्रति है, कहीं मेहनतकश श्रमिक के प्रति, कहीं पत्थर तोड़ते मजदूर के प्रति, कहीं धरती का सीना चीर कर अन्न उपजाते किसान के प्रति, तो कहीं मनुष्य मात्र के प्रति। हिंदी गज़ल में प्रेम के विविध रूप सामने आए। वह ममता, स्नेह, दया, करुणा, अनुराग, मातृत्व, अहिंसा, देश प्रेम, ईश्वर भक्ति, विश्व बंधुत्व, सुख- शांति, के सभी संदर्भों को समेटे हुए हैं।

भारतीयता और गज़ल में अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य रूप से एक तत्व समान रूप से समाहित है वह है उसकी सामासिकता। सबको समेटने की ताकत। एकमेव हो जाने की कामना। और अपने इस लक्ष्य में दोनों ही सदैव कामयाब रहे हैं। दोनों ही आज के समय की विसंगति, विद्रूपता से परिचित हैं। दोनों ही गिरते हुए नैतिक मूल्य, भ्रष्टाचार और अत्याचार के प्रति आक्रोशित है। दोनों ही मानवता के पक्ष में खड़े हैं एवं विश्व शांति, विश्व कल्याण की कामना करते हैं। दोनों ही भाषाई नफरत को मिटाना चाहते है।

हिंदी गज़ल की बढ़ती हुई लोकप्रियता एवं दिन-प्रतिदिन समृद्ध हो रही इसकी परम्परा का एक उल्लेखनीय कारण यह भी है कि समसामयिक हिंदी कवि इसे मात्र एक उधार ली गई विधा के रूप में नहीं मानते, वरन अभिव्यक्ति के एक सक्षम, सूक्ष्म व समयानुकूल माध्यम के रूप में इसका उपयोग कर रहे हैं। वे गज़ल को हिंदी कविता के अनुरूप नया मुहावरा, नया संस्कार एवं नया चरित्र देने में संलग्न हैं।

गज़ल के विकास में दोहा विधा का योगदान

डॉ राही मासूम रजा का मानना है कि हमारी गज़ल फारसी गज़ल का विस्तार नहीं है, अपितु भारतीय साहित्यिक परम्पराओं का एक क्रमबद्ध विकसित रूप है और उसके विकास में दोहा और सोरठा विधाओं का योगदान स्पष्ट है। वह प्रवृत्ति जिसमें शेर को दो भागों में बांटा जाता है। एक में दलील प्रस्तुत की जाती है व दूसरे में उसको सिद्ध किया जाता है। यह प्रवृत्ति ब्रजभाषा के दोहों में अक्सर पाई जाती है। इसे भारतीय शैली की मुख्य विशेषता माना गया है।

गज़ल के शेर में दो पंक्तियों में एक पूरी बात कह जाना और हर शेर का कथ्य की दृष्टि से अलग होना हिन्दी कविता में दोहा परम्परा से प्राप्त हुआ है। दोहे में 'गागर में सागर' भरने की बात पहले से कही जाती रही है।

हिन्दी ग़ज़ल ने अपनाए हिन्दी के पौराणिक मिथक

- हिन्दी ग़ज़ल ने भारतीय कविता की लम्बी परम्परा से अपने को जोड़ा। उससे आत्मसात किया। उसके बिम्ब, प्रतीक, उपमान, उपमेय व हिन्दी के पौराणिक मिथकों को अपनाया और अपने को समृद्ध किया।
- हिन्दी ग़ज़ल ने न केवल विषयगत संकीर्णता को तोड़ा, नए-नए विषयों के साथ आत्मसात किया, बल्कि हिन्दी छन्दों के सम्पर्क में आने से कई नई-नई बहारें सामने आई। जब कोई रचनाकार दूसरी विद्या में हाथ आजमाता है, तब वह अपनी विद्या के तत्व भी साथ ले जाता है। नवगीतकार जब गज़ल की तरफ आए तो नवगीत की शब्दावली भी गज़ल को मिली। नवगीत के बिम्ब, प्रतीक, उपमान-उपमेय, नवगीत का भाषाई मुहावरा गज़ल को मिला और एक नई गज़ल का नया जन्म हुआ। यही हिंदी गज़ल है।

लो गज़ल की इक शमा चुपचाप जलने आ गई
बर्फ तेरी याद की मन में पिघलने आ गई
ये हवा दिन भर तो आवारा धुंए के साथ थी
शाम को ये बाग में कपड़े बदलने आ गई
अब तो चेहरों पर तुम्हारे झुर्रियां कुछ तो दिखे
अब तुम्हारे आईनो की उम्र ढलने आ गई

'सैय्यारा' की ऐतिहासिक सफलता ने बॉलीवुड में उम्र, रसायन और प्रामाणिकता पर नई बहस छेड़ दी है—
क्या यह नई पीढ़ी की बदलती उम्मीदों का संकेत है?

चौंकाती है 'सैय्यारा' फिल्म की सफलता

मोहित सूरी की नई फिल्म 'सैय्यारा' न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक सांस्कृतिक बहस का कारण बन चुकी है। नवोदित जोड़ी अहान पांडे और अनीत पड्डा की यह रोमांटिक प्रेम कहानी जेन-जी दर्शकों के दिलों को छू रही है, जो अब उम्रदराज हीरोज़ और युवा हीरोइनों की अविश्वसनीय जोड़ियों से ऊब चुके हैं। सैय्यारा को उसकी स्वाभाविक केमिस्ट्री, सोलफुल म्यूज़िक, भावनात्मक गहराई और उम्र के अनुरूप रोमांस के लिए सराहा जा रहा है। सिनेमाघरों में दर्शकों की भावनात्मक प्रतिक्रियाएं—आंसू, तालियां, और उन्माद—इस बात का संकेत हैं कि यह फिल्म अब केवल एक 'मनोरंजन' नहीं, बल्कि एक 'अहसास' बन चुकी है। जब बड़े सितारों की वीएफएक्स से भरी फिल्में लड़खड़ा रही हैं, तब 'सैय्यारा' जैसी साधारण-सी लगती फिल्म दर्शकों की सच्ची जरूरतों को पूरा कर रही है—सादगी, प्रामाणिकता और भावनाओं की असली ताकत।

सुधांशु टाक
लेखक व समीक्षक

आज के दौर में जब तकनीक की बात होती है तो एक शब्द "जेन-जी" लोगों की जुबान के माध्यम से बार- बार सुनाई देता है। तो सबसे पहले ये जान लें कि यह "जेन जी" है क्या..? असल में जेन-जी अंग्रेजी के Gen Z का हिंदी रूपांतरण है। कुछ लोग इसे जेन-जेड भी कहते हैं। आज के दौर में जब तकनीक की बात होती है तो सबसे पहले जेन-जी लोगों का नाम आता है। ये वे लोग हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ है और 2024 में इनकी उम्र 12 से 27 साल के बीच में है। जेन-जी पीढ़ी कई मायनों में काबिल है और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं।

तो साहब इस जेन-जी पीढ़ी के नौजवानों में 18 जुलाई 2025 को रिलीज हुई हिन्दी फिल्म "सैय्यारा" को लेकर एक हिस्टीरिया- एक पागलपन पैदा हो गया है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म 'सैयारा' बॉक्स ऑफिस पर गदर काट रही हैं। इतनी बड़ी सफलता और टिकट खिड़की पर ऐसा ब्लॉक-बस्टर कलेक्शन लम्बे समय बाद देखने को मिल रहा है।

नवोदित अदाकारों अहान पांडे और अनीत पड्डा की इस पहली बॉलीवुड फिल्म 'सैय्यारा' ने रिलीज के पहले हफ्ते में दुनियाभर में बम्पर कमाई की है। इस एक हफ्ते में 'सैयारा' ने कमाई के मामले में कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। पीछे छूटने वालों में कई बड़े स्टार की बिग बजट फिल्में भी शामिल हैं।

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'सैयारा' ने सातवें दिन 13.71 करोड़ रुपए कमाए, जिसके बाद से भारत में इसका कलेक्शन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुनियाभर में फिल्म ने 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा छू लिया, जिसमें विदेशों से 37 करोड़ रुपए की कमाई शामिल है। फिल्म को मिल रहे जबरदस्त प्यार और दर्शकों की भीड़ ने इसे साल 2025 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बना दिया है। आप सभी की जानकारी के लिए 'सैयारा' का कुल बजट करीब 40 करोड़ रुपए है। यानी फिल्म पहले ही ब्लॉकबस्टर हो चुकी है।

मोहित सूरी की इस फिल्म को यश राज फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म का संगीत और 'आशिकी 2' जैसा रोमांटिक अहसास दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। दिल्ली, मुंबई, पुणे और जयपुर जैसे शहरों में फिल्म को सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग मिल रही है। 'सैयारा' की इस ऐतिहासिक कामयाबी ने हीरो अहान और हीरोइन अनीत को रातोंरात स्टार बना दिया है, और यह फिल्म बॉलीवुड में नए टैलेंट की ताकत दिखा रही है। फिल्म को सकारात्मक समीक्षाएं मिल रही हैं, जिसका परिणाम भी सामने दिख रहा है। भारत में 318 करोड़ और विदेश में 86 करोड़ ये मूवी कमा चुकी है।

'सैयारा' उस कहानी पर बनी फिल्म है, जो आप सैकड़ों बार देख-सुन चुके हैं। एक अक्खड़ मिजाज लड़का है कृष कपूर। उसका बचपन बुरा गुज़रा। अब वो म्यूज़िशियन बनना चाहता है। उसके लिए स्ट्रगल कर रहा है। तभी उसकी मुलाकात वाणी नाम की एक लड़की से होती है। वाणी जर्नलिस्ट है, मगर गाने भी लिखती है। कृष और वाणी मिलते हैं। म्यूज़िक बनाते हैं। प्रेम में पड़ते हैं और किन्हीं वजहों से उन्हें अलग होना पड़ता है। उन दोनों के साथ आने में क्या अड़चन है, यही फिल्म का क्रक्स है। बस यहीं से युवा पीढ़ी इस फिल्म से जुड़ रही है।

आज की जेनरेशन को इस फिल्म से जो चाहिए, वो सबकुछ इसमें मिलता है। एक फ्रेश लीड पेयर। बढ़िया केमिस्ट्री। मजबूत इमोशनल ड्रामा। हिट म्यूज़िक और ठीक-ठाक परफॉरमेंसेज़। हालांकि फिल्म की एंडिंग थोड़ी अटपटी लगती है। 'अब्रप्ट' भी कह सकते हैं। मगर उससे पूरी फिल्म पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। शायद आज की जेन जी ऑडियंस को यही बात उन्मादी बना रही है।

उन्मादी इसलिए लिखा, क्योंकि सिनेमा थियेटर्स से ऐसे ढेरों वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें लोग चीख रहे हैं। रो रहे हैं। मोहित सूरी की नई रोमांटिक फिल्म 'सैय्यारा' 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और दर्शकों के दिलों पर गहरा असर छोड़ रही है। अहान पांडे और अनीत पड्डा की ताजा जोड़ी ने स्क्रीन पर ऐसी केमिस्ट्री दिखाई कि थिएटर अब केवल मनोरंजन का केंद्र नहीं, बल्कि भावनाओं का समंदर बन गया है। फिल्म की कहानी प्यार, टूटन और आत्म-खोज के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें अहान ने एक महत्वाकांक्षी सिंगर कृष कपूर और अनीत ने एक संवेदनशील गीतकार वाणी बत्रा का किरदार निभाया है।

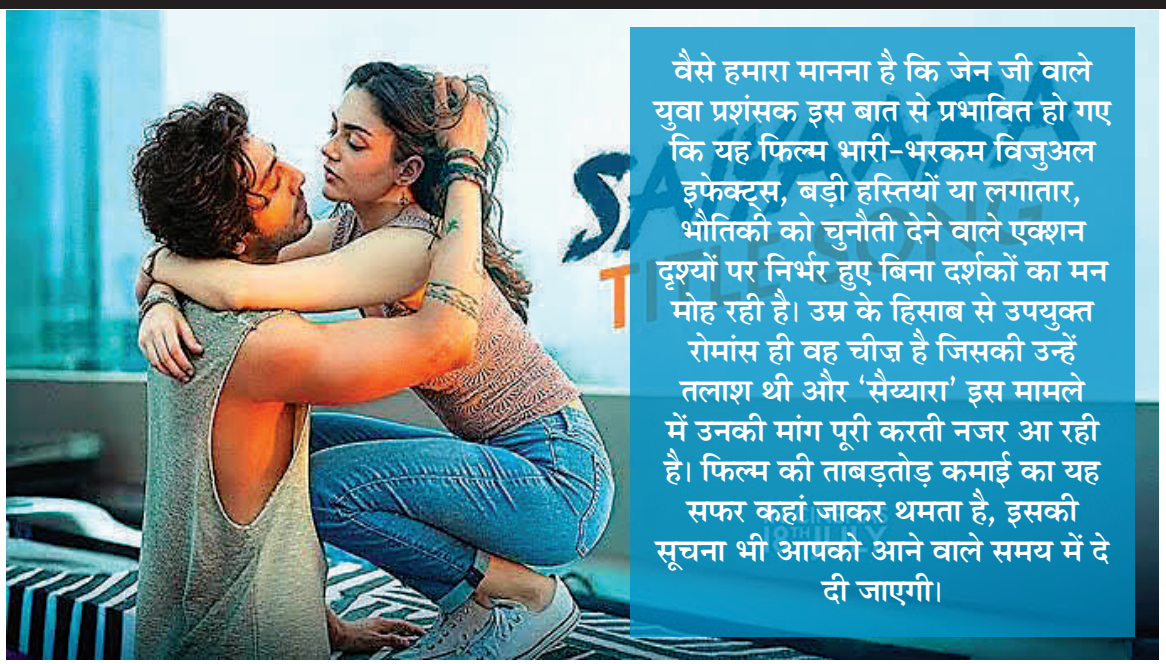

वैसे हमारा मानना है कि जेन जी वाले युवा प्रशंसक इस बात से प्रभावित हो गए कि यह फिल्म भारी-भरकम विजुअल इफेक्ट्स, बड़ी हस्तियों या लगातार, भौतिकी को चुनौती देने वाले एक्शन दृश्यों पर निर्भर हुए बिना दर्शकों का मन मोह रही है। उम्र के हिसाब से उपयुक्त रोमांस ही वह चीज़ है जिसकी उन्हें तलाश थी और 'सैय्यारा' इस मामले में उनकी मांग पूरी करती नजर आ रही है। फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई का यह सफर कहां जाकर थमता है, इसकी सूचना भी आपको आने वाले समय में दे दी जाएगी।

एक अहसास बन चुकी है 'सैय्यारा'

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि 'सैय्यारा' सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक अहसास बन चुकी है। कोई चुपचाप रोता दिख रहा है, तो कोई जोर-जोर से फूट-फूट कर रो रहा है। कुछ कपल्स सीट पर एक-दूसरे का हाथ थामे भावुक हो रहे हैं, वहीं एक वीडियो में एक लड़का आईवी ड्रिप लगाकर फिल्म देखने पहुंच गया। कुछ लोग इसे फिल्म की पीआर टीम का पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। लेकिन लगातार एक्शन और थ्रिलर से भरी फिल्मों के बीच 'सैय्यारा' ने अपने अनोखेपन से एकदम से ऑडियंस की भावनाओं को छू लिया है। लंबे समय से लोग एक सच्ची रोमांटिक कहानी की तलाश में थे और 'सैय्यारा' लोगों की उन उम्मीदों पर खरी उतर रही है।

फिल्म का क्रेज सभी शहरों में

'सैय्यारा' का जबरदस्त क्रेज लगभग सभी शहरों में देखने को मिल रहा है। कई शहरों के सिनेमाघरों विशेषकर मल्टीप्लेक्सेस में फिल्म के शोज़ लगातार हाउसफुल जा रहे हैं। फिल्म देखकर बाहर निकलते दर्शकों से जब फिल्म समीक्षक सवाल पूछ रहे हैं तो ज़्यादातर लोगों ने फिल्म को दिल छू लेने वाली बताया। एक्टर्स की दमदार परफॉर्मेंस, भावनाओं से भरपूर कहानी और सोलफुल म्यूजिक ने दर्शकों को पूरी तरह बांध लिया। लोगों का कहना था कि फिल्म न केवल रोमांटिक है, बल्कि मस्ट वॉच है।

इधर सोशल मीडिया पर एक हैंडल से एक्स यूजर ने अपने बॉलीवुड प्रेमियों से पूछा, 'सैय्यारा' को इतनी जबरदस्त प्रतिक्रिया क्यों मिल रही है?" तो जवाब तुरंत आने लगे।

एक यूजर ने जवाब में लिखा, "शायद जेन जेड अत्यधिक मांसल, वीएफएक्स से भरपूर 50+ साल के बुद्ध को अपनी पोतियों जितनी छोटी अभिनेत्रियों के साथ रोमांस करते देख कर थक गया है।" प्रशंसकों का कहना है कि पुराने अभिनेताओं को अपनी आधी उम्र की अभिनेत्रियों के साथ रोमांस करते देखने से मिली यह राहत की बात है।

"यार, इस पीढ़ी को कुछ युवा रोमांस वाली फ़िल्में तो मिलनी चाहिए (भले ही वो औसत दर्जे की ही क्यों न हो), जहां पुरुष अभिनेता 40 साल का न हो और अभिनेत्री 20 की। जहां पुरुष नायक ऐसा न लगे, जैसे उसने सालों से नहाया ही न हो और जिसमें दयनीय, घटिया और "हीरो" जैसे संवाद हों।"

ग्रहों की चाल

ज्योतिषी : विपुल डोभाल
ईमेल : vipravaani@gmail.com
मोबाइल : 9928424374

मेष

इस राशि के जातकों के लिए यह महीना भाई बहनों की तरफ से सुखद समाचार देने वाला है। पुराने मनमुटाव दूर होंगे और सौहार्द का वातावरण बनेगा। व्यर्थ के व्यय हो पर अंकुश लगाने में सफल होंगे। आर्थिक जोखिम से बचें और स्वयं को व्यर्थ के विवादों से दूर रखें। कृषि भूमि की खरीद का लाभ मिल सकता है। किसान और फल विक्रेता काफी लाभ में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं।
भगवान गणेश की स्तुति इस महीने आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगी।

वृषभ

इस राशि के जातकों को कुटुंब सुख प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से संबंधित विवाद आपसी समझौते से सुलझा सकते हैं, प्रयास करें। नव विवाहित दंपतियों में प्रेम बढ़ता दिखाई दे रहा है। नेत्र दोष संभव है, साथ ही सिर दर्द की शिकायत रह सकती है। व्यापारियों को लाभ मिलने की संभावना है। छाती, फेफड़े और हृदय से संबंधित रोगों की जांच करवाते रहें। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अनुकूल है।
भगवान शिव की उपासना इस महीने आपको निश्चित रूप से लाभ देने वाली है।

मिथुन

इस राशि के लिए यह महीना आर्थिक लाभ देता दिखाई दे रहा है। किंतु आप नए वस्त्रों, फैशन, लग्जरी इत्यादि पर खर्च करते हुए दिख रहे हैं। प्रेम संबंधों के मामले में भी आपको लाभ होता दिख रहा है। रिस्क लेने की क्षमता इस महीने बहुत बढ़ी रहेगी और कोई बड़ा नुकसान भी दे सकती है। बहुत नपे तुले रिस्क के साथ आगे बढ़ें। भाग्य साथ देता दिख रहा है। कुल मिलाकर यह महीना प्रसन्नता देता दिख रहा है।
हनुमान जी की उपासना आपके लिए शुभ फलदाई होगी।

कर्क

इस राशि के व्यक्तियों के लिए यह समय अत्यधिक लाभदायक दिखाई दे रहा है। अपने बुद्धि विवेक से आप धनार्जन भी करते दिख रहे हैं और साथ ही साथ कई समस्याओं का निदान स्वयं करने में सक्षम रहेंगे। क्रोध और जिद से बचें। किसी धार्मिक कार्य में धन व्यय करना आपके लिए भविष्य में शुभ फलदाई रह सकता है। भाग्य बिल्कुल भी साथ देता नहीं दिखाई दे रहा है। आपका स्वयं के प्रयास और मेहनत निश्चित रूप से आपको शुभ फल देने वाली है।
हनुमान जी की स्तुति और महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपके लिए शुभ रहेगा।

सिंह

इस राशि के जातकों को इस महीने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा अपनी वाणी और क्रोध के कारण बने बनाए कार्य ध्वस्त हो जाएंगे। नेत्र दोष हो सकता है और पेट से संबंधित रोग भी परेशान कर सकते हैं। पुलिस या कानूनी पचड़ों से स्वयं को दूर रखें तो अच्छा रहेगा। आय से अधिक व्यय होंगे। व्यर्थ की मानसिक चिंताएं परेशान रख सकती हैं।
भगवान शिव की उपासना आपके लिए शुभ फलदाई रहेगी।

कन्या

इस राशि के जातकों के लिए यह महीना धन लाभ देता दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका साथ देता दिख रहा है। आप घूमने फिरने और अन्य प्रकार की लग्जरी पर खर्च करते दिख रहे हैं। नए वस्त्र आभूषणों की खरीदारी होगी। परफ्यूम इत्यादि अन्य कॉस्मेटिक पर धन खर्च करेंगे। कुल मिलाकर यह माह आपके लिए काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। शत्रु परास्त होते दिख रहे हैं।
कात्यायनी माता की स्तुति इस महीने आपके लिए शुभ फलदाई रहेगी।

तुला

इस राशि के जातकों को स्वास्थ्य कष्ट का सामना करना पड़ेगा। कार्य स्थल पर वाद-विवाद की स्थिति के कारण नौकरी खतरे में पड़ सकती है। किसी रसायन से एलर्जी संभव है। स्वास्थ्य पर व्यय होता दिखाई दे रहा है। संतान के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना होगा। कार्य स्थल पर जिम्मेदारियां बढ़ेगी और कार्यभार भी बढ़ेगा। अगर आप 40 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो कान से संबंधित समस्या आ सकती है।

वृश्चिक

इस राशि के जातकों के लिए कुछ हद तक सुख बाधित होते दिख रहे हैं। आपके कार्य तो बनेंगे, किंतु रुक-रुक कर आगे बढ़ेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आती दिखाई दे रही है। भाग्य आपका साथ देता दिख रहा है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें।
इस महीने शनिवार और मंगलवार को बालाजी की स्तुति आपके लिए शुभ रहेगी।

धनु

इस राशि के जातक दाम्पत्य जीवन की मधुरता का लाभ उठा पाएंगे। कई बिगड़े संबंध दुरुस्त होंगे। भूमि, भवन या वाहन की खरीद इस महीने पूरी तरह रोक दें, अन्यथा हानि हो सकती है। व्यवसाय और ऑफिस में वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। पित्त संबंधी रोग परेशान कर सकते हैं। किसी महिला के कारण अपमान या बदनामी की स्थिति बन सकती है।
शनि देव की उपासना इस महीने आपके लिए शुभ रहने वाली है।

मकर

इस राशि के जातकों के लिए यह समय लाभकारी होता दिख रहा है। आपको धन लाभ होगा और आपके मान सम्मान में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। बुद्धिबल से आप लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। संतान की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता बन सकती है। स्वयं के लिए भी कमर और निचले हिस्सों को चोट इत्यादि से बचाने की आवश्यकता है। पत्नी के साथ संबंध मधुर होंगे। पत्नी की तरफ से धन लाभ संभव।
भगवान श्रीगणेश की उपासना आपके लिए शुभ रहेगी।

कुंभ

इस राशि के जातकों को कुटुंब में वार्तालाप नियंत्रित रूप से करना होगा। व्यर्थ के विवाद से बचें। आकस्मिक धन हानि के योग हैं। कीमती वस्तुओं के खोने का भय रहेगा। फिर भी कुछ सुखद समाचारों की प्राप्ति हो रही है और आप यात्राएं करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बीच-बीच में दाम्पत्य जीवन में कुछ कड़वाहट आ सकती है, किंतु कुछ क्षणों में पुनः प्रेम उत्पन्न हो जाएगा।
इस महीने शनि के उपाय करना आपके लिए शुभ रहेगा।

मीन

इस राशि के जातकों का भाई-बहन से विवाद हो सकता है। संतान की ओर से अवश्य सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। कमर से नीचे के अंगों में तकलीफ आ सकती है। आप अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच इस बीच अवश्य करते रहें। महीने का अंत होते-होते भाग्य आपका साथ देता दिखाई दे रहा है।
सूर्य को जल अर्पित करना आपके लिए शुभ रहेगा।

Sir Pratap Singh Ji
Benevolent Ruler
Rajasthan

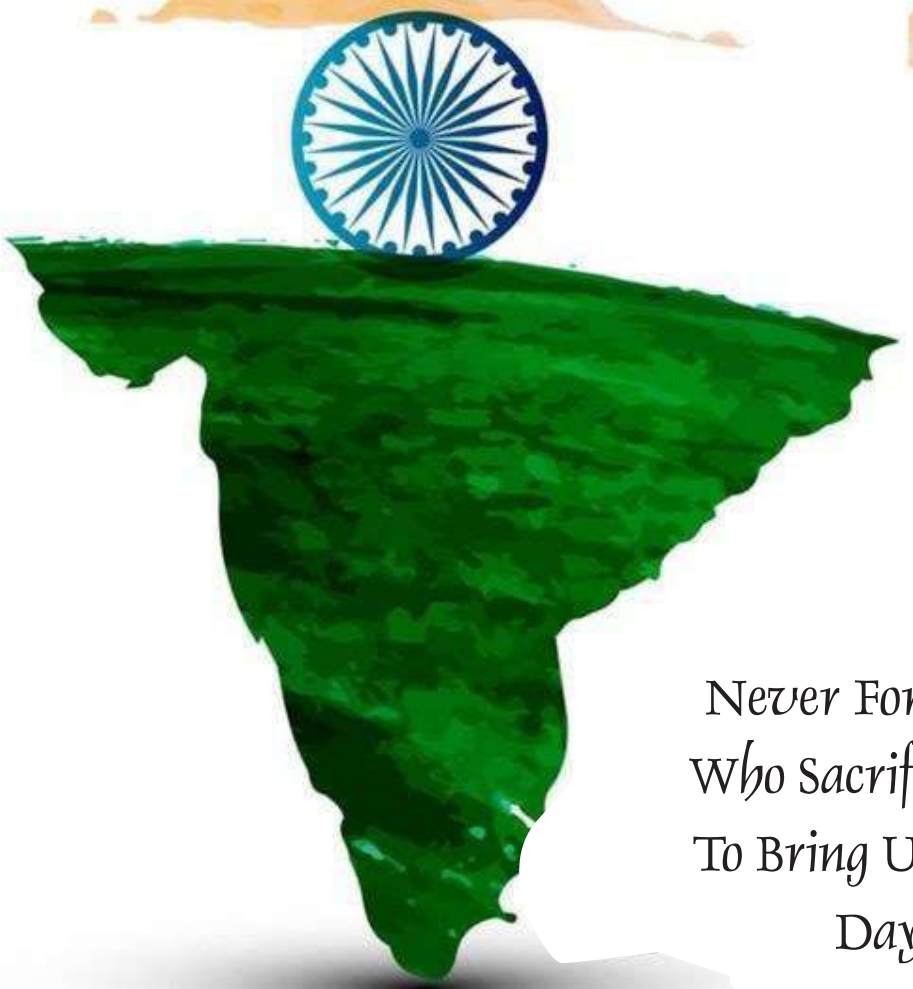

Munshi Shubhlal ji
Pioneer & Philanthropist

Hon'ble Justice
N. N. MATHUR
(Chief Patron)
Former Vice Chancellor
NLU Jodhpur

Girish Mathur
Founder of Sir Pratap Vidhi Mahavidyalay

Never Forget The Heroes
Who Sacrificed Their Lives
To Bring Up This Glorious
Day to India

Happy Independence Day

HISTORY OF SIR PRATAP SCHOOL VIS-A-VIS ITS JOURNEY TO

SIR PRATAP VIDHI MAHAVIDYALAYA

567th Glorious Years of Jodhpur

बैंक ऑफ़ बड़ौदा
Bank of Baroda

तेज सुविधाजनक किफ़ायती बड़ौदा कार ऋण

- नियत और अनियत ब्याज दरों का विकल्प
- सभी मॉडल्स पर 90% ऑन रोड़ फायनांस
- दैनिक घटते शेष आधार पर ब्याज की गणना
- समय-पूर्व भुगतान का सुविधाजनक विकल्प
- समय-पूर्व ऋण चुकता करने पर शून्य प्रभार
- गृह ऋण ग्राहकों और इलैक्ट्रिक वाहन ऋण के लिए ब्याज दर में 25 बीपीएस की छूट

#bobCarLoan

आवेदन के लिए स्कैन करें

साइबर अपराध शिकायतों की रिपोर्ट के लिए 1930 पर संपर्क करें/ www.cybercrime.gov.in पर विजिट करें।

कार लोन हेतु 846 700 1133 पर मिस कॉल करें*

#bobHomeLoan

Home = Happiness

Baroda Home Loan

- Maximum SAving with Baroda Max Saving Home Loan
- 0.05% Interest Rate Concession for Women Borrowers
- 0.10% Interest Rate Cocnession for Gen Z and Millennials (Aged under 40 Years)
- Easy Top-Up Facility Available
- Interest Calculated on a Daily Reducing Balance

*T&C Apply

Scan for Apply

Give a missed call*: Home Loan: 846 700 1111

www.bankofbaroda.in | Follow us on